विशेष डिजिटल अंक

सच को समर्पित समाचार पत्रिका

18 मई 2020, मूल्य ₹ 25

आउटलुक

www.outlookhindi.com

"कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस": नरेंद्र सिंह तोमर

संतुलन साधने का वक्त

- प्रो. अरुण कुमार
- प्रो. कौशिक बसु
- प्रो. बिश्वजीत धर
- सजी नारायण
- सीताराम येचुरी
- भूपेंद्र यादव

RNI NO. DELHIN/2009/26981

facebook.com/outlookhindi

twitter.com/outlookhindi

17

दोराहे पर सरकार

21 कैसे हो पटरी पर वापसी

23 नरेंद्र सिंह तोमर: किसान ही योद्धा

26 अरुण कुमार: असलियत समझें

28 कौशिक बसु: चूक पड़ेगी भारी

29 बिश्वजीत धर: पैकेज में देरी क्यों

31 भूपेंद्र यादव: बदलें पारंपरिक सोच

33 गौरव वल्लभ: लापरवाही की कीमत

34 सीताराम येचुरी: उपेक्षा से बढ़ा संकट

06 **संकट में राज्य:** केंद्र पर सवाल

09 **इंटरव्यू:** छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

10 **बिहार:** लॉकडाउन में नीतीश की मुश्किल

11 **झारखंड:** कोरोना से लड़ाई में संसाधनों की किल्लत

12 **उत्तर प्रदेश:** बदहाल आगरा मॉडल

14 **राजस्थान:** लॉकडाउन में ढील को तैयार

15 **मध्य प्रदेश:** शिवराज की मजबूरी

36 **निखिल डे:** गरीबों की सुनो

38 **उद्योग-धंधे:** संजीवनी की जरूरत

42 **सजी नारायण:** श्रमिकों का हित जरूरी

45 **फिल्म जगत:** संकट में मदद को बढ़े हाथ

कवर इलस्ट्रेशन: **साहिल**

आउटलुक

संपादक: हरवीर सिंह
डिप्टी एडिटर: सुनील कुमार सिंह
एसोसिएट संपादक: प्रशांत श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक संपादक: हरीश मानव
सहायक संपादक: के. के. कुलश्रेष्ठ, आकांक्षा पारे काशिव
वरिष्ठ कॉपी संपादक: सत्येन्द्र प्रकाश
विशेष संवाददाता: रवि भोई, कुमार भवेश चंद्र
संवाददाता: प्रतीक वर्मा
वेब टीम: आर.एस. राणा, शशिकांत वत्स, उपासना पांडेय, अक्षय दुबे
एडिटोरियल कंसल्टेंट: हरिमोहन मिश्र
डिजाइन: विमल सरकार (सीनियर आर्ट डायरेक्टर) रोहित कुमार राय (डिजाइनर), रंजीत सिंह (विजुअलाइजर)
फोटो सेक्शन: जितेंद्र गुप्ता (फोटो एडिटर), त्रिभुवन तिवारी (चीफ फोटोग्राफर), संदीपन चटर्जी, अपूर्व सलकड़े (सीनियर फोटोग्राफर) सुरेश कुमार पांडे (स्टाफ फोटोग्राफर) एस. रक्षित (चीफ फोटो कोऑर्डिनेटर), जे.एस. अधिकारी (सीनियर फोटो रिसर्चर)
संदर्भ: अलका गुप्ता

बिजनेस कार्यालय:
चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर: इंद्रनील रॉय
प्रकाशक: संदीप कुमार घोष
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट: मीनाक्षी आकाश
सीनियर जनरल मैनेजर: देववाणी टैगोर, शैलेन्द्र वोहरा
डिजिटल टीम: अमित मिश्रा
मार्केटिंग:
वाइस प्रेसिडेंट: श्रुतिका दीवान
सर्कुलेशन एंड सब्सक्रिप्शन: अनिंद्य बैनर्जी, गगन कोहली, जी. रमेश (साउथ), विनोद कुमार (नार्थ), अरुण कुमार झा (ईस्ट), शेखर सुवर्राना

प्रोडक्शन:
जनरल मैनेजर: शशांक दीक्षित
मैनेजर: सुधा शर्मा, गणेश साह (डिप्टी मैनेजर), गौरव श्रीवास (एसोसिएट मैनेजर)
अकाउंट:
वाइस प्रेसिडेंट: दीवान सिंह बिष्ट
कंपनी सेक्रेटरी एवं लॉ ऑफिसर: अंकित मंगल
प्रधान कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
संपादकीय कार्यालय: ए.बी.-5 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
टेलीफोन: 011-71280400, फैक्स: 26191420

संपादकीय ईमेल
edithindi@outlookindia.com
ग्राहकी के लिए संपर्क: 011-71280433, 71280462, 71280307
yourhelpline@outlookindia.com
अन्य कार्यालय:
मुंबई: 022-50990990
कोलकाता: 46004506, **फैक्स:** 46004506
चेन्नई: 42615224, 42615225 **फैक्स:** 42615095
बेंगलूरू: 43715021
संपादक हरवीर सिंह
आउटलुक पब्लिशिंग (इंडिया) प्रा.लि. की तरफ से इंद्रनील रॉय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली से प्रकाशित।

कुल पृष्ठ संख्या 50 कवर सहित

समझदारी जरूरी

4 मई के अंक में लॉकडाउन पर आधारित कई आलेख पढ़ने को मिले। अगर लॉकडाउन न होता तो स्थिति नियंत्रित करना मुश्किल होता। आम जनता ने भी इसमें सहयोग दिया है। सरकार को चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। सरकार ने घोषणा की है कि जहां कोरोना मरीज नहीं मिलेंगे वहां छूट दी जाएगी। लेकिन कोई भी छूट का गलत फायदा न उठाए और लापरवाही न बरतें। समझदारी ही हमें इस महामारी से बचाएगी।

जफर अहमद | मधेपुरा, बिहार

सैंडर्स और भारत

आउटलुक के 4 मई 2020 के विशेष डिजिटल अंक में प्रणय शर्मा का अमेरिका के डेमोक्रेट्स नेता सैंडर्स पर लेख पढ़ा। सैंडर्स के समाजवादी विचारों और अमेरिकी राजनीती में उनके विचारों के असर पर सरलता से लिखा गया है। सैंडर्स का राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर होना भारत के अनुकूल है। ये वही हैं, जो फरवरी में दिल्ली में हुई हिंसा को धार्मिक हिंसा के रूप से प्रचारित करने की कोशिश कर रहे थे। सैंडर्स के चश्मे का नंबर चीन, तुर्की से मिलता जुलता है। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही अपनी बातों को लेकर अस्थिर रहते हैं लेकिन भारत के बाजार तक अमेरिका को जोड़ने के लिए वे हमेशा भारत की ओर आकर्षित रहते हैं। सैंडर्स ने बेरोजगारों और युवाओं को प्रभावित किया है। उनकी इस लोकप्रियता को नकारा नहीं जा सकता।

कृष्ण चंद्र त्रिपाठी | रीवा, मध्य प्रदेश

कठोर कार्रवाई की जरूरत

मुंबई के उप-नगर पालघर में पुलिसकर्मियों के सामने ही दो संतों की 'मॉब लिंचिंग' महाराष्ट्र को कलंकित करने वाली घटना है। इसके लिए महाराष्ट्र शासन को संबंधित पुलिसकर्मियों सहित दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन पर जनता की सुरक्षा का दायित्व है, वे ही यदि मूकदर्शक बने रहेंगे, तो जनता किसके भरोसे रहेगी? ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र पुलिस के गौरव को नष्ट करती हैं। दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

रमेश शिंदे | गोवा

पुरस्कृत पत्र

कुदरत की मार

कोरोना महामारी के चलते किसान पहले ही परेशान थे। अब बेमौसम बारिश ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। खेत से गेहूं की तैयार फसल कटकर घर नहीं आ पाई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। कई किसानों की फसल कट कर खेत में ही पड़ी है। बेमौसम बरसात से किसान की नींद उड़ा दी हैं। वहां पड़े-पड़े अनाज भीग कर खराब हो जाएगी। ऐसे में खराब गेहूं बाजार में बचने में भी उन्हें परेशानी होगी। जाहिर सी बात है इससे गेहूं के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। यह सभी के लिए कठिन समय है। नौकरी पेशा लोगों के साथ किसान भी संकट में हैं। मौजूदा कठिन समय में सरकार को किसानों और निम्न आय वर्ग वालों के लिए मदद की घोषणा करनी चाहिए। किसानों की मदद के लिए राज्य सरकारों को सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी छूट देनी चाहिए।

डॉ. श्रीगोपाल नारसन | रुड़की, उत्तराखंड

अब आप अपने पत्र इस मेल पर भी भेज सकते हैं:
hindioutlook@outlookindia.com

श्रेष्ठ पत्र को उपहार स्वरूप 1000 रुपये मूल्य की पुस्तकें

सामयिक प्रकाशन
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
samayikprakashan@gmail.com
www.samayikprakashan.com

तकनीकी विकास ने पत्र लेखन की विधा को हाशिए पर जरूर धकेला है, लेकिन यह विधा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पत्र लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए आउटलुक हिंदी पत्रिका अपने पाठकों के लिए एक योजना ला रही है। किसी भी पत्रिका के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पाठकों के पत्र महत्वपूर्ण होते हैं। आउटलुक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर 150 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजें और पाएं हिंदी के प्रतिष्ठित सामयिक प्रकाशन की ओर से एक हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें। हर अंक में छपने वाले पत्रों में से एक सर्वश्रेष्ठ पत्र चुना जाएगा।

ध्यान रखें कि पत्र साफ लिखे गए हों और लंबे न हों। संबंधित लेख का उल्लेख जरूर करें और अपनी टिप्पणी सटीक रखें। चुने गए पत्र पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। अपना नाम एवं पिन कोड सहित पूरा पता जरूर लिखें। संपादकीय निर्णय सर्वोपरि होगा।

आउटलुक पत्रिका प्राप्त करने के स्थान

दक्षिण: **हैदराबाद** यादगिरी बुक स्टॉल, 040-66764498, **सिकंदराबाद** उस्मान बुक स्टॉल, 9912850566

उत्तर: **दिल्ली** - आईबीएच बुक्स एंड मैग्जीन डिस्ट्रिब्यूटर्स, 011-43717798,011-43717799, **लखनऊ** - सुभाष पुस्तक भंडार प्रा. लिमिटेड, 9839022871, **चंडीगढ़** - पुरी न्यूज एजेंसी, 9888057364, **देहरादून**- आदित्य न्यूज एजेंसी, 9412349259, **भोपाल**- इंडियन न्यूज एजेंसी, 9826313349, **रायपुर**- मुकुंद पारेख न्यूज एजेंसी, 9827145302, **जयपुर**-नवरत्न बुक सेलर, 9829373912, **जम्मू**- प्रीमियर न्यूज एजेंसी, 9419109550, **श्रीनगर**- जेपी न्यूज एजेंसी, 9419066192, **दुर्ग (छत्तीसगढ़)** - खेमका न्यूज एजेंसी, 9329023923

पूर्व: **पटना**- ईस्टर्न न्यूज एजेंसी, 9334115121, **बरौनी** -ज्योति कुमार दत्ता न्यूजपेपर एजेंट, 9431211440, **मुजफ्फरपुर**-अन्नू मैग्जीन सेंटर, 9386012097, **मोतीहारी**- अंकित मैग्जीन सेंटर, 9572423057, **कोलकाता**- विशाल बुक सेंटर, 22523709/22523564, **रांची**- मॉडर्न न्यूज एजेंसी, 9835329939, रवि कुमार सोनी, 9431564687, **जमशेदपुर**-प्रसाद मैग्जीन सेंटर, 2420086, **बोकारो**-त्रिलोकी सिंह, 9334911785,**भुवनेश्वर**-ए. के. नायक, 9861046179, **गुवाहाटी**- दुर्गा न्यूज एजेंसीज, 9435049511

पश्चिम: **नागपुर**-नेशनल बुक सेंटर, 8007290786, पाठक ब्रदर्स, 9823125806, **नासिक**- पाठक ब्रदर्स, 0253-2506898, **पुणे**- संदेश एन एस एजेंसी, 020-66021340,**अहमदाबाद**-के वी अजमेरा एंड संस, 079-25510360/25503836, **मुंबई**- दंगत न्यूज एजेंसी, 22017494

संतुलित रवैया जरूरी

हरवीर सिंह

महामारी कोविड-19 से पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है और उसने दुनिया के 78 देश में लागू लॉकडाउन में, सबसे सख्त लॉकडाउन में सरकार को पूरा सहयोग दिया, क्योंकि लड़ाई जिंदगी बचाने की है। अभी यह लड़ाई जारी है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, बल्कि दुनिया भर में कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक इसका इलाज या टीका विकसित नहीं कर लिया जाता। हो सकता है कुछ माह या साल भर तक लोगों की जिंदगी कुछ अलग तरीके से चले, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर संक्रमण से बचने की सावधानियां शामिल हों। आंशिक लॉकडाउन, कंटेनमेंट, रेड और ग्रीन जोन जैसे क्षेत्र बनते-बदलते रह सकते हैं। जाहिर है, दुनिया में ऐसा दौर मौजूदा पीढ़ियों ने नहीं देखा है। ऐसे असामान्य दौर में सरकारों के फैसले भी असाधारण ही होने थे। लेकिन हर देश और समाज की अपनी संरचना और प्रकृति है, इसलिए एक ही तरह का फॉर्मूला हर जगह कारगर नहीं हो सकता। जो अमेरिका, यूरोप या चीन में हुआ, वैसा ही हमारे यहां भी हो, यह संभव नहीं है। हमारा देश संघीय ढांचे और बहुभाषी, बहुधर्मी, समाज की बहुश्रेणियों और बहुसंस्कृति वाला है। यहां ये बातें कहने की इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि महामारी से लड़ने में हमारी मजबूती के साथ कई कमजोरियां भी सामने आई हैं।

केंद्र सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए रणनीति बनाने में शुरुआती दौर में राज्यों के साथ बेहतर तालमेल से परहेज किया। पहला 21 दिन का लॉकडाउन जिस तरह से लागू हुआ उसमें राज्य लगभग बिना तैयारी के थे। लिहाजा, मानवीय त्रासदी की तसवीरें देश को दशकों तक बेचैन करती रहेंगी। तालमेल की ऐसी ही खामियां चिकित्सा सामान, पीपीई किट और जांच किट खरीदने के मामले में दिखीं, जिसके नियम बार-बार बदलने पड़े। आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ने के बाद पैदा हालात से निपटने के लिए केंद्र ने कई आदेश जारी किए, जिनमें उतनी ही तेजी से बदलाव करने पड़े। राजस्व स्रोतों के लगभग सूख जाने से राज्य प्रधानमंत्री के साथ लगभग हर बैठक में केंद्रीय करों में अपनी हिस्सेदारी और राहत पैकेज का मुद्दा उठाते रहे हैं। लॉकडाउन खोलने और जीवन तथा आजीविका की पटरी पर वापसी को लेकर ठोस रणनीति और पारदर्शिता की खासी कमी झलक रही है।

इस बीच सबसे बेचैन करने वाला पहलू महामारी में सांप्रदायिकता को जोड़ने का कुत्सित प्रयास रहा। प्रशासनिक और पुलिस की खामियों को सामने लाने के बजाय मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हुई। यही नहीं, इस बात पर भी सवाल खड़े होने चाहिए कि संक्रमित लोगों की संख्या में तबलीगी जमात के लिए अलग से कॉलम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दिल्ली सरकार ने कई सप्ताह तक इस तरह के आंकड़े अलग से बताए और केंद्रीय अधिकारियों की ब्रीफिंग में भी यह जानकारी साझा की गई। संचार माध्यमों और खासकर टीवी न्यूज चैनलों ने इस मुद्दे को काफी हवा दी। नतीजतन, एक समुदाय को लेकर लोगों की सोच प्रभावित हुई। यही नहीं, कुछ चुनिंदा जनप्रतिनिधियों ने भी समुदाय विशेष से दूरी बनाने के विवादास्पद बयान तक दिए। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई हक नहीं है। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वायरस किसी जाति-धर्म को नहीं देखता है। इस तरह की स्थिति हमारी कमजोरी को उजागर करती है और महामारी के इस संकट में यह देशहित में नहीं है।

कई मामलों में यह भी साबित होता है कि केंद्र सरकार कोई पुख्ता रणनीति नहीं बना पा रही है। मसलन, सरकार के दावे के मुताबिक बीमारी काबू में है और वह लॉकडाउन से बाहर निकलने की सोच रही है तो पारदर्शी तरीके से चरणबद्ध प्लान लोगों के साथ साझा करने में क्या बुराई है। उधर, हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। आर्थिक संकट से केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने खर्चों और वेतनभत्तों में कटौती जैसे कदम उठाए हैं। देश में बेरोजगारों की संख्या रिकार्ड 12 करोड़ तक पहुंच गई है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को लेकर काफी खींचतान चल रही है। असल में, जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद राज्यों के पास शराब की बिक्री से एक्साइज शुल्क, स्टॉम्प ड्यूटी और पेट्रोलियम उत्पादों पर राज्यों में लगने वाला वैट ही उनका मुख्य राजस्व स्रोत है। लेकिन लॉकडाउन में यह ठप-सा है।

इसके अलावा लगातार घरों में बंद रहने से बड़ी संख्या में मानसिक बीमारियों के संकेत मिलने लगे हैं। शिक्षण संस्थानों की बंदी से पढ़ाई-लिखाई भी ठप-सी है। पूरा फोकस कोविड-19 पर होने के चलते दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों के इलाज तो हो ही नहीं रहे हैं। ऐसे मरीजों के लिए दिकक्तें बढ़ सकती हैं।

वक्त का तकाजा है कि केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल हो और फैसले ऐसे हों जो महामारी से जिंदगियां और आजीविकाएं दोनों को बचाने के बीच संतुलन बना सकें। इसमें चूक होती है तो कहीं ऐसा न हो कि बीमारी से ज्यादा इलाज महंगा पड़ जाए।

@harvirpanwar

केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल हो और फैसले ऐसे हों जो महामारी से जिंदगियां और आजीविकाएं दोनों बचाने के बीच संतुलन बना सकें। क्षुद्र राजनीति और कुत्सित सांप्रदायिक कोशिशें देशहित में नहीं

प्रधानमंत्री केयर फंड की जांच अगर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नहीं कर सकते तो यह बहुत विस्मयकारी समाचार है। फंड शुरू से अपारदर्शी है। क्या इसका भी हाल इलेक्टोरल बांड की तरह होने जा रहा है ? अब तो भगवान ही मालिक है।

यशवंत सिन्हा, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री

खाली हाथ लौटे

मध्यप्रदेश के रीवा संभाग के एक भाजपा नेता ताल ठोंककर अपने समर्थकों से कह गए थे कि वे मंत्री बनकर शहर आएंगे। नेताजी शिवराज सिंह के पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे और काफी ताकतवर भी। इसलिए शिवराज के कैबिनेट में जगह मिलने की पूरी उम्मीद थी। मंत्री बनने के लिए भोपाल में डेरा भी डाले रहे, लेकिन शिवराज के नैनो कैबिनेट में जगह नहीं मिली। उनके संभाग से मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल गई, जिनका दूर-दूर तक नाम ही नहीं था। नेता जी मुंह लटकाए अपने शहर लौटकर लॉकडाउन से प्रभावित गरीब तबके के लोगों को राशन बांटने में लग गए हैं।

प्रचार हो तो कैसे

कोरोनाकाल में अखबारों के पन्ने घटने का सबसे ज्यादा नुकसान विपक्षी नेताओं को हो रहा है। उन्हें खबरों के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। सारी कवरेज सरकार और आम आदमी ले जा रहे हैं। हालांकि सत्ताधारी बयानवीरों के बयान भी हाशिए पर हैं। पर अधिक चिंता में हैं विरोधी नेता क्योंकि उनके बयानों को अधिक तवज्जो नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो पहले जैसी अहमियत नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टी के एक नेता इस बात से बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि यदि अखबार ऐसे ही विरोधी नेताओं को दरकिनार करते रहे तो उनकी आवाज जनता तक पहुंचेगी कैसे? नेता जी सोशल मीडिया पर पीड़ितों की मदद करते हुए तस्वीरें भी नहीं पोस्ट कर पाते क्योंकि वहां पर उनके पीछे ट्रोलर्स पड़ जाते हैं। इसलिए खीज बढ़ती जा रही है। परेशानी में यह कहते फिर रहे हैं कि इस हालत में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो जनता के मन में छवि क्या बनेगी? ऐसे में क्या करें..हम भी लॉकडाउन में घर में कैद हो जाएं? साफ है नेता जी को कुछ प्रभावकारी रास्ता अपनाना होगा।

बाबुओं की कोरोना परीक्षा

प्रदेश के मुखिया कोरोना से लड़ाई में दिन रात एक किए हुए हैं। टीम इलेवन के साथ हर रोज दिमागी कसरत का दौर जारी है। हर रोज बाबूओं के लिए नई परीक्षा खड़ी हो जाती है। जिला अधिकारियों की परीक्षा भी बेहद कड़ी है। आत्मअनुशासन के पाठ ने उनके लिए बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा खड़ी कर दी है। उन्हें मालूम है कि परीक्षा में कम अंक का मतलब फेल है। गौतमबुद्धनगर के जिलाधिकारी महोदय का हश्र नजीर के तौर पर दिख रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि कई जिलाधिकारी महोदय तो अपनी चौहद्दी की व्यवस्था का हाल लेने के लिए खुद ही खुफिया बन गए हैं। भेष बदलकर जमीनी हाल पता कर रहे हैं।

लापरवाह मंत्री

छत्तीसगढ़ के धुर नक्सली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक कैबिनेट मंत्री के बिंदास काम की चर्चा हो रही है। लॉकडाउन में मंत्री जी बंगले में बैठे-बैठे थक गए तो बोरियत मिटाने के लिए राजधानी से करीब 250 किलोमीटर एक बाबा से मिलने चले गए। वहां पहुंचकर स्वागत करवाने और मेल -मुलाकात से भी परहेज नहीं किया। इस पर विपक्षी दल भाजपा ने राज्यपाल के पास शिकायत भी कर डाली। लेकिन उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जल-जंगल और जमीन से जुड़े होने का उन्हें भरपूर फायदा मिल रहा है।

लालच की हद

आपातकाल में जितना खरीदी करो, जिस दर से खरीदी करो, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसमें कमीशन का खेल भी चलता है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मध्य प्रदेश में भी खरीदी होनी थी। कहते हैं राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसर इस खरीदी से अपने को दूर नहीं होने देना चाहते थे। इस वजह से कोरोना की जद में आने के बाद भी मुंह बंद रखा। उनके इस लालच के चलते राज्य का स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पर चला गया। अब लालच की भी हद होती है।

पेट पड़ गया भारी

कोविड-19 के साए से बचने के लिए लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से 40 दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। एक दिन चंडीगढ़ में सुबह शाम घर से बाहर ताजी हवा लेने के नाम पर सैर करने वाले 200 से अधिक लोग पार्क में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इसमें से करीब 50 आला अधिकारी भी थे। इन लोगों को दो घंटे तक एक क्रिकेट स्टेडियम में कैद रहना पड़ा। इस सख्ती से बौखलाए पंजाब और हरियाणा के कई अधिकारियों ने तो देख लेने तक की धमकियां दे डालीं।

राज्यों का संकट ज्यादा गहरा

राजस्व के स्रोत बंद होने से कहीं वेतन में देरी तो कहीं भत्तों पर रोक

चंडीगढ़ से **हरीश मानव,** लखनऊ से **कुमार भवेश चंद्र,** रायपुर से **रवि भोई**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, तो उसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने दिसंबर और जनवरी का जीएसटी बकाये का मुद्दा उठा दिया। उसी दिन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर जीएसटी का 4,386 करोड़ रुपये का बकाया देने की मांग कर डाली। दरअसल, लॉकडाउन के चलते कुछ जरूरी वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं को छोड़कर करीब 70 फीसदी उद्योग धंधे और सेवाएं ठप हैं। आर्थिक गतिविधियां सीमित होने से राज्यों के संसाधन सूखने लगे हैं। पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट, प्रॉपर्टी की स्टांप ड्यूटी, वाहन रजिस्ट्रेशन और शराब पर आबकारी शुल्क संसाधन जुटाने के लिए राज्यों के अपने स्रोत हैं, लेकिन पेट्रोल-डीजल की बिक्री 30 से 40 फीसदी रह गई है, शराब की

राज्यों को चाहिए मदद : मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक करते प्रधानमंत्री

बिक्री बंद है और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नाममात्र की हो रही है। खजाने में पैसे नहीं होने के कारण राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही हैं। कुछ राज्यों ने तो कर्मचारियों को मिलने वाले कई भत्तों पर भी रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कहा, "कोनो अर्निंग नेइ, शुधु बर्निंग (कोई कमाई नहीं है, सिर्फ खर्च हो रहा है)।" राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र की तरफ से बड़े पैकेज के बिना लॉकडाउन के बाद राज्य कैसे सामान्य स्थिति में लौटेंगे।

खाने-पीने की जिन जरूरी वस्तुओं और दवाओं का उत्पादन और बिक्री जारी है, उनमें 70 फीसदी से अधिक वस्तुएं या तो जीएसटी मुक्त हैं या उन पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगता है। जीएसटी का 80 फीसदी गैर-जरूरी वस्तुओं और सेवाओं से आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक5 राज्यों का दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 का जीएसटी कंपेंसेशन 30 से 34 हजार करोड़ रुपये बकाया है। क्रिसिल का अनुमान है कि 40 दिन के लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एसबीआइ के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्य कांति घोष के अनुसार अगर

राज्य 2018-19 के जीएसडीपी का एक फीसदी भी कोविड से निपटने में खर्च करते हैं, तो यह रकम 1.6 लाख करोड़ रुपये बैठेगी। फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) एक्ट के अनुसार राज्यों का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के तीन फीसदी तक हो सकता है। राज्य इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही प्रधानमंत्री के साथ बैठक में कई राज्यों ने इसे पांच फीसदी करने की मांग की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 17 अप्रैल को राज्य सरकारों के लिए वेज एंड मींस एडवांस की सीमा 2019-20 की तुलना में 60 फीसदी बढ़ा दी। इस व्यवस्था के तहत राज्य आरबीआइ से 90 दिनों के लिए रेपो रेट पर कर्ज ले सकते हैं। हालांकि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का कहना है कि इस एडवांस से राज्यों को 19,335 करोड़ रुपये की ही अतिरिक्त नकदी मिलेगी।

सूखते संसाधनों का असर साफ दिखने लगा है। पंजाब और हरियाणा के 50 फीसदी से अधिक कर्मचारियों को मार्च का वेतन 20 अप्रैल के बाद जारी हुआ। पंजाब में 25 अप्रैल तक एक लाख से अधिक मुलाजिमों का वेतन बाकी था। मार्च में जीएसटी संग्रह तो गिरा ही, तालाबंदी के कारण अप्रैल का जीएसटी संग्रह भी 50 फीसदी रहने के आसार हैं। आरबीआइ के आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब को केंद्र से जीएसटी में हिस्सेदारी के तौर 43 फीसदी राजस्व हासिल होता है। बाकी 57 फीसदी राजस्व पेट्रोल-डीजल व अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट, शराब पर एक्साइज, इलेक्ट्रिसिटी डयूटी, प्रॉपर्टी पर स्टांप डयूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, व्हीकल टैक्स, खनन रॉयल्टी आदि से हासिल होता है। लॉकडाउन के चलते पेट्रोलियम उत्पादों से राजस्व 30 फीसदी और बिजली से 40 फीसदी रह गया है। राजस्व के बाकी स्रोत लगभग शून्य हैं। यदि लॉकडाउन 3 मई तक ही रहता है तो पंजाब को चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 10,309 करोड़ रुपये कम राजस्व मिलने की आशंका है। इसलिए राज्य सरकार ने अपने प्रशासनिक खर्चों में 30 फीसदी कटौती कर दी है।

पंजाब को केंद्र से लॉकडाउन में शराब बिक्री की अनुमति नहीं मिली तो राज्य सरकार ने लॉकडाउन के बीच खनन की अनुमति दे दी। हरियाणा ने भी प्रॉपट्री की रजिस्ट्री शुरू कर दी। हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (राजस्व) धनपत सिंह ने *आउटलुक* को बताया कि 20 अप्रैल से रजिस्ट्री खोलने के पांच दिन में सरकार को स्टांप डयूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 5.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

पंजाब के 7.5 लाख मुलाजिमों और पेंशनभोगियों में शिक्षा विभाग और बोर्ड-कॉरपोरेशन के करीब एक लाख मुलाजिमों को मार्च का वेतन नहीं मिल पाया है। अब अप्रैल का 3,500 करोड़ रुपये का वेतन और पेंशन सिर पर है। गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजों के एक लाख से अधिक कर्मचारियों का वेतन तो जनवरी से बकाया है। पंजाब अनएडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एसोसिएशन के महासचिव डॉ. अंशु कटारिया ने बताया कि सरकार से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 1,850 करोड़ बकाया जारी न होने से 1,650 कॉलेजों के एक लाख से अधिक कर्मचारियों को चार महीने से वेतन नहीं किया जा सका है।

आउटलुक से बातचीत में पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया, "अप्रैल में वेतन, पेंशन, कोविड-19 राहत कार्य और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7,301 करोड़ रुपये का खर्च बैठता है। केंद्र से 3,000 करोड़ रुपये अंतरिम मुआवजे के अलावा दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक जीएसटी के 4,400 करोड़ रुपये बकाये की मांग की है।" उन्होंने बताया कि केंद्र से मार्च में जीएसटी के 1,136 करोड़, कोविड-राहत फंड में 225 करोड़ और वित्त आयोग से 625 करोड़ मिले हैं। लॉकडाउन के एक महीने में वैट, एक्साइज, स्टांप ड्यूटी और मोटर व्हीकल टैक्स से रेवेन्यू घटकर सिर्फ 30 फीसदी रह गया है। बादल के अनुसार, 2020-21 के बजट में अप्रैल में 3,360 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का अनुमान था। इसमें जीएसटी से 1,322 करोड़, पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट से 465 करोड़, स्टेट एक्साइज से 521 करोड़, मोटर व्हीकल टैक्स से 198 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी डयूटी से 243 करोड़, स्टांप डयूटी से 219 करोड़ और 392 करोड़ रुपये नॉन टैक्स रेवन्यू मद में प्राप्त होने थे।

केंद्र की ओर से राहत पैकेज और जीएसटी का बकाया जारी न किए जाने की सूरत में बादल ने फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) एक्ट में मंजूर सीमा से अधिक कर्ज दिलाने की गुहार केंद्र से लगाई है। उन्होंने ने बताया

मंदी की मार : कारोबार बंद होने से खजाना खाली, योगी सरकार ने छह भत्ते खत्म किए

कि आरबीआइ ने हाल ही राज्यों को वेज एंड मींस एडवांस की जो सीमा बढ़ाई है, उससे 500 करोड़ रुपये अधिक एडवांस मिलने से कुछ राहत मिलेगी।

खस्ता वित्तीय हालात पर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को घेरते हुए शिरोमणि अकाली दल के महासचिव और पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम मजीठिया ने आउटलुक से कहा, "राजस्व प्रबंधन में सरकार की नाकामी से राज्य के कर्मचारी परेशान हैं। 2018 से कर्मचारियों के डीए का 5000 करोड़ रुपये बकाया है।" भाजपा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि आपदा प्रबंधन फंड में पंजाब को मार्च में 247.5 करोड़ और 2020-21 के लिए 15वें वित्तीय आयोग ने राजस्व घाटा ग्रांट के रूप में 638.25 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके बावजूद सरकार जनता से झूठ बोल रही है कि केंद्र उसे संकट में राहत के लिए मदद नहीं कर रहा है।

उत्तर प्रदेश की स्थिति भी कुछ अलग नहीं। खर्च बचाने के लिए राज्य सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में पूरे एक साल तक 30 फीसदी कटौती के साथ ही विधायक निधि को भी एक साल के लिए निलंबित रखने का फैसला किया है। यह रकम मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में जाएगी। आपदा निधि 1951 में बदलाव कर इसमें 600 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए एक साल के लिए स्थगित करने के साथ छह तरह के भत्ते भी समाप्त कर दिए गए हैं। नगर भत्ता, सचिवालय भत्ता, रिसर्च भत्ता और विशेष भत्ता पर एक साल के

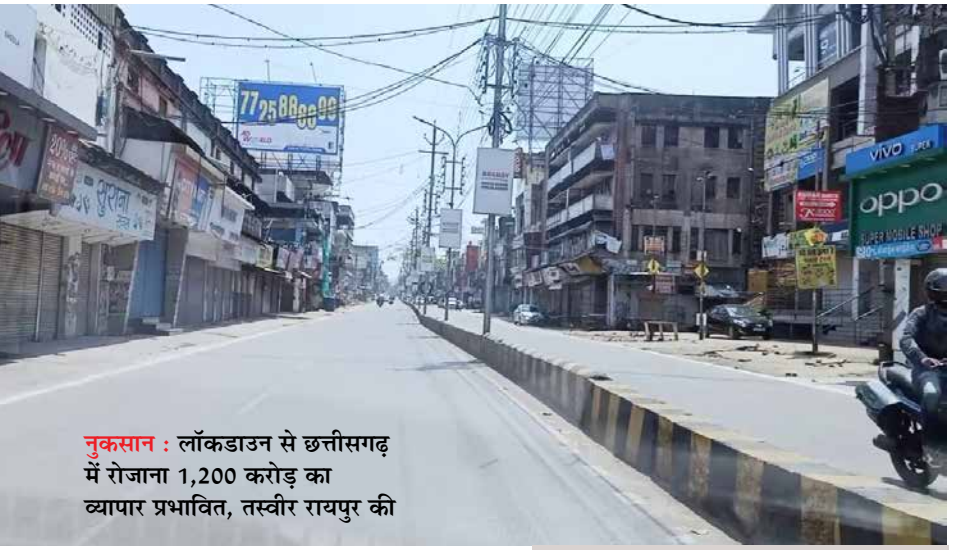

नुकसान : लॉकडाउन से छत्तीसगढ़ में रोजाना 1,200 करोड़ का व्यापार प्रभावित, तस्वीर रायपुर की

लिए रोक लगा दी गई। अपर मुख्य सचिव (वित्त) संजीव मित्तल के इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों में तीखी प्रतिक्रिया है। वे इसे अमानवीय बताते हुए हालात सामान्य होते ही आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडेय कहते हैं, "भत्तों में कटौती का फैसला अदूरदर्शी है। कर्मचारी स्वेच्छा से एक या दो दिन का वेतन हर महीने देने को तैयार हैं।" विपक्षी दलों के नेता भी भत्ते में कटौती का विरोध करने लगे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुलकर कर्मचारियों का समर्थन कर रही हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जरूर फिलहाल इस मामले पर चुप हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से 25 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक की बचत होगी। कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए फ्रीज करने से 16 हजार करोड़ रुपये बचेंगे। इसके अलावा 9 हजार करोड़ की बचत छह तरह के भत्तों पर रोक से होगी। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में शराब की दुकानें पूरी तरह बंद हैं। पान मसाला और गुटखा बेचने पर भी पाबंदी है। शुरुआत में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से होने वाली आय भी शून्य हो गई थी, लेकिन बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्री की शुरुआत कर दी गई, पर यह इतनी धीमा है कि इससे ज्यादा राजस्व की उम्मीद फिलहाल बेकार है।

चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुराग मिश्र कहते हैं, "शुरुआत में लगभग सभी कारोबार ठप हो गए थे। अब जो थोड़ी गतिविधियां शुरू हुई हैं, उनसे बड़ी उम्मीद बेमानी है। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए भी कारोबारियों को 24 मई से 6 जुलाई तक की छूट मिली हुई है। जाहिर है सरकारी खजाने को इससे होने वाली आय के लिए इंतजार तो करना ही होगा।"

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रमुख अर्थशास्त्री डॉ. अरविंद मोहन कहते हैं, "राजस्व प्राप्ति के मोर्चे पर कड़ा संघर्ष साफ दिख रहा है। इन हालात में कोविड-19 जैसी आपदा का सामना करने के लिए सरकार के पास विकल्प बेहद सीमित हैं। अनावश्यक खर्चों में कटौती ही ऐसा विकल्प है जिससे सरकार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च कर पाएगी।" मौजूदा परिस्थिति में विधायकों के वेतन और कर्मचारियों के भत्तों में कटौती को डॉ. मोहन उचित फैसला बताते हैं। उनका सुझाव है कि बड़े अफसरों के पेट्रोल खर्च और मनोरंजन भत्तों पर रोक जैसे कड़वे फैसले भी करने चाहिए। इसके अलावा सरकारी स्कीमों की समीक्षा करके वह राशि स्वास्थ्य क्षेत्र और लघु उद्योगों के लिए खर्च करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा कृषि क्षेत्र पर भी अधिक फोकस करने की जरूरत है। यहां से सरकार को अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जरूरी ताकत मिल सकती है।

छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन के कारण करीब 11 हजार करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान का अंदेशा है। राज्य का आर्थिक आधार खेती के साथ लोहा, सीमेंट और कोयला आधारित उद्योग हैं। बिजली बेचकर भी राज्य अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। स्टील इंडस्ट्री से राज्य को 26 फीसदी राजस्व मिलता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के उपाध्यक्ष अमर पारवानी का कहना है कि लॉकडाउन से राज्य में रोजाना औसतन 1,200 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो रहा है। इसकी भरपाई अब संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा के अनुसार शादी के सीजन को देखते हुए व्यापारियों ने एडवांस माल मंगवा लिया था। कुछ सामान आ गया, कुछ अटक गया। लॉकडाउन खुलने के बाद बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं। कुछ उद्योग संगठनों ने राज्य सरकार से विशेष पैकेज की भी मांग की है। लेकिन राज्य सरकार की अपनी समस्या है, वह कोरोना संक्रमण से निपटने के साथ-साथ लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक गतिविधियों के सुचार रूप से संचालन और अपने खर्च के लिए केंद्र सरकार की तरफ ताक रही है। व्यापार और उद्योग ठप होने से उससे मिलने वाला राजस्व तो कम हुआ ही है, शराब से होने वाली आय भी बंद हो गई है। एक महीने में शराब के मद में उसे 400 करोड़ का नुकसान होने का अंदेशा है। पेट्रोल-डीजल की खपत कम होने से वैट संग्रह भी कम हो गया है। खनिज रायल्टी भी प्रभावित हुई है। राज्य सरकार को अब तक जीएसटी के हिस्से के 1,500 करोड़ रुपये मिले हैं, बाकी 500 करोड़ का इंतजार है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र से राज्यों को आर्थिक पैकेज देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि रायपुर सांसद सुनील सोनी का कहना है कि मुख्यमंत्री केंद्र से पैकेज मांगने के बजाय निर्माण मजदूर कल्याण निधि के अंतर्गत 18 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य के खाते में जमा 350 करोड़ रुपये से भुगतान करे। 18 लाख निर्माण श्रमिकों को 1,000 रुपये देने पर भी सिर्फ 180 करोड़ ही खर्च होंगे। इस संबंध में केंद्र की एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य है। ऐसा न करके केंद्र से 30,000 करोड़ का पैकेज मांगकर मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में भी 350 करोड़ से अधिक राशि जमा है।

एक लाख दो हजार 907 करोड़ रुपये सालाना बजट वाले छत्तीसगढ़ पर 57,848 करोड़ का कर्ज है। सरकार की चिंता किसानों को धान का बोनस देने की भी है, जिसके लिए बजट में 5,100 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोरोना संकट के बाद इस पर भी संशय के बादल मंडराने लगे हैं।

पंजाब ने मोंटेक की अध्यक्षता में 20 विशेषज्ञों की टॉस्कफोर्स बनाई

पंजाब सरकार ने कोविड-19 के असर से अर्थव्यवस्था को अगले एक साल के भीतर बहाल करने के लिए योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया की अगुवाई में 20 अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों की टॉस्क फोर्स गठित की है। टॉस्क फोर्स को अपनी पहली रिपोर्ट 31 जुलाई, दूसरी 30 सितंबर और आखिरी रिपोर्ट 31 दिसंबर 2020 तक सरकार को सौंपनी है। आहलूवालिया के अलावा टॉस्क फोर्स के अन्य सदस्यों में एम. गोविंद राव, रथीन रॉय, अशोक गुलाटी, देवेश कपूर, टी. नंदकुमार, अजयपाल सिंह बंगा और एसपी ओसवाल प्रमुख हैं।

"केंद्र आर्थिक पैकेज दे"

छत्तीसगढ़ के ***मुख्यमंत्री भूपेश बघेल*** *ने कहा कि राज्य में पहले ही बचाव के उपाय कर लिए गए, जिसके कारण यहां हालत नहीं बिगड़ी। आउटलुक के विशेष संवाददाता* ***रवि भोई*** *से खास बातचीत में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, लॉकडाउन खोलने या न खोलने का अधिकार राज्यों को देना चाहिए। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप्प हो गई हैं। व्यापार-उद्योग को नए सिरे से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार से राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए। बातचीत के अंश :*

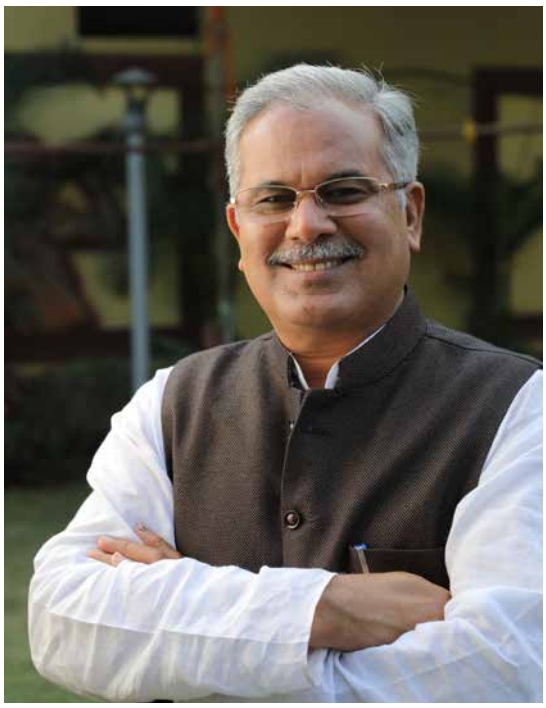

कोरोना संक्रमण रोकने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ की खास गिनती हो रही है और इसे सराहा जा रहा है। संक्रमण फैलने से रोकने की रणनीति क्या रही?

हमने बचाव के साथ सुरक्षा नियम का पालन किया। देश में लॉकडाउन लागू होने से पहले 19 मार्च को ही हमने धारा 144 लागू कर सार्वजानिक स्थानों पर भीड़ न बढ़ने के साथ राज्य की सीमाएं सील कर दी थीं। स्कूल-कालेज बंद भी कर दिए थे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया। लोगों ने सरकार की बात को समझा।

छत्तीसगढ़ में गांवों तक संक्रमण का प्रभाव नहीं पहुंचा। यह कैसे संभव हुआ?

यह बीमारी विदेश से आई। विदेश यात्रा से लौटने वालों को हमने होम क्वारेंटाइन किया। उन पर लगातार नजर रखी। उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की। इस कारण यह सिर्फ शहरों तक सीमित रहा। ग्रामीणों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया।

इसमें केंद्र सरकार का सहयोग मिला?

केंद्र सरकार ने टेस्टिंग किट्स और दूसरे साधन मुहैया कराए। बाद में राज्यों को खरीदी के अधिकार दिए। संसाधन और टेस्टिंग सुविधा सीमित है। इस कारण हमने बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी।

क्या छत्तीसगढ़ में जांच कम हो रही है?

दिल्ली, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों की तुलना में जांच कम हो रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर विदेश से आने वालों या बुखार वाले मरीजों की ही जांच की गई। हमने हाथ धोने के प्रति जागरूकता और फिजिकल डिस्टेंस पर जोर दिया।

लॉकडाउन का राज्य की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का प्रभाव देखते हैं?

उद्योग-धंधे चौपट हो गए हैं। रजिस्ट्री से लेकर परिवहन और माइनिंग समेत दूसरे सारे काम रुक गए हैं। इससे राज्य का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

राज्य की आर्थिक हालत सुधारने के लिए केंद्र सरकार से अब तक कोई मदद मिली?

नेशनल डिजास्टर फंड का हिस्सा मिलना था, पर नहीं मिला। जीएसटी के 2,000 करोड़ रुपये में से हमें अपने हिस्से के 1,500 करोड़ मिले हैं।

लॉकडाउन से हुई हानि से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ ने केंद्र से आर्थिक पैकेज मांगा है?

छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से 30 हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। 10 हजार करोड़ रुपए तो राज्य के उद्योगों को फिर से चलाने के लिए चाहिए। राज्यों के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। राजस्व कहां से आएगा? आर्थिक पैकेज न मिलने से कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा।

आर्थिक पैकेज की मांग कांग्रेसशासित राज्य कर रहे हैं। भाजपाशासित या दूसरे मुख्यमंत्री नहीं?

उनकी मौन सहमति है। किसी ने आर्थिक पैकेज का विरोध नहीं किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। इसे आप किस रूप में देखते हैं?

किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उद्योग और व्यापार चलेंगे। इस कारण से रिजर्व बैंक ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की है। पिछले साल सरकार ने किसानों का धान 2,500 रुपये क्विंटल की दर से खरीदा था। इस साल भी 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है और बोनस के तौर पर अंतर की राशि राजीव किसान न्याय योजना के तहत जल्द किसानों को दी जाएगी।

आपने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखा है। इसकी कोई खास वजह?

भारत सरकार को हम चावल देते हैं। राज्य ने भारत सरकार से केंद्रीय पूल में 31 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया था। लेकिन अभी सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन की ही सहमति दी गई है। राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल बांटने के बाद भी राज्य के पास 10 लाख मीट्रिक टन धान बच जाएगा। यही वजह है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए राज्य ने केंद्र से अतिरिक्त चावल लेने के लिए केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है।

छत्तीसगढ़ सरकार कोटा में पढ़ने वाले बच्चों को वापस लाए। क्या दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी लाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

कोटा में बच्चे एक ही जगह पर थे, इसलिए उन्हें लाना संभव हुआ। कई और शहरों में भी पढ़ने वाले कुछ और बच्चे फंसे हुए हैं, ऐसी ही स्थिति मजदूरों के मामलों में भी है। कुछ मजदूर जम्मू-कश्मीर में फंसे हैं, तो कुछ किसी और राज्य में। दो-चार बच्चों या मजदूरों के लिए बसें भेजना संभव नहीं है। पर उन्हें अपने गृह राज्य में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। फंसे बच्चों और मजदूरों को वापस लाने के लिए ट्रेन चलाने के लिए मैंने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है और उनसे आग्रह भी किया है।

तीन मई के बाद आप लॉकडाउन खोलने के पक्ष में हैं या बढ़ाने के?

लॉकडाउन राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ के पडोसी राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमित केस आ रहे हैं, ऐसे में राज्यों की सीमा खोलने से वहां भी खतरा बढ़ जाएगा।

सुशासन बाबू की दुविधा

दूसरे राज्य प्रवासी मजदूरों और कोटा से छात्रों की वापसी में जुटे, लेकिन नीतीश का इनकार

पटना से **गिरिधर झा**

आगामी विधानसभा चुनाव के महज कुछ महीने पूर्व कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने की चुनौती के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ी राजनैतिक दुविधा में घिर गए हैं। लॉकडाउन के चलते राज्य से बाहर फंसे लाखों दिहाड़ी मजदूर और कोटा में पढ़ रहे हजारों छात्रों को घर वापस बुलाने के प्रश्न पर उनकी सरकार को विपक्ष की तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। कई मुख्यमंत्रियों ने देशव्यापी बंदी के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे अपने-अपने राज्य के लोगों को विशेष इंतजाम करके वापस बुलाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन नीतीश अब तक इसे गैर-जरूरी समझते रहे हैं। नीतीश के अनुसार महामारी से निबटने का सबसे कारगर तरीका सामाजिक दूरी ही है। लोगों की आवाजाही से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। नीतीश चाहते हैं कि अभी जो जहां है, वहीं रहे। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों की वापसी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, "ये छात्र संपन्न परिवारों से आते हैं और अधिकतर अपने परिजनों के साथ रहते हैं। उन्हें वापस बुलाने की जरूरत क्यों है।" मुख्यमंत्री के अनुसार, जब प्रवासी मजदूर कई सप्ताह से अन्य राज्यों में फंसे हैं, कोटा से छात्रों को बुलाना उचित नहीं है। नीतीश सरकार ने विभिन्न शहरों में फंसे लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए हैं और राहत कार्यों पर अब तक करीब 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

बिहार से हर साल हजारों छात्र इंजीनियरिंग या मेडिकल की परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं। 25 मार्च से शुरू लॉकडाउन के कारण वहां के सभी संस्थान बंद हो गए और आवागमन के साधनों के अभाव में अधिकतर छात्र वहीं फंस गए हैं। इनमें बिहार से गए छात्रों की संख्या लगभग 12 हजार है। उनमें से अनेक वापस आना चाहते हैं और कुछ ने इसके लिए धरना भी दिया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने बसें भेजकर अपने छात्रों को वापस बुला लिया तो विपक्षी पार्टियों ने नीतीश पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। कोटा में छात्रों का मामला अब पटना हाइ कोर्ट पहुंच चुका है। सुनवाई के दौरान नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन में छात्रों को वहां से नहीं लाया जा सकता। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की तो वहां भी नीतीश ने केंद्रीय आपदा अधिनियम में संशोधन करके केंद्र से सभी राज्यों के लिए एक समान नीति बनाने की मांग की। इस बीच, राजद समेत सभी विपक्षी दलों ने नीतीश पर हमला तेज कर दिया है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि दस राज्य सरकारों ने 25,000 से अधिक छात्रों को वापस बुला लिया, लेकिन नीतीश अपने अहं और छात्रों के प्रति उदासीनता के कारण ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार सत्ताधारी दलों के रसूखदार नेताओं को विशेष पास देकर उनके बच्चों को कोटा से वापस लाने की सुविधा दे रही है, लेकिन आम लोगों के बच्चों को वहीं छोड़ दिया है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी के अनुसार 17 लाख प्रवासी श्रमिकों और कोटा में पढ़ाई कर रहे कुछ हजार छात्रों को एक ही पलड़े पर तौल देना असंवेदनशील और अमानवीय भी है। दरअसल, भाजपा के एक विधायक द्वारा अपनी बेटी को कोटा से सड़क मार्ग द्वारा बिहार वापस लाने से विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। नवादा जिले के हिसुआ के विधायक अनिल सिंह हाल ही अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति पत्र लेकर कोटा में पढ़ रही अपनी बेटी को लेकर आ गए। जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने यह दावा किया कि ऐसा करने वाले वह अकेले नहीं हैं बल्कि 700 अन्य व्यक्तियों को ऐसी अनुमति मिली है। हालांकि, इसके बाद पास जारी करने वाले अधिकारी को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन इस प्रकरण ने नीतीश सरकार की समस्या जरूर बढ़ा दी है।

बंद दरवाजा : बिहार सरकार ने कहा है कि अभी दूसरे राज्यों से मजदूर प्रदेश में न लौटें

जब लाखों मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं, तब कोटा से छात्रों को बुलाना उचित नहीं होगा

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

फिक्र : रांची में जरूरतमंदों को खाना वितरित करते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

तबाही रोकना चुनौती

प्रदेश में जांच की सुविधा अपर्याप्त, बचाव के उपाय भी नाकाफी

रांची से **महेन्द्र कुमार**

झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल, रांची के रिम्स में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल के बाहर दो लोग बातें कर रहे थे। उनकी बातचीत से यह चिंता साफ झलक रही थी कि झारखंड बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहा है। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन इसके खत्म होते ही जैसे ही बाहर से लोग आएंगे, संक्रमण और फैलेगा। उनका सवाल था कि संसाधन और सुविधाओं के अभाव में झारखंड सरकार स्थिति को कैसे संभालेगी। झारखंड में कोरोना के संक्रमण का भयावह रूप अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी एक वजह जांच की रफ्तार का कम होना है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे एक चिकित्सक कहते हैं, "हम संदिग्धों की जांच ही नहीं कर पा रहे हैं, तो मरीजों का पता कैसे चलेगा। टेस्टिंग किट कम हैं, इसलिए जांच की रफ्तार सुस्त है।" झारखंड में पिछले एक महीने में महज 5,380 सैंपल की जांच की गई है। राज्य के पांच कोरोना जांच केंद्रों में हर दिन दो सौ से भी कम सैंपल की जांच हो रही है, यानी एक केंद्र में 40 से भी कम। महाराष्ट्र के एक जांच केंद्र में हर दिन औसतन 700 सैंपल की जांच होती है, जबकि दिल्ली में यह संख्या 810 है।

झारखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अधिक नहीं है। 31 मार्च को तबलीगी जमात से जुड़ी मलेशियाई महिला के रूप में राज्य में पहला मामला आया था, तब से 25 दिन में यह 70 तक पहुंचा है। कोरोना प्रबंधन की दूसरी सबसे बड़ी कमी संदिग्धों के चयन में है। विशेषज्ञ कहते हैं कि झारखंड में सैंपल लेने के बाद उस संदिग्ध को छोड़ दिया जाता है। तीन दिन बाद अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तब आइसोलेशन में रखा जाता है। इन तीन दिनों में वह कम से कम डेढ़ सौ लोगों को संक्रमित कर चुका होता है, लेकिन उनकी जांच नहीं होती। विशेषज्ञ बताते हैं कि जांच से ही कोरोना संक्रमण का पता लग सकता है। बिना लक्षण वाले लोग भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। एक और कमी यह है कि किसी कोरोना संक्रमित के परिजनों की जांच तुरंत नहीं की जा रही है, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा बना रहता है।

झारखंड के पास बचाव के भी पर्याप्त उपाय नहीं हैं। महज 4.85 लाख ट्रिपल लेयर मास्क और 45 हजार पीपीई किट से कितने स्वास्थ्यकर्मियों का बचाव हो सकता है? मास्क और सेनेटाइजर जैसी मूलभूत चीजें भी आसानी से नहीं मिल रही हैं। संक्रमण की जांच के लिए सिर्फ 504 इंफ्रारेड थर्मल गन और 2517 वीटीएम किट हैं। यदि पांच जांच केंद्र पूरी क्षमता से काम करें, तो इतने वीटीएम किट पांच दिन में ही खत्म हो जाएंगे। इलाज की व्यवस्था में भी झारखंड अच्छी स्थिति में नहीं है। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए 206 अस्पतालों में साढ़े सात हजार सामान्य बेड और आठ हजार के करीब आइसीयू बेड का इंतजाम किया गया है। करीब 29,00 आइसोलेशन बेड भी हैं। राज्य में आज की तारीख में मात्र 206 वेंटिलेटर हैं, और 340 के ऑर्डर दिए गए हैं।

लॉकडाउन के कारण राज्य के करीब 10 लाख प्रवासी मजदूर देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हैं। करीब आठ हजार छात्र भी कोटा और दूसरे शहरों में फंसे हैं। इतनी बड़ी संख्या में बाहर से आनेवालों के साथ संक्रमण भी आ सकता है। इससे राज्य की स्वास्थ्य मशीनरी पर कितना दबाव पड़ेगा, यह सोच कर ही डर लगता है। सीमित क्षमता के कारण उनकी जांच में भी समस्या आएगी। बाहर से आनेवालों को राज्य में व्यवस्थित करने की भी चुनौती होगी। इसके लिए सरकार को खेती पर ध्यान देना होगा, ताकि बाहर से आनेवाले मजदूरों को काम दिया जा सके। किसानों को प्रोत्साहित कर उन्हें हर किस्म की खेती के लिए तैयार करना होगा, उन्हें हर तरह की मदद करनी होगी। छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान न हो, इसके लिए कोटा जैसी व्यवस्था विकसित करनी होगी। छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों और दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर क्षेत्रों की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। इस क्षेत्र को समुचित प्रोत्साहन की भी जरूरत होगी, ताकि अर्थव्यवस्था को चलाए रखने का भार केवल ग्रामीण क्षेत्र पर न पड़े।

आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड इन परिस्थितियों का सामना किस तरह और कितना कर पाता है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही संसाधनों की कमी की बात कह चुके हैं। वह कहते हैं, "हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, हम 90 प्रतिशत केंद्र पर निर्भर हैं। हमारे लिए तो यह डबल डिजास्टर है।" भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश कहते हैं, "यह सरकार कोरोना से जंग में सही तरीके से काम नहीं कर रही, केवल बहानेबाजी कर रही है।" अब देखना है कोरोना से झारखंड कैसे निपटता है। यही हेमंत सोरेन की असली परीक्षा होगी।

प्रदेश के मजदूर और छात्र अगर लौटे तो सीमित संसाधनों से उनकी जांच कर पाना नामुमकिन होगा

पीटीआइ

सक्रियता: अधिकारियों के साथ बैठक करते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ

सराहे आगरा मॉडल ने ही खोली पोल

आगरा के मेयर की चिट्ठी और वायरल हुए वीडियो से आदित्यनाथ सरकार की कोशिशों पर फिरा पानी

लखनऊ से **कुमार भवेश चंद्र**

कहावत है कि जो जितना सराहा जाता है, कई बार वही फंदा बन जाता है। जिस आगरा मॉडल की चर्चा ऐसी हुई कि केंद्र ने कोविड-19 से निपटने के लिए उसे भीलवाड़ा, केरल मॉडल के साथ मिसाल बनाने की कोशिश की, उसकी पोल भाजपा के ही एक मेयर की चिट्ठी और एक क्वारेंटाइन केंद्र की बदइंतजामी के वायरल हुए वीडियो ने ऐसी खोली कि उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार की तमाम कोशिशों पर सवाल खड़े होने लगे। हालांकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पिछले एक महीने से लगभग हर रोज अपने सरकारी आवास पर अफसरों के साथ बैठक कर प्रदेश में कोरोना संक्रमण और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में स्वास्थ्य, राहत और अलग-अलग समस्याओं पर काम करने के लिए 11 टीमें बना रखी हैं। हर रोज होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री कोरोना पर काबू करने में आने वाली समस्याओं के हर नए पहलू पर अपनी टीम से विमर्श करते हैं, उन्हें टास्क देते हैं और पिछले टास्क की प्रगति की समीक्षा करते हैं। मुख्यमंत्री की इस सक्रियता की वजह से अफसरों के बीच सख्ती का संदेश गया है।

लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्री ने अपने नोएडा दौरे के समय न केवल वहां के डीएम बीएम सिंह को फटकार लगाई थी, बल्कि उनका तबादला भी राजस्व विभाग में कर दिया था। इससे भी अफसरों में सख्ती का संदेश गया। एक तरफ अफसरों पर सख्ती और दूसरी ओर कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री की चुस्ती ने प्रदेश की

सीमा के बाहर एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी छवि को गढ़ने का काम किया। आनंद विहार की सीमा से पैदल चलकर यूपी में दाखिल होने वाले मजदूरों को घर भेजने का सवाल हो या कोटा में फंसे प्रदेश के विद्यार्थियों से लेकर दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बस से घर वापसी की उनकी मुहिम, मुख्यमंत्री की प्रशंसा उनके विरोधी भी करने लगे। कोटा में फंसे छात्रों की वापसी के फैसले पर भी उन्हें विपक्षी नेताओं की तारीफ मिल चुकी है।

अप्रैल का आखिरी हफ्ता आते-आते आदित्यनाथ की छवि को करारा झटका दिया आगरा के एक मेयर नवीन जैन की चिट्ठी ने। नवीन जैन ने अपने जिला प्रभारी मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा को चिट्ठी लिखकर जो सवाल उठाए हैं, वह कोरोना संक्रमण से लड़ने की सरकार की तैयारियों की पोल खोलते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का केंद्र बने आगरा से उठे आरोपों के इस गुबार में यह चिट्ठी मुख्यमंत्री की सक्रियता और सख्ती दोनों पर सवाल उठाती है। इस चिट्ठी के बाद विपक्षी नेताओं ने भी योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना पर काबू पाने में सरकारी कोशिशों को कटघरे में खड़ा कर दिया है।

नवीन जैन ने साफ तौर पर कहा है कि आगरा चीन का वुहान बनने की कगार पर खड़ा है। शहर के हॉट स्पॉट में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में न तो समय से टेस्ट कराए जा रहे हैं, न ही वहां लाए गए मरीजों को समय से खाना-पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। नवीन ने यह भी लिखा है कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की 'डोर स्टेप डिलीवरी' के दावे भी फेल साबित हुए। जरूरी सामान की कालाबाजारी का आरोप भी उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर मढ़ दिया है।

ये सब ऐसे सवाल हैं, जो मुख्यमंत्री की रोज-ब-रोज होने वाली बैठकों की चिंताओं और दावों का उपहास उड़ाते हैं। ये सवाल अगर विपक्षी दल के नेताओं की ओर से उठाए जाते तो मुमकिन है कि उन्हें राजनैतिक मानकर भुला दिया जाता। लेकिन नवीन आगरा में भाजपा के कार्यकर्ता और मेयर हैं। इतना ही नहीं, वे अपने शहर के मेयर होने के साथ ही भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता डॉ. चंद्रमोहन आगरा के मेयर की शिकायत को एक जनप्रतिनिधि के नाते उनकी चिंता बताते हैं। डॉ. चंद्रमोहन कहते हैं, "आगरा में बड़ी संख्या में तबलीगी जमात के आयोजन से लौटे लोगों का आवागमन हुआ, जिसके कारण वहां संक्रमण बहुत तेजी से फैला। इस वजह से वहां इस समस्या ने बड़ा रूप धारण किया। आगरा के जनप्रतिनिधि होने के नाते वहां के मेयर ने जो चिंता जताई, उसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और स्थिति को संभाला है। अब वहां स्थितियां काफी हद तक नियंत्रण में हैं।"

सरकारी उपेक्षा: आगरा के क्वारेंटाइन केंद्र में पैकेट फेंकते कर्मचारी का नजारा

हालांकि आगरा निवासी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय कहते हैं, "आगरा या पूरे देश में इस संक्रमण का जो विस्तार है, उसे लेकर मेरा नजरिया बिलकुल अलग है। मैं इसे इतना गंभीर नहीं मानता कि इसके लिए सबको घरों में बंद कर दिया जाए। मैं तो शुरू से ही लॉकडाउन के विरोध में हूं। इसकी जरूरत ही नहीं थी। आगरा के एक क्वारेंटाइन केंद्र में आज कोरोना के मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की जो तसवीरें सामने आ रही हैं, वे जरूर प्रशासनिक अदूरदर्शिता का नतीजा हैं।" राय उस वीडियो का जिक्र करते हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण के शक में क्वारेंटाइन सेंटर में लाए गए लोगों का हाल दिखाया गया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि क्वारेंटाइन सेंटर के गेट पर पानी की बोतलों को पैकिंग समेत गेट पर छोड़ दिया गया है और कथित रूप से कोरोना संक्रमित लोग गेट की जालियों से हाथ निकालकर उन्हें लेने की होड़ करते दिख रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री की टीम इलेवन इतने कम संख्या में मरीजों को हैंडल कर पाने में इस कदर लाचार दिख रही है तो इस संख्या के विस्फोट होने पर क्या हालात हो सकते हैं। घटना के बाद सरकार ने आगरा के बीडीओ मनीष वर्मा को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सवाल सिर्फ मरीजों के साथ दुर्व्यवहार या क्वारेंटाइन सेंटर की अव्यवस्थाओं का ही नहीं है। गोपामऊ के भाजपा विधायक श्याम प्रकाश मेडिकल उपकरण और सामान खरीदने के लिए विधायक निधि से दिए गए 25 लाख रुपये वापस मांग रहे हैं। इसके लिए श्याम प्रकाश ने हरदोई के मुख्य विकास अधिकारी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। उनका आरोप है कि इस तरह के सामान की खरीद में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।

अप्रैल का आखिरी हफ्ता आते-आते आदित्यनाथ की छवि को करारा झटका दिया आगरा के एक मेयर नवीन जैन की चिट्ठी ने

आदित्यनाथ सरकार का प्रशासन एक तरफ अपने ही पार्टी के लोगों के निशाने पर है, तो दूसरी ओर विपक्षी नेता भी सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं, "चाहे पीपीई का मामला हो या वेंटिलेटर, आइसीयू की व्यवस्था का सवाल, सभी मामलों में सूबे की यह सरकार पूरी तरह फेल है। कोई बताएगा कि आगरा में क्वारेंटाइन किए गए लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है।" सवाल यह भी है कि आगरा मॉडल को केंद्र सरकार भी बेहतर बता रही थी, उसकी खामियां उजागर होने के बाद योगी सरकार दोहरे संकट में आ सकती है।

संक्रमण का ग्राफ स्थिर करने में सफल

राजस्थान में कोरोना से अब तक (27 अप्रैल) 2328 लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 51 लोगों की मौत हो गई है। संक्रमण रोकने में राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश में चर्चा हुई, लेकिन फिर भी कई जगहों पर स्थिति गंभीर है। कोरोना की लड़ाई में राज्य की क्या तैयारी है, इस पर आउटलुक *के सवालों का चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव* **रोहित कुमार सिंह** *ने जवाब दिया है। पैश हैं अंश:*

राजस्थान उन राज्यों में है, जहां सबसे पहले कोरोना के मामले सामने आए, लेकिन दो महीने से स्थिति संभल नहीं रही है?

राजस्थान में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज दो मार्च को पाया गया था। उसके बाद राजस्थान देश में पहला राज्य था, जिसने लॉकडान की शुरुआत की। भीलवाड़ा मॉडल देश के सामने आया। आज राजस्थान देश में प्रति दस लाख जनसंख्या में सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य है। सरकार के इन्हीं प्रयासों के कारण राजस्थान कोरोना वायरस के ग्रोथ ग्राफ को स्थिर (फ्लैट) करने में सफल रहा है।

अभी तक कितने हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान हुई है और उनकी क्या स्थिति है?

राजस्थान में अभी तक 18 जिलों में 2,061 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। सभी जगहों पर कर्फ्यू लगाकर तेजी से लोगों की पहचान की गई। अब सभी हॉटस्पॉट के पॉजिटिव पाए गए केस निगेटिव होते जा रहे हैं।

भीलवाड़ा मॉडल एक सफल उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाए गए?

भीलवाड़ा में काफी आक्रामक रूप से और बहुत कम समय में संक्रमित मामलों की पहचान और आइसोलेशन का काम किया गया। परिणाम देश के सामने है। यही उपाय पूरे राज्य में अपनाकर राजस्थान ने कोरोना वायरस के नियंत्रण में सफलता पाई।

केंद्र सरकार कह रही है कि जयपुर क्षेत्र काफी संवेदनशील बन गया है, यहां पर भीलवाड़ा मॉडल क्यों सफल नहीं हो पा रहा है?

जयपुर के रामगंज में अब कोरोना संक्रमण थम गया है। टेस्ट सैंपल ज्यादातर निगेटिव आ रहे हैं। शुरुआती दौर में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण परेशानी आई। क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था, ज्यादा से ज्यादा आर-पीसीआर टेस्ट और कठोर निगरानी से रामगंज अब सुरक्षित है।

राज्य में कोविड अस्पतालों, बेड और वेंटिलेटरों की क्या स्थिति है?

राज्य में त्रिस्तरीय मॉडल अपना गया है। इसके तहत 63 कोविड हेल्थ केयर, 52 हेल्थ सेंटर और 56 कोविड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। साथ ही पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर, पीपीई किट्स और मास्क की व्यवस्था कर ली गई है।

राज्य में टेस्टिंग को लेकर क्या रणनीति है?

राज्य में दो तरह की टेस्टिंग की जा रही है। पहले, सभी जिलों में एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस के जरिए कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा रहा है। दूसरे स्तर पर कोरोना कंटेनमेंट स्ट्रैटजी के तहत हॉटस्पॉट में चिन्हित व्यक्तियों की जांच की जा रही है। राजस्थान में आरटी-पीसीआर से रोजाना 5,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। जल्द ही इसकी संख्या बढ़कार 10 हजार टेस्ट कर दी जाएगी।

लॉकडाउन का उद्देश्य संक्रमण को रोकना और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तैयारी करना था। उसमें सफल रहे, अब धीरे-धीरे ढील के लिए तैयार हैं।

लॉकडाउन को क्या अभी आगे बढ़ाया जाना चाहिए या फिर इसमें ढील देनी चाहिए।

लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकना और सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को संभालने के लिए तैयार करना था। सरकार अपने उद्देश्यों में सफल रही है। अब सरकार लॉकडाउन में ढील देने के लिए तैयार है।

कई राज्य राजस्थान में फंसे छात्रों को वापस बुला रहे हैं, क्या इससे संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है?

विभिन्न राज्य सरकारों ने राजस्थान में पढ़ रहे छात्रों को वापस बुलाया है। इन सभी छात्रों का टेस्ट किया जाएगा और उन्हें 14 दिन क्वारेंटाइन में रखा जाएगा, उसके बाद परिवार के पास भेजा जाएगा। इसलिए इनसे संक्रमण का खतरा नहीं है।

इस दौर में कोविड-19 के अलावा दूसरे मरीजों का इलाज भी बड़ी चुनौती बन गया है, इसके लिए राज्य कितना तैयार है?

कोरोना संक्रमण वाले मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण दूसरे मरीजों के अस्पताल में आने पर खतरा बना हुआ था। सरकार ने इस चिंता को तुरंत दूर करते हुए सभी जगह अलग कोविड अस्पताल चिन्हित कर दिए। अब सभी मरीज बिना किसी भय के इलाज करवा सकते हैं। हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।

नैनो मंत्रिमंडल : राज्यपाल लालजी टंडन और शिवराज सिंह नए मंत्रियों के साथ

कैबिनेट में दिखा शिवराज-सिंधिया का कद

सत्ता के नए समीकरणों को देखते हुए मुख्यमंत्री को कितना फ्री हैंड मिल पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है

रवि भोई

कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ लेने के 29 दिन बाद मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन जैसा वे चाहते थे, वैसा मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। पांच लोगों के मंत्रिमंडल में दिल्ली के नेताओं की छाप ज्यादा दिखाई पड़ रही है। इस मंत्रिमंडल से आने वाले दिनों में शिवराज सिंह को कितना फ्री हेंड मिलेगा, यह भी बड़ा सवाल है। मंत्रिमंडल के आकार और चेहरे से लगता है शिवराज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भी नाप दिया गया। साथ ही पिछले 15 साल तक राज्य के बड़े चेहरे रहे भाजपा नेताओं को हैसियत दिखा दी गई। सिंधिया मंत्रिमंडल में कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे अपने छह विश्वस्तों को मंत्री और एक को उप मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे। यह उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें दो लोगों से ही संतोष होना पड़ा। कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग दे दिया गया, उनके पुराने अनुभव का लाभ लेना भी शिवराज ने जरूरी नहीं समझा, जबकि सिलावट कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री से मिलकर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए लंबा सुझाव दे आए थे। कांग्रेस सरकार में मलाईदार परिवहन और राजस्व विभाग की कमान संभाल चुके गोविंद राजपूत को खाद्य-नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई।

एक बात साफ है कि सिंधिया की मांग के कारण मंत्रिमंडल गठन टल रहा था और सहमति नहीं बन पा रही थी। अन्यथा 23 मार्च को मुख्यमंत्री के साथ कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। इससे कांग्रेस को ऊंगुली उठाने का भी मौका भी नहीं मिलता। मंत्रिमंडल को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल अभियान के कारण भाजपा हाईकमान ने छोटा

मंत्रिमंडल बनाकर उसे चुप करा दिया साथ ही कई संकेत भी दे दिए। ब्राम्हण चेहरे गोपाल भार्गव कांग्रेस राज में नेता प्रतिपक्ष थे, फिर भी उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। ब्राम्हण नेता नरोत्तम मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल कर नंबर दो का दर्जा देकर हाईकमान ने अपने विश्वस्त पर ज्यादा भरोसे की रणनीति अपनाई। नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह के करीबी होने के साथ उनके आपरेशन लोटस में अहम भूमिका निभा चुके हैं। कहा जाता है नरोत्तम मिश्रा को अमित शाह अपने कार्यकाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन तब मुख्यमंत्री शिवराज के विरोध के कारण मिश्रा पीछे हो गए और शाह को जबलपुर के सांसद राकेश सिंह के नाम पर मुहर लगानी पड़ी। 22 विधायकों के दल-बदल के बाद मुख्यमंत्री की दौड़ में शिवराज और अन्य नेताओं के साथ नरोत्तम भी थे, लेकिन भाजपा हाईकमान ने राज्य में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए पुराने खिलाड़ी शिवराज पर ही दांव लगाया। पर मंत्रिमंडल से लग रहा है कि हाईकमान ने लगाम अपने पास ही रखी है।

नरोत्तम मिश्रा को गृह और स्वास्थ्य-परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। वर्तमान कोरोना संक्रमण से निपटने में गृह और स्वास्थ्य विभाग की ही अहम् भूमिका है। कहा जा रहा है कि नरोत्तम को पहले स्वास्थ्य विभाग ही दिया जा रहा था, उन्होंने हाईकमान से दबाव बनवाकर गृह विभाग भी ले लिया। गौरतलब है कि कमलनाथ के राज में ई-टेंडरिंग मामले में गड़बड़ी के आरोप में नरोत्तम मिश्रा के निजी सचिवों के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने कार्रवाई की थी।

कमल पटेल को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का करीबी माना जाता है। मध्यप्रदेश की राजनीति में शिवराज और कैलाश विपरीत ध्रुव जैसे हैं, तो कुछ मौकों पर कमल पटेल भी शिवराज के खिलाफ खड़े दिखाई दिए। साफ है कि हाईकमान की सहमति के बैगर पटेल न तो मंत्री बन पाते न उन्हें कृषि और किसान कल्याण जैसा बड़ा विभाग मिल पाता। मीना सिंह के नाम ने सबको चौंकाया। कमलनाथ सरकार में मंत्री न बन पाने से दुखी बिसाहूलाल सिंह ने मंत्री बनने लिए ही कांग्रेस से बगावत की थी। कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता और कई बार मंत्री रहे बिसाहू लाल की जगह उमरिया की आदिवासी विधायक मीना सिंह को मंत्री बना दिया गया। मीना सिंह को संघ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा की पसंद बताया जा रहा है। मीना सिंह को आदिमजाति कल्याण मंत्री बनाया गया है।

मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की जब भी बात चली मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खास पांच पूर्व मंत्रियों के नाम चर्चा में जरूर रहे- पूर्व गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व कृषि एवं सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन, पूर्व ऊर्जा एवं खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह तथा पूर्व पीएचई मंत्री रामपाल सिंह। कल्पना भी नहीं की जा रही थी कि शिवराज का मंत्रिमंडल बनेगा और उसमें ये नहीं होंगे। इनमें से किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। कहा जाता है कि ये नेता 13 साल तक शिवराज की छाया की तरह रहे। अपने लोगों को कैबिनेट में जगह न दिलाने को पार्टी में शिवराज की पकड़ कमजोर होने के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे गोपाल भार्गव मंत्री तक नहीं बन पाए। इस झटके से स्वाभाविक तौर पर भार्गव खुश नहीं होंगे। भार्गव का सम्मान बरकरार रखने के लिए कुछ लोग उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए चला रहे हैं। वैसे छोटे मंत्रिमंडल में जगह न मिल पाने से नाराज विधायकों से प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने बात की है और अगले विस्तार में मंत्री बनाने का भरोसा दिलाया है।

विस्तार कब होगा, यह तय नहीं है। लॉकडाउन खुलने या फिर उपचुनाव के बाद। सिंधिया का जोर इस बात पर है कि उनके 7-8 लोग मंत्री के तौर पर उपचुनाव में जाएं, जिससे जीत में मदद मिले। बिसाहूलाल सिंह, एदलसिंह कंसाना, राजवर्धनसिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग भी मंत्री पद की चाह में कांग्रेस छोड़कर भाजपा आए हैं। सवाल है कि भाजपा कितने गैर विधायकों को मंत्री बना सकती है। अभी तो दो मंत्री पद मिला है, लेकिन इससे ज्यादा होते हैं तो कांग्रेस अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। भोपाल के एडवोकेट जेपी. धनोपिया कहते हैं, "विधायकी छोड़ने वालों को मंत्री बनाना लोकतंत्र की हत्या है। संविधान में गैर विधायकों को मंत्री बनाने की सीमा भले ही तय नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने की प्रत्याशा में कितनों को मंत्री बनाया जा सकता है?" भाजपा के पास अभी 107 विधायक हैं। 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए उसे दस और विधायकों की जरूरत है। इसलिए भाजपा सिंधिया की शर्तों को ज्यादा भाव नहीं दे रही है। भाजपा सिंधिया के दबाव में रहती तो तय था कि मंत्रिमंडल का आकर बड़ा होता और कांग्रेस से भाजपा में आए दस लोग मंत्री बन जाते।

तुलसी सिलावट के उप मुख्यमंत्री न बनने को सिंधिया के हथियार डालने के रूप में देखा जा रहा है। फिर भी सिंधिया अपने वजूद को बचाए रखने के लिए चंबल-ग्वालियर संभाग की अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में डालना चाहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज कह रहे हैं, "कोरोना संकट से निपटने के बाद विस्तार में और लोगों को मौका दिया जायएगा।" भाजपा हाईकमान ने छोटे मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधकर सिंधिया-शिवराज की आंखों का चश्मा हटा दिया है। अब शिवराज को नरोत्तम की पीठ पर बैठकर कोरोना की जंग लड़नी होगी। नरोत्तम के पास गृह और स्वस्थ्य दोनों विभाग है। अब देखना है कि वे शिवराज को पटकते हैं या साथ लेकर आगे बढ़ते हैं।

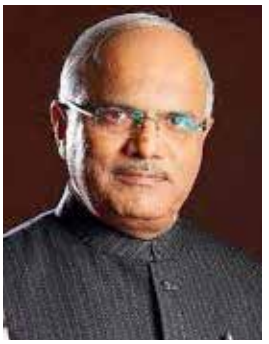

आपात स्थिति को ध्यान में रखकर यह मंत्रिमंडल बनाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त की हैं। आगे विस्तार में और लोगों को मौका दिया जाएगा। पार्टी में किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है

विनय सहस्त्रबुद्धे
मध्य प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा

भाजपा ने प्रदेश की जनता के साथ मजाक किया है। मंत्रिमंडल के गठन से ही इनके संघर्ष की वास्तविकता सामने आ चुकी है। आज जिनकी आवश्यकता थी, वो नदारद और जो संकट में भाग खड़े हुए वो अंदर हैं

कमलनाथ
पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

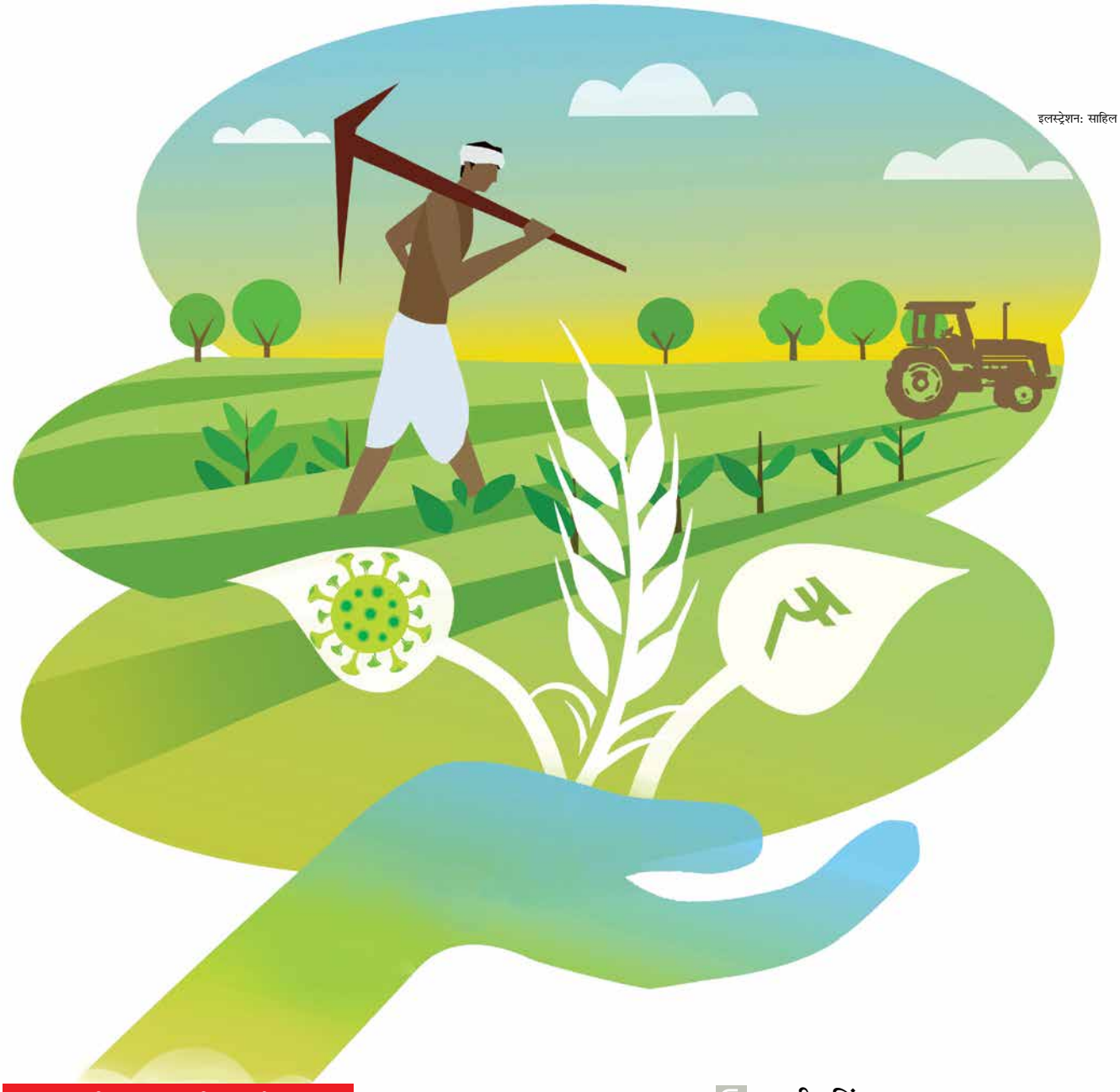

इलस्ट्रेशन: साहिल

पटरी पर वापसी/आलेख

कैसे रफ्तार पकड़े जिंदगी

ग्रामीण भारत में है 'इंडिया' की सेहत सुधारने का फॉर्मूला, फौरी राहत और कृषि को मजबूत करना होगा सार्थक विकल्प

हरवीर सिंह

दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के चलते भयावह आर्थिक मंदी दस्तक दे रही है। आशंका है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पांच फीसदी तक सिकुड़ सकती है और उसे पटरी पर लाने के लिए दुनिया की बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने बड़े स्टिमुलस पैकेज घोषित कर दिए हैं। अमेरिका का स्टिमुलस पैकेज तो हमारी अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर पहुंचने वाला है। चीन, जापान, जर्मनी और यूरोपीय संघ के

कई अन्य विकसित देशों के पैकेज भी काफी बड़े हैं। भारत में तो सबसे सख्त लॉकडाउन के पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की सांसें थम-सी गई हैं लेकिन सरकार से किसी सार्थक पैकेज का इंतजार ही चलता रहा है। सरकार लॉकडाउन खोलने का कोई पुख्ता प्लान लेकर आए तो आर्थिक गतिविधियां फिर शुरू हो पाएं।

फिलहाल सरकार ने जो कुछ ढील दी है, उससे लगभग न के बराबर ही गतिविधियां शुरू हो सकी हैं। कई स्वास्थ्य एक्सपर्ट और नीतिगत विशेषज्ञ एकमत हैं कि लॉकडाउन से देश में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में मदद मिली है। हालांकि मरीजों की संख्या और मौतें बढ़ रही हैं। अलबत्ता, कुछ राज्यों की बेहतर रणनीति और कामकाज के चलते मरीजों की संख्या घटी है और हालात सुधर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन खोलने या सीमित करने पर बहस बढ़ गई है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय तक बंदी झेलने की स्थिति में नहीं है। बंद हो रहे कारोबार और बेरोजगारी के स्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते वैश्विक संस्थाएं भारत में गरीबी में भारी इजाफे और भुखमरी बढ़ने की भयावह आशंकाएं जता रही हैं।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की रणनीति आखिर क्या है? बिना किसी बड़े स्टिमुलस पैकेज के अभी इसका जवाब नहीं मिल रहा है और न ही सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रणनीति या एक्शन प्लान सामने आ पाया है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकार की चुनौती जहां बाजार में मांग बनाए रखना है, वहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया कराना है। इसमें कोई शक नहीं है कि मैन्यूफैक्चरिंग और सर्विस क्षेत्र में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है। इनमें सरकार की कोशिश गिरावट को कम करना ही हो सकती है क्योंकि 40 दिन के लॉकडाउन में इन दोनों क्षेत्रों में 80 से 90 फीसदी गतिविधियां बंद-सी रही है। मांग के बिना ये उद्योग शुरू भी नहीं हो पाएंगे। कोई भी ऑटो कंपनी आने वाले दिनों में कारों और दुपहियों की बिक्री की संभावना के आधार पर ही उत्पादन करेगी। यही स्थिति व्हाइट गुड्स से लेकर गारमेंट और दूसरे मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्रों की है। असल में उद्योग जगत सरकार से लगातार मांग कर रहा है कि उसे पटरी पर लाने के लिए सीधे पैकेज दिया जाए।

सरकारी पहल का हिसाब

सरकार के अभी तक मोटे तौर पर दो कदम ही सामने आए हैं। एक, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है क्योंकि इस पैकेज का बड़ा हिस्सा पहले से ही बजट प्रावधानों में शामिल है। मसलन, सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त में करीब 17 हजार करोड़ रुपये दिये हैं, जो पहले से जारी योजना का हिस्सा हैं। इसी तरह, मनरेगा में पहले का बकाया और नए साल में भुगतान के लिए अग्रिम पैसा राज्यों को दिया है। दूसरे, जनधन खातों में पांच सौ रुपये जमा करने और उज्ज्वला योजना के लिए सिलेंडर देने के साथ कमजोर वर्ग की पेंशन का भुगतान और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अतिरिक्त पांच किलो अनाज देने का फैसला किया है। लेकिन इसे नाकाफी बताया जा रहा है।

उद्योग को कैसी राहत

उद्योग के लिए एक बड़े पैकेज की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है जिसका आकार छह से सात लाख करोड़ रुपये होना चाहिए। अमेरिका और दूसरे देशों ने बड़े, मझोले और छोटे उद्योगों के लिए बड़े पैकेज घोषित किये हैं जिनमें कर्मचारियों को नौकरी पर बरकरार रखने के लिए वेतन का पैसा, कॉरपोरेट बांड्स की खरीद और सस्ते कर्ज शामिल हैं। लेकिन हमारी सरकार अभी इस पर चुप्पी साधे हुए है। मंत्रियों के समूह अभी इस बात को लेकर परेशान हैं कि उद्योगों को मिलने वाले पैकेज का हिसाब कैसे रखा जाए कि वह जरूरतमंद तक पहुंचा है या नहीं। लेकिन 24 अप्रैल को फ्रैंकलिन टैंपल्टन ने अपनी म्यूचुअल फंड की छह स्कीम बंद की, तो पूरे म्युचुअल फंड क्षेत्र पर संकट खड़ा होने की आशंका पैदा होने के दो दिन बाद रिजर्व बैंक ने 50 हजार करोड़ रुपये की लिक्विडिटी इस क्षेत्र को देकर कुछ अनिश्चितता कम करने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से भारतीय पूंजी बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पैसा निकाला है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था की कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है और फ्रैंकलिन टैंपल्टन प्रकरण इसकी एक आहट है। जो तत्परता 2008 के वित्तीय संकट के समय दिखी थी, वह गायब दिख रही है। तमाम अर्थशास्त्रियों का मत है कि सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़कर बड़े राहत पैकेज का ऐलान करना चाहिए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत तरलता बढ़ाने के कदमों की सीमाएं हैं क्योंकि संकट मांग का है जिसमें घरेलू और वैश्विक दोनों हैं। जरूरत से अधिक संरक्षणवादी रवैया भी देश की अर्थव्यवस्था के हित में नहीं है।

कृषि संकट और संभावनाएं

लेकिन उद्योगों से अधिक इस मौके पर जरूरत कृषि और किसान की सुध लेने की है क्योंकि उसमें मांग और खपत बढ़ाने की क्षमता है। फिर, खाद्यान्न, फलों, सब्जियों, डेयरी और प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के ट्रेड को देखें तो यह जीडीपी के 20 फीसदी को पार कर जाता है। जाहिर है, ऐसे में केवल कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जहां गतिविधियां सामान्य बनी रही हैं। पिछले पांच साल में कृषि और सहयोगी क्षेत्र की वृद्धि दर 3.5 से पांच फीसदी के बीच रही है। तमाम प्रतिकूल स्थितियों

कैसी हो पहल: **वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य**

खरीद का संकट: मध्य प्रदेश के जबलपुर में गेहूं खरीद का मंडी में इंतजार करते किसान

और बीमारी के संक्रमण की आशंका के बावजूद रबी फसलों की हार्वेस्टिंग जोरों पर है और गेहूं की कटाई अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। असली चुनौती इसके विपणन की है। गेहूं की सरकारी खरीद के लिए कुछ राज्यों ने अधिक तैयारी की है तो कुछ राज्यों में हालात बेहतर नहीं हैं। उम्मीद है कि करीब 11 करोड़ टन गेहूं की उपज में करीब 350 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद होगी। अगर सरकारी एजेंसियां बेहतर काम करती हैं और संकट के इस दौर में किसानों के हितों के संरक्षण का जिम्मा ठीक से उठाती हैं तो यह आंकड़ा पार भी हो सकता है क्योंकि मौजूदा हालात में गेहूं में प्राइवेट ट्रेड लगभग न के बराबर रह गया है और तकरीबन पूरा मार्केट सरप्लस सरकारी खरीद में ही आएगा। ऐसे में सरकार की कोशिश बिचौलियों पर अंकुश लगाकर किसानों को उपज का पूरा दाम दिलाना होनी चाहिए।

हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में स्थिति बेहतर है लेकिन सबसे अधिक गेहूं पैदा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। वहां सरकारी एजेंसियों यूपी एग्रो और यूपी उपभोक्ता सहकारी संघ के पास मैनपावर और ढांचागत सुविधाएं न होने के चलते प्राइवेट आढ़तियों को खरीद प्रक्रिया में शामिल किया जाना किसानों के लिए हितकर नहीं है। राज्य सरकार यह आश्वस्त नहीं कर पाती है कि किसानों का गेहूं 1925 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ही खरीदा जाए। पिछले अनुभव हैं कि आढ़तियों ने किसानों को पूरा एमएसपी नहीं दिया लेकिन सरकार से पूरी कीमत हासिल की। इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का जिम्मा राज्य सरकार का है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें एमएसपी पर गेहूं की खरीद को सुनिश्चित कर पाती हैं तो किसानों के हाथ में करीब 70 हजार करोड़ रुपये की आय होगी। यह पैसा आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने में मदद करेगा।

इसके साथ ही दालों और तिलहन की सरकारी खरीद अगर एमएसपी पर हो जाती है तो किसानों के लिए बेहतर होगा। इस साल करीब 230 लाख टन दालों की पैदावार का अनुमान है जो देश की जरूरत के लगभग बराबर है। इससे आयात पर निर्भरता काफी कम हो गई है। तीसरी चुनौती तिलहन फसलों की है। सरकार को संकट के इन दिनों में किसानों को आश्वस्त करना चाहिए कि तिलहन की पूरी खरीद एमएसपी पर होगी। साथ ही सरकार अगर आगामी खरीफ सीजन के लिए तिलहन फसलों के एमएसपी में ज्यादा बढ़ोतरी करने के साथ देश में खाद्य तेलों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए सीमा शुल्क दरों में इजाफा करती है तो देश में खाद्य तेलों के करीब 70 हजार करोड़ रुपये के सालाना आयात को रोका जा सकेगा। यह पैसा देश की कृषि अर्थव्यवस्था में इजाफा कर सकेगा। साथ ही डेयरी और पॉल्ट्री जैसे उद्योगों को बेहतर प्रोटीनयुक्त फीड की उपलब्धता बढ़ेगी। पिछले कुछ बरसों में दालों के मामले में यह रणनीति कामयाब रही है।

कृषि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा गन्ना और चीनी का उत्पादन है। इस साल देश में चीनी के उत्पादन में करीब 60 लाख टन की गिरावट के बावजूद उत्पादन देश की कुल खपत करीब 250 लाख टन के आसपास रहेगा। इसके अलावा करीब 100 लाख टन का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद है जो वैश्विक स्तर पर मांग की अधिकता और कम उत्पादन के चलते निर्यात आय का बड़ा साधन बन गया है। इसके साथ ही चीनी उद्योग सालाना 190 करोड़ लीटर एथनॉल का उत्पादन कर रहा है जो पेट्रोल में ब्लैंडिंग की दस फीसदी की जरूरत से तो कम है लेकिन पांच फीसदी के काफी करीब है। यह चीनी उद्योग के लिए आय का बड़ा स्रोत बनता जा रहा है। कोविड-19 महामारी के इस दौर में जब सेनिटाइजर की जरूरत बढ़ी तो सरकार की अनुमति के बाद चीनी मिलों ने तुरंत करीब नौ लाख लीटर प्रति माह की उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। हालांकि बिहार ऐसा राज्य है जिसने चीनी मिलों को सेनिटाइजर बनाने की अनुमति नहीं दी है।

जाहिर है, कोविड-19 और उसके बाद के दौर में दुनिया और जीवन-शैली बदल सकती है इसलिए सेनिटाइजर चीनी मिलों के लिए एक नये रेवन्यू स्रोत के रूप में बना रहेगा। इसके पहले शराब और बिजली बनाने का काम भी चीनी मिलें कर रही हैं लेकिन इसका फायदा किसानों के साथ साझा करने में उन्हें अभी भी परहेज है। यही वजह है कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 15 हजार करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। उद्योग के सूत्रों के मुताबिक, 22 अप्रैल को बकाया भुगतान 12 हजार करोड़ को पार कर गया था लेकिन यह राशि गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के बाद देयता के आधार पर है। इसलिए इसमें आठ अप्रैल के बाद की आपूर्ति और भुगतान के अंतर के आधार पर सही आकलन किया जा सकेगा।

कोविड महामारी के चलते चीनी उद्योग के लिए भी एक बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट के चलते वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें जून, 2008 के स्तर पर पहुंच गई हैं और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री गिरने के चलते पेट्रोलियम कंपनियों की एथनॉल खरीदने में रुचि कम हो रही है। दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री पर प्रतिबंध

उद्योगों से अधिक इस मौके पर जरूरत कृषि और किसान की सुध लेने की है क्योंकि उसमें मांग और खपत बढ़ाने की क्षमता है

थमी रफ्तार: निर्यात और आवाजाही रुकी तो बंदरगाहों पर जमा सामान

है। ऐसे में किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सरकार को पैकेज लाने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि चीनी के निर्यात के रास्ते भी अब तंग हो रहे हैं। इसलिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

उधर, दूध, फल, सब्जी, मीट और पॉल्ट्री जैसे कृषि और सहयोगी क्षेत्रों के उत्पादों को लॉकडाउन की भारी मार से गुजरना पड़ रहा है। मांग घटने और ट्रांसपोर्ट तथा भंडारण की समस्या के चलते इन उत्पादों के किसानों को पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान की आशंका है लेकिन यह भी सच है कि लॉकडाउन समाप्त होने पर ये क्षेत्र तेजी से पटरी पर आ जाएंगे।

कृषि उपज निर्यात की संभावनाएं

इस रबी मार्केटिंग सीजन के अंत में केंद्रीय पूल में खाद्यान्न स्टॉक 900 लाख टन को पार कर सकता है। एक अप्रैल को केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का भंडार 738.5 लाख टन था जो बफर स्टॉक के तय मानकों से साढ़े तीन गुना है। इसलिए गेहूं की खरीद के बाद यह अभी तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। यह देश के लिए एक बेहतर मौका लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां यह भंडार सरकार को महामारी के संकट के दौर में खाद्यान्न उपबलब्धता की किसी भी तरह की चिंता से मुक्त करता है वहीं भारत को दुनिया की फूड फैक्टरी के रूप में रणनीति बनाने के लिए मौका दे रहा है। असल में खाद्यान्न, चीनी, दूध के उत्पाद, फल, सब्जियों और मीट प्रॉडक्ट की एशियाई और अफ्रीकी देशों में जबरदस्त मांग है और हमारे पास इनके निर्यात के लिए उत्पाद उपलब्ध हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार को एक समग्र निर्यात नीति बनाने के साथ ही कोटा, परमिट और राजनीति को किनारे रखकर काम करना होगा। अगले दो साल में कृषि उत्पादों के निर्यात को 2018-19 के 38.7 अरब डॉलर से बढ़ाकर कम के कम 80 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय करके काम करना चाहिए।

जीडीपी और कृषि

महामारी के बावजूद दो बातें होने वाली हैं। एक तो कृषि और सहयोगी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का अकेला ऐसा क्षेत्र होगा जो वृद्धि दर बरकरार रखेगा, बशर्ते सरकार किसानों को उनके उत्पादों की सही कीमत सुनिश्चित कर सके। दूसरे, अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के सिकुड़ने से जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी मौजूदा 14 फीसदी से बढ़ जाएगी और ऐसा कई दशकों में पहली बार होगा। इसलिए जहां संभावनाएं बेहतर हैं, पहले सरकार को उस क्षेत्र पर फोकस करना चाहिए।

क्या करे सरकार

सरकार मनरेगा में सालाना करीब 80 हजार करोड़ रुपये खर्च करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस साल यह खर्च बढ़ सकता है। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो खर्च होगा, वह भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाएगा। बेहतर होगा कि सरकार जल्दी ही कृषि क्षेत्र के लिए एक राहत पैकेज घोषित कर दे जिसमें कम से कम एक साल तक ब्याज मुक्त ऋण और बाजार हस्तक्षेप योजनाओं के तहत किसानों की आय को बेहतर किया जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि को दोगुना करने की राय तमाम विशेषज्ञ दे रहे हैं। असल में यह रणनीति सरकार और देश की अर्थव्यवस्था के लिए 'लो हैंगिंग फ्रूट' की तरह साबित होगी, जो जल्दी परिणाम दे सकती है। सामान्य मानसून का अनुमान आ चुका है और अगले त्यौहारी सीजन के पहले बेहतर खरीफ की फसल की संभावना भी बन गई है। ऐसे में रबी और खरीफ के ये दो बंपर सीजन अर्थव्यवस्था के बूस्टर का काम कर सकते हैं। इसके चलते मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के उत्पादों के लिए मांग बेहतर हो सकती है, जो वहां क्षमता के बेहतर उपयोग और रोजगार सृजन में मददगार होगी।

कोविड-19 महामारी के इस दौर में यह बात साफ हो गई है कि उदारीकृत और ग्लोबलाइज्ड अर्थव्यवस्था अभी भी देश की करीब 90 फीसदी असंगठित श्रम शक्ति को यह भरोसा नहीं दिला पाई है कि संकट में सेवा और मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र और शहरी इलाके इनको स्थायित्व देते हैं। लॉकडाउन के बाद करोड़ों गरीब श्रमिक अपने गांवों को कूच करते सड़कों पर दिखे। उसकी तसवीरें और वीडियो लोगों के जेहन में दशकों तक रहेंगे, जो देश की कमजोरी के सबूत की तरह हैं। इन लोगों का बोझ भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही झेलना है इसलिए वहां ज्यादा संसाधन खर्च करने की जरूरत है।

बेहतर होगा कि सरकार जल्दी इस हकीकत को समझे कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में भारत यानी कृषि और ग्रामीण क्षेत्र सबसे अहम भूमिका निभाने की स्थिति में है और उसी आधार पर लॉकडाउन खोलने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की रणनीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या करती है, यह देखना होगा।

पैकेज देने में कोताही घातक

हर ओर यही मांग कि ठोस राहत पैकेज ही लॉकडाउन से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकता है

प्रशांत श्रीवास्तव

आम आदमी, उद्योग जगत, राजनैतिक दल, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री सबकी जुबान पर एक ही सवाल: मोदी सरकार कब राहत पैकेज का ऐलान करेगी और क्या वह पैकेज दुनिया की बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की तर्ज पर होगा। देशव्यापी लॉकडाउन का दूसरा दौर भी खत्म हो रहा है। वजह यह कि लॉकडाउन के इन 40 दिनों में गरीब-गुरबों, रोज कमाने-खाने वाले लोगों, प्रवासी मजदूरों के आगे तो भुखमरी की हालत है, संगठित क्षेत्र के वेतनभोगी भी वेतन कटौती से मुकाबिल हैं और बड़े उद्योग भी भारी घाटे की जद में हैं। ऐसे में आर्थिक दुर्दशा मुंह बाए खड़ी है और देश का सामाजिक ताना-बाना बिखरने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन सरकार बेफिक्र लगती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लॉकडाउन के दौर की चौथी बातचीत में कहा, अर्थव्यवस्था की फिक्र की जरूरत नहीं। वैसे, अभी तक सरकार ने ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च को 22 अरब डॉलर (करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये) का जो राहत पैकेज का ऐलान किया था, उसमें नया कुछ ढूंढे ही मिलता है। बहुत सारे प्रावधान तो इस साल बजट के ही हैं, जिन्हें दोबारा पैकेज की तरह ऐलान कर दिया गया। वह भी हमारी जीडीपी का महज 0.8 फीसदी है।

इसके उलट दूसरे देशों की तत्परता और पैकेज की बानगी देखिए। अमेरिका ने जीडीपी का 10 फीसदी, जर्मनी ने 33 फीसदी, फ्रांस ने 14 फीसदी, जापान ने 19 फीसदी की राशि राहत पैकेज के रूप में दी है। यही नहीं, बांग्लादेश ने 2.5 फीसदी राशि राहत पैकेज अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दिया है। हमारे यहां उद्योग जगत, अर्थशास्त्री से लेकर राजनैतिक दल सभी 5-6 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की जरूरत बता रहे हैं। सरकार बार-बार यही संकेत देती रही है कि जल्द ही राहत पैकेज का ऐलान होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि पैकेज में हो रही देरी संकट को गहरा कर रही है। दूसरे देशों ने तो मार्च में ही विस्तृत पैकेज का ऐलान कर दिया था। अमेरिका ने 26 मार्च, जर्मनी ने 23 मार्च, बांग्लादेश ने 3 अप्रैल

सब कुछ ठप : लॉकडाउन में बंद पड़ा एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट

और जापान ने 7 अप्रैल को ऐलान कर दिया। ऐसे में सरकार की देरी पर भी सवाल उठ रहे हैं। पैकेज में देरी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम का सवाल है "सरकार या तो बहुत ज्यादा सोच रही है या फिर सोच ही नहीं रही है। मौजूदा संकट साहस भरे कदम उठाने का है। सरकार को तुरंत 5-6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का बिना समय गंवाए ऐलान कर देना चाहिए।" कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार से बड़े राहत पैकेज की मांग करते हुए कहा है, "गरीब तबके को कैश ट्रांसफर के जरिए 7500 रुपये की तुरंत सहायता दी जाए।" कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, "छोटे और मझोले उद्योग को जल्द से जल्द 2 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज देना चाहिए।"

संकट गंभीर: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी

संकट कितना गंभीर है, इसे दुनिया भर की एजेंसियों के आकलन से भी अहसास होता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक, मूडीज, फिच जैसी एजेंसियां कोरोना संकट से पहले भारत की ग्रोथ रेट 2020-21 में 5-6 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगा रही थी। उन्हीं एजेंसियों ने अब ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर दो फीसदी से लेकर 0.8 फीसदी तक कर दिया है। फिच ने इस अवधि के लिए ग्रोथ का अनुमान 0.8 फीसदी कर दिया है। उद्योग जगत के संगठन एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल अशोक सूद का कहना है, "संकट इतना गंभीर है कि सरकार को तीन लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। कर्मचारियों और श्रमिकों को वेतन की दिक्कत न आए, इसलिए सरकार की तरफ से तुरंत राहत मिलनी चाहिए। दूसरे, कंपनियों को नकदी की दिक्कत न आए, यह भी देखना चाहिए। तीसरे, मांग बढ़ाने के लिए सरकार को निवेश करना चाहिए। इन सबके लिए 200-300 अरब डॉलर के राहत पैकेज की दरकार होगी, जो जीडीपी के करीब 10 फीसदी के बराबर है। यह पैकेज दो हिस्सों में अगले 12-18 महीने में चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए।"

गहराते संकट का अहसास सरकार और सत्तारूढ़ दल को भी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने मौजूदा भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव, बिजनेस करने की लागत में कमी लाने संबंधी उपाय, कम आय वालों को वित्तीय सहायता और खासकर ठेका मजदूरों को कार्य स्थल पर आवास और उनके बच्चों के लिए स्कूल वगैरह का प्रबंध करने की नीति बनाने का सुझाव दिया है।

लॉकडाउन में श्रमिकों को हो रही दिक्कतों पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर विवेक कुमार कहते हैं, "लॉकडाउन के ऐलान से साफ है कि सरकार ने यह सोचा ही नहीं कि गरीब का क्या होगा। आखिर महानगरों के स्लम में ही 1.5-2 करोड़ लोग रहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग अपने घरों को छोड़कर शहरों में आकर अपना भेट भर रहे हैं। अचानक हुए लॉकडाउन से उनकी स्थिति काफी खराब हो गई है। उनके सामने केवल जीवन बचाने का संकट नहीं, बल्कि उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा हो गया है। साथ ही इस दिक्कत में उन्हें यह भी समझ में आ रहा है कि कैसे उनकी अनदेखी की जा रही है, जिससे भारी असंतोष पैदा हो सकता है।"

असल में देश का 90 फीसदी श्रमिक वर्ग असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिनकी आजीविका ज्यादा छोटे और मझोले उद्योग-धंधों पर टिकी है। लॉकडाउन की वजह से इस सेक्टर पर सबसे ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ा है। इसी को देखते हुए उद्योग जगत के संगठन फिक्की ने छोटे और मझोले उद्योगों (500 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाली कंपनियां) को राहत पैकेज के तहत एक साल के लिए ब्याज मुक्त और कोलैटरल फ्री लोन (बिना गारंटी लिए, दिया जाने वाला कर्ज) देना चाहिए। यह कर्ज इस शर्त पर कंपनियों को मिलना चाहिए कि वे अगले एक साल तक अपने कर्मचारियों की छंटनी न करें। इसी तरह लॉकडाउन के तहत कर्ज पर मिली मोरेटोरियम सुविधा को भी बढ़ाना चाहिए। जीएसटी सहित दूसरी टैक्स देनदारियों को अगले छह महीने तक टाल देना चाहिए। इसके अलावा कर्ज नहीं चुकाने पर गैर निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के नियमों के तहत 90 दिन की सीमा को बढ़ाकर 360 दिन करने की जरूरत है।

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट विजय कलंतरी का कहना है, "छोटे उद्योग-धंधों में ज्यादातर कामगार ऐसे हैं जिनकी कमाई रोजाना होती है। उनके पास प्रॉविडेंट फंड की सुविधा नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा पीएफ से पैसे निकालने की सुविधा का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस समय उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की जरूरत है। लॉकडाउन लंबा खिंचने से उनकी आजीविका पर संकट आ गया है। इससे छोटे और मझोले उद्योगों को करीब एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने की आशंका है। गंभीर होती स्थिति को देखते हुए सरकार को चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खत्म करना चाहिए।

एक सवाल केंद्र सरकार के खर्चों में हो रही कटौती पर भी उठ रहा है। हाल ही में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। यह रोक जून 2021 तक लागू रहेगी। इस संबंध में माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कई सारे सवाल उठाए हैं। उनका कहना है, "सरकार को गैर-जरूरी खर्चों में तुरंत कटौती करनी चाहिए। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े संकट में भी सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन जैसे गैर जरूरी प्रोजेक्ट, मूर्तियां बनाने को रोकने की बात नहीं कर रही है। जबकि इस समय उसकी प्राथमिकता महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की होनी चाहिए। इसी तरह अचानक हुए लॉकडाउन की वजह से प्रवासी श्रमिकों के सामने आजीविका और भोजन का संकट खड़ा हो गया है। जब केंद्रीय गोदामों में प्रचुर मात्रा में अनाज का भंडार है तो सरकार को हर जरूरतमंद को मुफ्त भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए।" कांग्रेस भी यह मुद्दा उठा चुकी है। साफ है कि लॉकडाउन ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गहरी चोट पहुंचाई है। ऐसे में कोविड संकट के बीच सरकार को तुरंत राहत पैकेज देकर मरहम लगाने की जरूरत है। इसमें देरी बड़े स्तर पर चोट पहुंचा सकती है।

इंटरव्यू/नरेंद्र सिंह तोमर

जितेंद्र गुप्ता

"किसान हैं पहली प्राथमिकता"

कोरोना संकट और लॉकडाउन से ठप अर्थव्यवस्था में जान डालने की कूव्वत सिर्फ खेती-किसानी और छोटे या अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों में है, इस पर तमाम आर्थिक जानकारों की राय एक जैसी है। रबी की बंपर फसल से अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलने का अनुमान है। लेकिन रबी फसलों की कटाई और खरीद-बिक्री में कई तरह की दिक्कतें हैं। मजदूरों, ढुलाई और सरकारी खरीद की किल्लतें भारी नुकसान कर सकती हैं। सरकार के कदम थोड़े बताए जा रहे हैं और राहत भी उम्मीद के अनुरूप नहीं है। इसलिए सरकार की सक्रियता ही उम्मीद इस किरण को उजाले में बदल सकती है। ऐसे में सारा दारोमदार कृषि मंत्रालय के कंधे पर है। बिना प्रचार किए काम में जुटे रहने की ख्याति वाले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री **नरेंद्र सिंह तोमर** *भरपूर उम्मीद के साथ कई कदमों और उनमें निरंतर सुधार का जिक्र करते हैं, जो सुर्खियों में अभी नहीं आ पाए हैं। संपादक* **हरवीर सिंह** *ने उनसे सरकार की प्राथमिकताओं और रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। प्रमुख अंश:*

इस साल खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है, लेकिन रबी फसलों की कटाई के समय ही कोरोना संकट और लॉकडाउन से आई परेशानी दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है?

पूरी दुनिया में फैला कोरोना संकट हमारी भी परीक्षा ले रहा है। हम बड़ी आबादी वाले कृषि प्रधान देश हैं। हमारे यहां की स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी महामारी से निपटने के लिए नाकाफी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी को सीमित करने के लिए जब लॉकडाउन की घोषणा की, उसी समय उन्होंने प्रतिकूलता का आकलन कर लिया था। कृषि क्षेत्र में भी प्रतिकूल असर का अंदेशा था। सरकार के फैसलों में कृषि क्षेत्र को पर्याप्त अहमियत दी गई। सरकार ने फसलों की कटाई के लिए किसानों और मजदूरों को लॉकडाउन से छूट दी। किसानों को फसलों का सही मूल्य दिलाने के लिए भी सरकार ने समय रहते सोचा। यही वजह है कि आवाजाही शुरू होने से पहले ही किसानों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर ली। किसानों ने अपने क्षेत्र में कोरोना योद्धा के तौर पर काम करते हुए दस-बारह दिन पहले दलहन और तिलहन फसलों की कटाई कर ली। गेहूं की भी हार्वेस्टर से कटाई हो रही है। करीब 70 फीसदी कटाई पूरी हो चुकी है। जिन राज्यों में बुवाई देरी से होती है, वहां कटाई का काम चल रहा है। किसान अपनी फसलों को घर में नहीं रख सकता, उसे तुरंत बेचना होता है। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) और नेफेड से खरीद के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा है। एफसीआइ और नेफेड राज्यों के साथ मिलकर विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत खरीद कर रहे हैं। हमने राज्यों से खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने को कहा है ताकि सोशल

डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।

देश में संभवत: पहली बार ऐसा अवसर आया है जब ऐसे संकटकाल में भी खाद्यान्न और फल-सब्जी की कमी नहीं है। देश में खाद्यान्न का भरपूर भंडार है। क्या किसान इसके श्रेय के हकदार नहीं है?

बिलकुल, किसानों ने कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई है। यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान भी खाद्यान्न, सब्जियों, दूध जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आसान हो पाई और कीमतें भी नियंत्रित रहीं। सरकार की नीतियों की अपनी भूमिका होती है लेकिन किसानों को अवश्य ही इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। हम इसके लिए किसानों का धन्यवाद करते हैं।

वास्तव में खरीद 20 अप्रैल से ही शुरू हो पाई है। क्या आप यह निगरानी कर रहे हैं कि राज्यों में गेहूं लेकर खरीद केंद्रों और मंडियों में पहुंचने वाले किसानों को टोकन जारी किए जा रहे हैं, एसएमएस से संदेश भेजे जा रहे हैं और सुचारु रूप से खरीद हो रही है या नहीं? क्या मंडियों और खरीद केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन हो रहा है?

एसएमएस के जरिए किसानों को संदेश भेजने की व्यवस्था सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू की गई। परिस्थिति को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी इसे लागू किया है। खरीद केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। राज्य और केंद्र स्तर पर हम पूरी व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। मेरी केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से बात होती रहती है। राज्यों से भी बात होती है। खरीद के शुरुआती तीन-चार दिनों में आवक धीमी थी, लेकिन अब काम सुचारु रूप से चल रहा है।

मंत्रालय ने उपज की ढुलाई, खाद-बीज और उपकरणों की दुकानें खोलने को लेकर अपने आदेशों में कई बदलाव किए। राज्यों से कहा गया कि वे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट में संशोधन करें ताकि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन किसानों से सीधे खरीद कर सकें, ई-नैम के जरिए बिक्री कर सकें। इन मामलों में राज्यों ने क्या कदम उठाए?

केंद्र सरकार की एडवायजरी को तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने आंशिक या किसी अन्य रूप से अनुमति दी है। बिहार में एपीएमसी है ही नहीं। सभी राज्य इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि किसानों को उपज बेचने में परेशानी न हो। 14 से ज्यादा राज्यों में फल-सब्जियों को एपीएमसी से बाहर किया जा चुका है। ई-नैम का भी उपयोग किया जा रहा है। हम 585 मंडियों में से 415 को जोड़ रहे हैं। इससे खरीद आसान होगी। कृषि उपज ढुलाई में अवश्य दिक्कतें थीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के रोक हटाने के बाद अब कोई परेशानी नहीं है। हमने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां देश भर से कोई भी वाहन चालक या किसान कृषि उपज का वाहन रोके जाने की शिकायत कर सकता है। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारी तत्काल बात करके समाधान करवा रहे हैं। हमने 15 अप्रैल को 'किसान वेब हेल्प डेस्क' लांच की। इसमें किसानों के अलावा ड्राइवर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक पांच लाख छोटे-बड़े वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। यह ऐप किसानों और ट्रांसपोर्टरों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है। किसान अपनी फसल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐप पर बुकिंग कर सकते हैं। इस ऐप पर भाड़ा भी तय हो जाता है। लॉकडाउन के कारण कहीं और फंसे चालकों को अपने वाहन तक जाने और वाहन में कृषि उपज ले जाने की अनुमति है।

बागवानी फसलों की पैदावार खाद्यान्न फसलों से भी ज्यादा हो गई है। बागवानी फसलें ज्यादा मूल्य की होने के साथ जल्दी नष्ट होती हैं। किसानों को आलू, आम, टमाटर वगैरह ले जाने में खासी दिक्कतें होने की खबरें आईं। इस समस्या का आपने क्या समाधान निकाला और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार क्या सोच रही है?

किसानों को आंशिक नुकसान हुआ। लेकिन शहरों में सब्जियों और फलों की किल्लत नहीं हुई और कीमतें भी नहीं बढ़ीं। इसका एक पहलू यह भी है कि अच्छी कीमत मिलने के कारण गांवों से सब्जियां ही नहीं, बल्कि दूध भी पूरी मात्रा में शहरों में भेज दिया जाता था। गांवों में इनकी किल्लत हो जाती थी। लॉकडाउन के दौरान गांवों में इनकी उपलब्धता बढ़ गई। किसानों को कुछ नुकसान अवश्य हुआ, लेकिन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआइएस) से फल उत्पादक किसानों को फायदा मिल रहा है। इस स्कीम में राज्यों के साथ मिलकर फलों की खरीद हो रही है।

किसानों ने कोरोना योद्धा के तौर पर अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई है। इसी वजह से लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न, सब्जियों, दूध की कमी नहीं हुई

दलहन और तिलहन की खरीद में कैसी प्रगति है?

दलहन और तिलहन का उत्पादन अच्छा रहा है। गेहूं के साथ इन फसलों की भी सरकारी खरीद हो रही है। नेफेड दालों की खरीद करके मिलिंग कराता है और उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है।

सहकारी क्षेत्र ने लॉकडाउन के दौरान दूध की अच्छी खरीद की और वितरण किया। लेकिन प्राइवेट डेयरियों और हलवाई वगैरह की फुटकर खरीद प्रभावित होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ।

यह सही है कि निजी डेयरियों और शहरों की फुटकर खरीद प्रभावित होने से किसानों को कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन गांवों में इस समय दूध की नदियां बह रही हैं। इस समय गांवों में दूध-दही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

हाल में सरकार ने किसानों के लिए कर्ज लौटाने को स्थगित किया है। 31 मई तक कर्ज लौटाने पर किसानों को चार फीसदी रियायती ब्याज का फायदा मिलेगा। क्या सरकार किसानों के लिए और कोई पैकेज ला रही है?

सरकार ने अप्रैल में किसान सम्मान निधि के तहत नौ करोड़ किसानों को 17,876 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को 7,300 करोड़ रुपये दिए गए। मनरेगा के तहत मजदूरों के सारे बकाए का भुगतान किया गया। राज्यों को आगे मनरेगा कार्यों के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए हैं। जनधन खातों के माध्यम से 20.40 करोड़ महिलाओं को 10,200 करोड़ रुपये की मदद दी गई और 2.84 करोड़ वृद्ध और दिव्यांगों को सहायता दी गई। हमारे मंत्रालय की ओर से 36,000 करोड़ रुपये की मदद दी गई। इसमें पीएम किसान निधि को भी जोड़ दिया जाए तो रकम 57,000 करोड़ रुपये बैठती है।

कोरोना संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय 1.70 लाख करोड़ रुपये के पहले पैकेज के बाद दूसरे पैकेज की तैयारी कर रहा है। क्या दूसरे पैकेज में किसानों को वित्तीय मदद दिए जाने की संभावना है।

अभी कुछ कहना संभव नहीं है। पीएम किसान से 75,000 करोड़ रुपये की मदद दी जा रही है। कुछ समय पहले हमने दो-ढाई करोड़ बचे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट से इसकी शुरुआत की थी।

सिर्फ 15 दिनों में 85 लाख किसानों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया। बैंकों ने 18 लाख किसानों को कार्ड जारी कर दिए, जिसमें उन्हें तीन लाख रुपये तक कर्ज के तौर पर निकालने की सुविधा दी गई है। हमारी कोशिश कम से कम एक करोड़ किसानों को कार्ड वितरित करने की है। इससे 65,000 करोड़ रुपये के कर्ज किसानों को मिल सकेंगे।

सरकार ने मनरेगा मजदूरों के बकाए का भुगतान किया और इसके तहत कार्यों का दायरा भी बढ़ाया है। मनरेगा में मजदूरों को ऐसे समय में लगाया जा रहा है जब कटाई का सीजन चल रहा है। क्या इससे दिक्कतें नहीं आएंगी? क्या कृषि गतिविधियों को मनरेगा के कार्यों में शामिल करने की योजना है?

मनरेगा के तहत 264 तरह के कार्य होते हैं, इनमें से 162 कार्य कृषि से जुड़े हैं। मनरेगा में किसानों के खेतों में मजदूर भेजने पर उसका हिसाब-किताब रखना मुश्किल होगा। सरकार की सोच है कि जब हम हर साल इस मद पर 60-70 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं तो एसेट बनने चाहिए। हम इसके जरिए जल संकट से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। एक तथ्य यह भी है कि मनरेगा के अधिकांश मजदूर बाहर नहीं जाते हैं। फैक्ट्रियों में स्थायी कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले, अनुबंधित श्रमिक और जगह-जगह जाकर खेतों में कटाई करने वाले मजदूर अलग होते हैं। लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने पर फैक्ट्रियों वाले और अनुबंधित मजदूर अपने घरों की ओर वापस चल दिए। लेकिन खेतिहर मजदूर या तो खेतों में पहुंच गए थे क्योंकि कटाई शुरू हो चुकी है या फिर निकल ही नहीं पाए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के उद्देश्य से ही सरकार ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काम शुरू करने की अनुमति दी है। इन योजनाओं से रोजगार पाने के इच्छुक लोगों को काम मिल रहा है। हमने पीएम आवास योजना में भी 1,000 करोड़ रुपये दिए हैं। राज्यों में करीब 48 लाख आवास बने हैं लेकिन अभी उन्हें पूर्ण करना बाकी है।

वर्तमान स्थिति में क्या आपको लगता है कि मनरेगा में मानव दिवसों में बढ़ोतरी होगी।

पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा का 60 हजार करोड़ रुपये का बजट था, जबकि इस पर 71 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए। नया वित्त वर्ष अभी शुरू ही हुआ है। वित्तीय दिक्कतों के चलते इस बार 61 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मजदूरी बढ़ने और कोरोना संकट के चलते मांग बढ़ने के कारण इस साल 80 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च का अनुमान है। इसके लिए हमें अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी होगी।

कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से मजदूर गावों में पहुंच गए हैं। वे काम के लिए शहरों की तरफ जल्दी नहीं जाएंगे। उन्हें नए जॉब कार्ड की आवश्यकता होगी। क्या नए कार्ड बनाए जा सकते हैं?

नए कार्ड बनाने पर कोई रोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करके जॉब कार्ड बनवा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा संकट से निकलने में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकास का इंजन बनेगा। यहां लॉकडाउन का ज्यादा असर नहीं पड़ा। आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था का प्रभावी इंजन बनाने के उद्देश्य से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए और सटीक रणनीति अपनाई जानी चाहिए?

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए सरकार ने मनरेगा, पीएम आवास और सड़क निर्माण शुरू करने की अनुमति दी है

ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों में कुछ व्यवधान आया था, लेकिन लॉकडाउन-2 लागू होने के कुछ दिनों के बाद आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई तो सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खोला गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य और जिला प्रशासन को सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य संबंधी एडवायजरी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा। हर क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाई जा सकती है। जिन जिलों में कोई संक्रमण नहीं है और हॉटस्पॉट नहीं हैं, वहां गतिविधियां तेज हो सकती हैं। धीरे-धीरे लोगों को भी एहसास होगा कि अगर वे कुछ भी छूने से बचेंगे, मास्क लगाएंगे और सैनिटाइजर इस्तेमाल करते रहेंगे तो संक्रमण नहीं होगा। जिला स्तर पर ये उपाय करने और गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का काफी भंडार है। महामारी के दौर में पूरी दुनिया में खाद्य वस्तुओं जैसे चीनी, मीट, फल वगैरह की मांग है। क्या हम निर्यात के लिए ऐसी रणनीति अपना सकते हैं, जिसमें प्रतिबंध कम हों और हम कृषि निर्यात को बढ़ाकर इस अवसर का फायदा उठा सकें?

सरकार इस मामले में गंभीर है। संबंधित मंत्रालय अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि जिंस विदेशों में भेजने वाले निर्यातकों से बात की। हम उनके सुझावों पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही आवश्यक कदम उठाएंगे।

एक-दो महीने में निर्यात गतिविधियां भी सामान्य होने की उम्मीद है। आज हम कृषि और खाद्य उत्पादों के मामले में फायदे की स्थिति में हैं, तो क्या इस अवसर का भरपूर लाभ उठा पाएंगे?

निश्चित ही, कुछ समय में सारी दिक्कतें दूर होंगी। भारत से निर्यात तेज होगा और हम इस मुश्किल के दौर में भी देश के लिए नए अवसर पैदा कर सकेंगे।

मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के अनुकूल राजनीतिक बदलाव हो चुका है। वहां आपकी सरकार भी बन गई है और छोटा मंत्रिमंडल भी गठित हो गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?

तीन मई के बाद जल्दी ही मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा। इस समय कोरोना को छोड़कर कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। इसलिए कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं यह अवश्य कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस संकट से निपटने के लिए पूरी ताकत और तन्मयता से काम कर रही है। उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हालात जल्दी ही सामान्य होंगे। भोपाल और इंदौर में ही स्थिति ज्यादा गंभीर है। पर यहां भी स्थिति जल्दी ही नियंत्रण में होगी।

आपके मंत्रालय का राज्यों से तालमेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। मौजूदा दौर में आपको राज्यों से कैसा सहयोग मिल रहा है?

हमें सभी राज्यों से सहयोग मिल रहा है। हमने राज्यों के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की है। सभी राज्य काम कर रहे हैं और केंद्र के निर्देशों का पालन करना चाहते हैं। आज के समय में सबकी एक ही प्राथमिकता है कि लोगों की जिंदगी बचाई जाए और कृषि और ग्रामीण गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। सभी इस मामले में एकमत हैं। इसका सकारात्मक असर होगा।

हकीकत देखिए, हुजूर!

महज ख्याली पुलाव न पकाइए, महामारी की रोकथाम जरूरी मगर आर्थिक गतिविधियां ठप होने से दुश्वारियां बेइंतहा, अर्थव्यवस्था शून्य से 75 फीसदी नीचे पहुंची

अरुण कुमार

विस्तारित लॉकडाउन पर विचार अहम है। यह हर किसी के लिए अनकही दुश्वारियां लेकर आया है, खासकर हाशिए पर गुजर-बसर करने वाले वर्ग की तकलीफों की तो इंतहा हो गई है। जरूरी वस्तुओं को छोड़कर ज्यादातर उत्पादन ठप है, कारोबार घाटा झेल रहे हैं और इनमें अनेक तो शायद दोबारा खड़े भी न हो पाएं। अर्थव्यवस्था को नुकसान तो लंबे समय तक के लिए हो चुका है। इसलिए नीति- नियंताओं के सामने दुविधा है कि 3 मई के बाद क्या करें।

असलियत को ध्यान में रखकर बने योजना

नीतियां वास्तविकता को ध्यान में रखकर बनें, सिर्फ ख्याली पुलाव न पकाएं कि सब ठीक हो जाएगा। जमीनी हालात को देखकर ही योजनाएं बनाई जानी चाहिए। कोविड-19 महामारी नई है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, इसलिए सटीक योजना बनाना मुश्किल है। दुनिया भर में चल रहे अनेक अनुसंधानों के बावजूद, आने वाले दिनों में क्या होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं।

इस महामारी का जनक एक वायरस है जो म्युटेट (जैविक रासायनिक रूपांतरण के जरिए) होकर जानवरों से मनुष्य में आया है। अब यह एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैला रहा है। अगर हम खुशकिस्मत हुए तो शायद उसमें फिर म्युटेशन हो और वह कम जानलेवा हो जाए। अभी तक यह पता है कि इस वायरस के तीन रूप हैं। लेकिन हम अपनी खुशकिस्मती के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि वायरस म्युटेशन से और ज्यादा घातक भी हो सकता है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि तापमान बढ़ने से वायरस नष्ट हो जाएगा, लेकिन अप्रैल में भारत में और इससे पहले उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले इलाकों में इसका संक्रमण लगातार बढ़ने से उम्मीदें कम हो गई हैं। हाइड्रोक्लोरोक्वीन को इस वायरस से बचाव की संभावित दवा माना जा रहा था, लेकिन अध्ययनों से पता चल रहा है कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि इस दवा के साइड इफेक्ट से लोगों की मौत हो रही है। सो, फिलहाल न तो इसकी कोई दवा है, न कोई टीका।

कोई भी योजना बनाते समय निकट भविष्य को तो ध्यान में रखना ही है, दीर्घकालिक नतीजों की भी तैयारी करनी है। ऐसा न हो कि हम दूसरी बार भी निहत्थे पकड़े जाएं। इस बार तो हम ऐसे पकड़े गए हैं कि यह मालूम ही नहीं कि इस संकट से कैसे निपटें। एक 'सतर्कता का सिद्धांत' भी होता है कि सबसे बुरे का अनुमान लगाइए और उसी के मुताबिक योजनाएं बनाइए। जीवन सामान्य रूप में बचाए रखना तात्कालिक फायदों से ज्यादा जरूरी है, जो सौभाग्य से रोग का प्रकोप घटने से शायद मिल जाए।

कुछ जिलों में संक्रमण के नए मामले नहीं मिल रहे हैं तो हम यकीन से नहीं कह सकते कि ऐसा पर्याप्त टेस्टिंग के अभाव में है या वास्तव में वहां संक्रमण नहीं फैला है

लंबा लॉकडाउन क्यों?

लॉकडाउन से बीमारी फैलने की रफ्तार कम होती है और इससे चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने की थोड़ी मोहलत मिल जाती है। भारतीय चिकित्सा व्यवस्था खेदजनक रूप से अपर्याप्त है। यहां डॉक्टर, नर्स, अस्पताल और उपकरण सबकी कमी है। न्यूयॉर्क सिटी, इंग्लैंड, इटली और स्पेन की चिकित्सा व्यवस्था भारत से बेहतर होने के बावजूद बीमारी पर जल्दी नियंत्रण करने में नाकाम रही। यह बात स्पष्ट है कि लॉकडाउन से वायरस नहीं मरता, बल्कि इससे निपटने की तैयारी करने का समय मिल जाता है। इससे वायरस की दवा या टीका बनाने तक के लिए भी मोहलत मिल सकती है।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली की खामियों, भीषण गरीबी और कुपोषण की समस्या को देखते हुए भारत को अपेक्षाकृत लंबे समय तक लॉकडाउन की जरूरत है। पर्याप्त टेस्टिंग सुविधाओं के अभाव में हम यह भी नहीं कह सकते कि बीमारी फैल रही है या नियंत्रण में है। अगर कुछ जिलों में संक्रमण के नए मामले नहीं मिल रहे हैं तो भी हम यकीन से नहीं कह सकते कि ऐसा पर्याप्त टेस्टिंग के अभाव में है या वास्तव में वहां संक्रमण नहीं फैला है। पर्याप्त टेस्टिंग के अभाव में सब कुछ खोलना बीमारी को दोबारा फैलने के लिए आमंत्रित करना है। तब हमें फिर से लॉकडाउन करना पड़ेगा जो पहले से भी ज्यादा दुखदायी होगा। हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की दुर्दशा से बीमारी बहुत तेजी से फैल सकती है और नतीजतन सामाजिक अराजकता पैदा हो सकती है।

एक वैकल्पिक विचार यह है कि लॉकडाउन से गरीबों का रोजगार छिन गया है, उनकी कमाई बंद हो गई है और वे भूखों मर जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि अगर बड़ी संख्या में लोग संक्रमण के शिकार हो जाते हैं तो दूसरे वायरस की तरह इस मामले में भी हर्ड इम्युनिटी (सामूहिक प्रतिरोध क्षमता) बन जाएगी। यानी वायरस के प्रति लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाएगी। यह तर्क भी दिया गया है कि 80 फीसदी लोगों में बीमारी का हल्का रूप उभरा है और वे अपने आप ठीक हो गए हैं। इनमें बीमारी का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। बाकी 15 फीसदी में कुछ लक्षण दिखाई देंगे और उन्हें आइसोलेशन में रखने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पांच फीसदी को अस्पताल में भर्ती करने और दो फीसदी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी और उनकी

मौत भी हो सकती है। लेकिन इंग्लैंड में यह नीति काम नहीं आई। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने और विशाल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ी। आशंका है कि कोरोना वायरस के चलते यूरोप में सबसे ज्यादा मौतें इंग्लैंड में ही होंगी।

भारत में इस विपदा से आदमी की जान की क्षति काफी ज्यादा होगी। अगर यह बीमारी पहले चरण में सिर्फ 60 फीसदी आबादी में फैलती है तो इसका मतलब हुआ 82 करोड़ भारतीय संक्रमित होंगे। अगर 20 फीसदी को आइसोलेशन में रखने और अस्पताल ले जाने की नौबत आई तो 27 करोड़ बेड की जरूरत पड़ेगी। पांच फीसदी को वेंटिलेटर की आवश्यकता हुई तो सात करोड़ लोगों को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, जबकि हमारे पास करीब एक लाख ही वेंटिलेटर हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों की मौत हो जाएगी और मरने वालों की तादाद एक साल में पांच करोड़ से भी अधिक हो सकती है। क्या समाज इतनी बड़ी तबाही झेल सकता है? यही वजह है कि हमें लंबे समय तक लॉकडाउन की जरूरत है। यह आजादी के बाद से ही देश में व्याप्त भीषण गरीबी के प्रति बेपरवाही और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की अनदेखी का नतीजा है।

लॉकडाउन कैसे कारगर हो?

भारत में लॉकडाउन अपने आप में चुनौती है। गरीबों में इस तरह के संकट झेलने की ताकत नहीं है। वे रोज कमाते हैं और रोज अपनी जरूरत का सामान खरीदते हैं। मध्यम वर्ग के लोगों या अमीरों की तरह वे जरूरी वस्तुएं खरीद कर नहीं रख सकते। वे भीड़भाड़ वाली जगहों में रहते हैं। कई बार एक ही कमरे में पांच या उससे भी ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए वहां आइसोलेशन मुमकिन नहीं है। गरीब जहां रहते हैं वहीं उन्हें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की जरूरत है। हमारे गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं इसलिए उसे गरीबों में बांटा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गरीब बाहर निकलेंगे और खाने-पीने की चीजों की लूट भी हो सकती है। इससे लॉकडाउन बेमतलब हो जाएगा। उनकी मुफ्त जांच होनी चाहिए क्योंकि वे जांच के लिए प्रति व्यक्ति 4,500 रुपये देने में सक्षम नहीं हैं। उन्हें झुग्गी बस्तियों से निकालने की भी जरूरत है। स्कूल, हॉल और खुली जगहों पर टेंट बनाकर उन्हें ठहराया जा सकता है। जो लोग अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, जांच के बाद उन्हें उनके गांव जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

किसानों के सामने अपनी उपज बेचने की समस्या है और उनकी उपज के दाम गिर रहे हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि फल और सब्जियां खेतों में ही सड़ रही हैं। सरकार को पूरी उपज खरीद लेनी चाहिए और उसे शहरी इलाकों में भेजना चाहिए, जहां कमी है। सार्वजनिक परिवहन की बसें और ट्रक इन दिनों खाली हैं, उनका इस्तेमाल इस काम में किया जा सकता है। इस तरह किसान के खलिहान से अनाज वगैरह खरीद कर लोगों के घर तक पहुंचाने से किसानों और शहरी गरीबों, दोनों की समस्याओं का समाधान होगा, साथ ही लॉकडाउन भी सफल होगा।

बंटे खाना: गरीबों का धैर्य टूटा तो अराजकता की आशंका

स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए। चुनिंदा फैक्टरियों में चिकित्सा उपकरणों और सुरक्षात्मक पहनावे का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। आइसोलेशन वॉर्ड के लिए होटलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मेडिकल और नर्सिंग के छात्र-छात्राओं को पैरामेडिकल प्रशिक्षण देकर आइसोलेशन वॉर्ड और अस्पतालों में उनकी मदद ली जा सकती है।

राहत पैकेज के लिए संसाधन

लॉकडाउन की अवधि में जनवरी 2020 की तुलना में उत्पादन 25 फीसदी से भी कम है, यानी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (-)75 फीसदी है। अगर उत्पादन छह महीने में महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाता है (हालांकि यह काफी आशावादी अनुमान है) तो अर्थव्यवस्था की विकास दर (-)17 फीसदी होगी। अगर अर्थव्यवस्था में दो महीने तक लॉकडाउन रहता है और उसके बाद इसमें तत्काल रिकवरी आती है और यह महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच जाता है (जो असंभव है) तो विकास दर (-)9 फीसदी होगी। आइएमएफ कैसे 1.9 फीसदी विकास दर का अनुमान लगा रहा है, यह समझ से परे है।

अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट से सरकार के राजस्व में भी तेजी से कमी आएगी। उद्योगों के टैक्स में कटौती या कोई राहत पैकेज देना मुमकिन नहीं होगा। वित्तीय क्षेत्र बड़े संकट में होगा। उसको बचाने के साथ उद्योग जगत को भी नाकाम होने से रोकने की चुनौती होगी। ब्याज के भुगतान और रक्षा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए धन जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। गरीबों के राहत पैकेज और चिकित्सा खर्चों के लिए वेतन वगैरह में कटौती करनी पड़ेगी। बेरोजगार और गरीब हो चुकी आधी आबादी को छह महीने तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक की 1.9 डॉलर की गरीबी रेखा की तुलना में आधी रकम भी दी जाए तो 15 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। इसमें स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे मदों पर होने वाले खर्च को भी जोड़िए। दूसरे खर्चों में व्यापक कटौती किए बिना सरकार यह नहीं कर पाएगी।

निष्कर्ष

भारत इन दिनों अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और इसके लिए अलग हटकर सोचने की जरूरत है। विशेषज्ञों के अनुसार बिना लॉकडाउन के स्थिति नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। यह भी सच है कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था थम जाएगी और संसाधन नहीं बचेंगे। लेकिन जीवन बचाना भी उतना ही अहम है ताकि लॉकडाउन का फल मिल सके। इसके लिए हमें सिर्फ सबसे जरूरी चीजों पर खर्च करने की जरूरत है, और वह है जीवन और कारोबार को बचाने के लिए राहत पैकेज। इस महामारी से निपटने के बाद हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हमारा समाज कैसा है, लेकिन अभी तो समूचा फोकस जीवन और कामकाज बचाने पर ही होना चाहिए।

(लेखक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में मैल्कम आदिशेषैया चेयर प्रोफेसर हैं)

दशकों पीछे जाने का डर

लॉकडाउन के बाद परमिट राज की संस्कृति को रोकना जरूरी, ऐसा नहीं होने से गंभीर संकट खड़ा होगा

कौशिक बसु

अभी यह अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी कि जब हम कोविड-19 की सुरंग से निकले तो दुनिया कैसी दिखेगी। फिलहाल, हम इस सुरंग के बाहर रोशनी नहीं देख पा रहे हैं। हमें यह भी नहीं मालूम है कि कोई सटीक टीका भी मिल पाएगा, जिससे हम कोविड के थोड़े-बहुत डर के साथ जीना और काम करना शुरू कर पाएंगे, जैसे हम अब इन्फ्लूएंजा के साथ कर पा रहे हैं। या कुछ साल तक भरोसेमंद टीका ईजाद नहीं हो पाता है और हमें सामाजिक मेलजोल में दूरी रखकर और लगातार टेस्ट के जरिए वायरस के संक्रमण से बचे रहने के लिए आश्वस्त होना पड़ेगा और अपनी जिंदगी और आजीविका चलाते रहना होगा।

कोविड-19 के रहस्यमय संकट और उसके माकूल आर्थिक जवाब पर अनेक तरह के विचार चर्चा में हैं। हमें विश्व युद्धों और महामारियों के इतिहास से मालूम है कि ऐसी आपदाएं देशों के हालात पलट देती हैं, विजेता पिछड़ जाते हैं और पिछड़े अगुआ हो जाते हैं। फिर भी, तमाम अनिश्चितता के बावजूद, यह बेहद जरूरी है कि भविष्य के बारे में सोचा जाए और अपनी तरफ से भरसक कोशिश की जाए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था और उसके हिस्सेदार देश बेहतर करें और लोगों को बेवजह तकलीफ न झेलनी पड़े।

हमने देशों की अर्थव्यवस्थाओं के हालात के शुरुआती लक्षण देखना शुरू किया है और हम उसके आधार पर कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। लिहाजा, अगर संभव हो तो, इस वक्त तमाम मतभेदों को दूर रखकर मानवता के सामने खड़ी इस चुनौती के मुकाबले के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए। वायरस के प्रकोप की रोकथाम और अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के बीच सही संतुलन बैठाने की चुनौती है। हम वायरस के प्रकोप की रोकथाम की कीमत गरीबों, कामगारों और प्रवासी मजदूरों को ही अदा करने नहीं दे सकते और न ही अर्थव्यवस्था की नींव इस कदर कमजोर होने दे सकते हैं कि हम महामारी से उबरने के बाद आर्थिक मलबे पर बैठे पाए जाएं। जिंदगियों और माली हालत के बीच चुनाव, दरअसल जिंदगियों और जिंदगियों के बीच चुनाव करने जैसा है।

वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने की भारत की कोशिशों की तारीफ हुई है, सिर्फ केरल राज्य की नहीं, जिसे दुनिया भर से वाहवाही मिली है, बल्कि समूचे देश की। कोविड-19 के मामले भारत में अभी कम हैं। हर एक करोड़ लोगों में केवल पांच लोगों की जान गई है। यह आंकड़ा बेहद कम है, सिर्फ बेल्जियम के मुकाबले नहीं, जो इस फेहरिस्त में सबसे ऊपर है और प्रति एक करोड़ आबादी में 5,180 जानें गंवा चुका है, बल्कि कई दूसरे देशों के मुकाबले भी। मसलन, अमेरिका में यह अनुपात 1,370, स्पेन में 4,550, इटली में 4,080 और ब्रिटेन में 2,550 है।

जायज बात तो यह है कि प्रति एक करोड़ आबादी में मौत के आंकड़ों के मामले में भारत ही सबसे अलग नहीं है। अपेक्षाकृत कम आंकड़े फिलहाल लगभग समूचे अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों में भी हैं। यह अनुपात बांग्लादेश में 7, श्रीलंका में 3, पाकिस्तान में 9, तंजानिया में 2, नाइजीरिया में 1 और इथोपिया में 0.3 है। कोई भी यह फर्क नहीं समझ पा रहा है कि एक तरफ यूरोप और उत्तरी अमेरिका है और दूसरी तरफ अफ्रीका और दक्षिण एशिया है। यह इसलिए तो हो नहीं सकता कि ये देश अलग-थलग हैं। बांग्लादेशी दुनिया भर में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं और इथोपिया की चीन से आमदरफ्त काफी है। इसके बावजूद इन दोनों देशों में मृत्यु दर काफी कम है। आखिर, ऐसा क्यों है? इसका टका-सा जवाब तो यही है कि हम नहीं जानते। फिर भी, हमें वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के सभी वाजिब कदम उठाने ही होंगे। यह एहसास बेहद जरूरी है कि जोखिम शून्य नहीं हो सकता। जिंदगी में कुछ भी जोखिम से खाली नहीं होता। वायरस को हराने के लिए मकसद 'प्रजनन दर' या आर-ओ को एक से नीचे लाने का होना चाहिए। आर-ओ का मतलब है संक्रमण के शिकार एक व्यक्ति से औसतन कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है। किसी भी इलाके में अगर आर-ओ एक से नीचे आ जाता है, जैसा केरल में हुआ है, तो हम समझते हैं कि उस इलाके से बीमारी छंटने लगी है।

आर्थिक नीति की चुनौती यह है कि लॉकडाउन कैसे खोला जाए। यह बेहद सावधानीपूर्वक मगर फुर्ती से करना होगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया के 73 देशों में लागू सख्त लॉकडाउन में भारत सबसे ऊपर है। थोड़े समय के लिए यह फायदेमंद है। लेकिन सख्ती के पायदान पर कोई देश लंबे समय तक जमे रहना नहीं चाहेगा। उसका असर गरीबों की बर्बादी में दिखेगा और दीर्घावधिक आर्थिक संभावनाओं को नुकसान पहुंचाएगा।

देश में बेरोजगारी दर आज 24 फीसदी है, जो अब तक की सबसे अधिक है। मार्च में भारत से पूंजी का पलायन सबसे अधिक हुआ है। मोटे तौर पर 15 अरब डॉलर देश से बाहर चले गए। यह मार्च में दुनिया की किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था से सबसे बड़ा पूंजी पलायन भी है। साफ है कि वैश्विक खिलाड़ियों की यह प्रतिक्रिया है कि अर्थव्यवस्था की गाड़ी थम गई है। लिहाजा, भारतीय रुपया कमजोर हुआ है और अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ऐसी कुछ समस्याएं तो इस मनहूस दौर में उभरनी स्वाभाविक हैं। हम कुछ समय के लिए इन समस्याओं से निपट सकते हैं। लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत विश्व व्यापार, निर्यात और कारोबार के मौके दूसरे देशों को थमा देगा और कामकाजी वर्ग को भारी दुर्दिन में धकेल देगा।

3 मई को लॉकडाउन का यह चरण खत्म होने पर हमें कारोबार खोलना शुरू करना होगा, निजी क्षेत्र, खासकर अनौपचारिक उद्यमों और छोटे उद्योगों को शुरू करने की इजाजत देनी होगी। आचार-व्यवहार के तौर-तरीकों, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, हाथ धोने के नियम तो तय करने होंगे, लेकिन हमें गरीब मजदूरों को उनके काम की जगह पहुंचने की सुविधाएं भी शुरू करनी होंगी और हमारे फर्म और कारखानों को काम शुरू करने देना होगा। साथ ही, हमें आचार-व्यवहार से नियम-कायदों के प्रति सबको 'भागीदारी' के लिए प्रोत्साहित करना होगा, न कि अफसरशाही के 'फरमान' से। भारत में 'परमिट राज' का लंबा इतिहास रहा है, जिसमें सारे कारोबार अफसरशाही की मर्जी पर निर्भर रहते थे। उसका रवैया यह था कि सबका गला दबाकर कुछ बड़ी कंपनियों को बढ़ने दिया जाए। नतीजतन, देश की आर्थिक वृद्धि लंबे समय तक अवरुद्ध रही। हमें उस पुराने रवैए के बढ़ जाने के खिलाफ चौकस रहना होगा।

भारत ही नहीं, सभी उभरते देश दोराहे पर खड़े हैं। इस अकाल-वेला में कोई भी अहम चूक सामान्य दौर जैसी नहीं होगी कि उसे सहज ठीक किया जा सके। कोई गलत कदम देश को कई दशकों तक पीछे धकेल सकता है।

(लेखक अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, यह लेख इंडियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित हुआ है)

राहत पैकेज में देरी क्यों

आज ऐसे लाखों-करोड़ों लोगों को सरकार की मदद की जरूरत है, जिनके जीवन और आजीविका पर भारी संकट

डॉ. बिश्वजीत धर

महामारी कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं सख्त लॉकडाउन में हैं, जिससे लोगों की जिंदगियां और अजीविकाएं ऐसे संकट में हैं, जैसा आधुनिक सभ्यता के दौर में कभी नहीं दिखा था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे 1930 के दशक की महामंदी के बाद सबसे बुरा आर्थिक दौर कहा है, लेकिन कुछ ताजा आंकड़े तो और भयावह तसवीर का संकेत दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत के एक अहम संकेत ऊर्जा की कीमतें गोता लगा गई हैं। दुनिया भर में तेल की कीमतें तय करने में अहम भूमिका निभाने वाले वेस्ट टेक्सास क्रूड की वायदा कारोबारी कीमतें शून्य से नीचे पहुंच गईं। प्रति बैरल -37.63 डॉलर की कीमतें 1946 के बाद के सबसे निचले स्तर पर चली गईं। विश्व व्यापार संगठन के मुताबिक, वैश्विक व्यापार का आकार 2020 में 13 से 32 फीसदी तक घट सकता है। ये आंकड़े बताते हैं कि चालू साल में वैश्विक अर्थव्यवस्था पांच फीसदी तक घट सकती है। चिंता की बात यह है कि अभी भी अधिकांश देश कोविड-संकट में फंसे हुए हैं।

तो, अर्थव्यवस्था के इस असाधारण बुरे दौर में वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है? पश्चिमी देशों ने इस असाधारण वक्त में घरेलू मांग बढ़ाने और कारोबार की मदद के लिए अब तक के सबसे बड़े आर्थिक राहत पैकेज देने के फौरी कदम उठाए। अमेरिका ने कोरोनावायरस सहायता, राहत और आर्थिक (केयर्स) कानून बनाकर सबसे पहले पहल की। केयर्स कानून के तहत अमेरिका करीब 2.2 लाख करोड़ डॉलर की पूंजी अर्थव्यवस्था में डालेगा, जो उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 फीसदी के बराबर है। इसके अलावा फेडरल रिजर्व बैंक ने छोटे और मझोले बिजनेस को बचाने के लिए 2.3 करोड़ डॉलर का राहत पैकेज देने का भी ऐलान किया है। इस भारी भरकम राहत पैकेज ने अमेरिकन रिकवरी ऐंड रिइन्वेस्टमेंट कानून 2009 के तहत 831 अरब डॉलर के दिए गए पैकेज को भी बौना कर दिया है। उस वक्त भी अमेरिकी सरकार ने आर्थिक मंदी से बचाने के लिए राहत पैकेज दिया था।

अमेरिका के मौजूदा राहत पैकेज में सबसे बड़ी राहत वहां के निवासियों को मिलेगी। उन्हें 560 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें से 300 अरब डॉलर कैश ट्रांसफर के रूप में और बाकी राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में दी जाएगी। कैश ट्रांसफर राशि ऐसे चार लोगों के परिवार को मिलेगी, जिनकी कुल आय 1.50 लाख डॉलर से कम है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अकेले रहता है और उसकी आय 75 हजार डॉलर तक है तो उसे भी कैश ट्रांसफर के तहत सहायता राशि मिलेगी। अहम बात यह है कि सहायता राशि देते समय गरीबी रेखा को पैमाना नहीं माना गया है। अमेरिका ने 2020 के लिए ऐसे चार लोगों के परिवार को गरीबी रेखा के तहत माना है जिनकी आय 26,200 डॉलर से कम है। आसान शब्दों में कहें, तो राहत पैकेज देते समय अमीर-गरीब का पैमाना नहीं माना गया है। यानी सहायता राशि एक निश्चित आय तक सभी लोगों को मिलेगी।

बड़े कॉरपोरेट को भी बड़े पैमाने पर राहत दी गई है। केयर्स कानून के तहत 500 अरब डॉलर की रकम कर्ज, कर्ज की गारंटी और दूसरे निवेश के लिए खर्च की जाएगी। इसी तरह ऐसी छोटी कंपनियां, जिनमें 500 या उससे कम कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें राहत पैकेज के तहत 350 अरब डॉलर की सहायता राशि दी जाएगी। ऐसी कंपनियां एक करोड़ डॉलर का कर्ज कर्मचारियों को वेतन देने, उन्हें छंटनी से बचाने, किराया देने और मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए भी ले सकेंगी, जिसे जरूरत पड़ने पर माफ भी किया जा सकता है। यह कदम जून तक कर्मचारियों की छंटनी रोकने के लिए उठाया गया है।

अमेरिका की तरह यूरोपीय संघ के देशों ने भी राहत पैकेज देने में कोई देरी नहीं की है। जर्मनी ने 1.1 लाख करोड़ यूरो का राहत पैकेज दिया है, जो उसकी जीडीपी का एक-तिहाई है। इसके तहत 600 अरब यूरो का आर्थिक स्थायित्व कोष (इकोनॉमिक स्टैबिलाइजेशन फंड) बनाया गया है। इसका इस्तेमाल कंपनियां कर्ज की गारंटी देने और वित्तीय संकट में फंसी कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने में कर सकेंगी।

जर्मनी की तरह फ्रांस की सरकार ने भी कंपनियों के कर्ज की गांरटी ले ली है। इसके अलावा छोटे कारोबारियों के लिए भी राहत पैकेज का ऐलान किया है। फ्रांस की सरकार ने कुल जीडीपी की करीब 14 फीसदी राशि राहत पैकेज के रूप में दी है। इसी तरह जापान ने 990 अरब डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान किया है, जो उसकी कुल जीडीपी का करीब 19 फीसदी है।

आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। सरकार का राहत पैकेज का ऐलान नहीं करना काफी चौंकाने वाला है

इन सरकारों के राहत पैकेज का स्पष्ट संदेश है कि असाधारण समय, असाधारण कदमों की मांग करता है। इसके लिए उन्होंने अपनी राजकोषीय नीति को अधिकतम स्तर तक लचीला बना दिया है। मौजूदा संकट में सरकार का खर्च बढ़ाकर ही मांग निकाली जा सकती है। ऐसा करने से बिजनेस डूबने से बच जाएंगे। दूसरे देशों के रुख के मद्देनजर यह हैरान करने वाला है कि भारत सरकार ने अभी तक इस तरह के राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है। अभी तक राहत पैकेज के नाम

पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए 1.7 लाख करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया है। इसमें अधिकतर मदों के लिए किए गए प्रावधान नए नहीं हैं। लेकिन अगर इसी को स्वीकार कर लिया जाए, तो भारत का राहत पैकेज, उसकी जीडीपी के मुकाबले केवल 0.7 फीसदी है। गरीबों को राहत पैकेज के तहत 500 रुपये दिए जाने का प्रावधान भी काफी कम है, उन्हें संकट के इस दौर में जीवनयापन के लिए इससे ज्यादा की जरूरत है।

दुनिया के दूसरे देशों के विपरीत भारत सरकार के इस रुख का अगर विश्लेषण किया जाए तो एक संभावना यह लगती है, कि सरकार राजकोषीय घाटे को बढ़ने से रोकना चाहती है। वह राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन कानून के तहत राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखना चाहती है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ती गई है। इस वजह से लगातार यह मांग उठ रही है कि सरकार आक्रामक राजकोषीय नीति अपनाए। लेकिन भारत सरकार लगातार भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर भरोसा किए हुए हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सस्ते कर्ज की नीति पर भरोसा कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि बाजार जब पूरी तरह धराशायी हो गया है, उसके बावजूद रिजर्व बैंक नकदी बढ़ाने की नीति पर ही चल रहा है। उसे लगता है कि ऐसा करने से मांग बढ़ जाएगी। हाल ही में रेपो रेट में की गई कटौती इसी नीति की परिचायक है।

आजादी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। सरकार का राहत पैकेज का ऐलान नहीं करना काफी चौंकाने वाला है। सरकार को हर हाल में यह समझना चाहिए कि बाजार में मौजूद नकदी का इस्तेमाल उसे करना होगा। इसके लिए सरकार को अपनी उधारी बढ़ानी होगी और उसे अपने राजकोषीय घाटे के बढ़ने की चिंता छोड़नी होगी। इसी तरह के कदम की सलाह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भी दी है। आइएमएफ ने अप्रैल में जारी अपनी रिपोर्ट (फिस्कल मॉनीटर) में कहा है कि भारत को अपने राजकोषीय प्रबंधन की नीति में बदलाव लाना होगा, ताकि वह महामारी के संकट से निपट

आरबीआइ की पहल: केंद्रीय बैंक के फैसले से मांग कैसे बढ़ेगी

सके। उसे स्वास्थ्य पर अपना खर्च बढ़ाना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में जारी गिरावट को संभाला जा सके।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो भी राहत पैकेज बनाएगी, उसका प्रमुख जोर कॉरपोरेट सेक्टर को राहत देने पर ही होगा। लेकिन राहत पैकेज बनाते वक्त दो बातों पर उसे खास तौर से ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि इस संकट में सबसे ज्यादा परेशानी में नौकरीपेशा वर्ग है, उसमें भी प्रवासी मजदूर बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। उनके जीवन और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। दूसरी अहम बात कृषि क्षेत्र के लिए है, जो इस समय प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की वजह से दोहरे दबाव का सामना कर रहा है। इस समय सरकारी तंत्र को रबी की फसल की ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से निजी क्षेत्र का बाजार पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इसके अलावा सरकार को राहत पैकेज बनाते समय दूसरे देशों के पैकेज पर भी गौर करना चाहिए। ऐसा करने से उसे यह पता चलेगा कि इन देशों ने अपने छोटे और मझोले बिजनेस को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। मसलन, बांग्लादेश ने अपनी गारमेंट इंडस्ट्री को राहत दी है। वहां गारमेंट इंडस्ट्री में ज्यादातर महिलाएं काम करती हैं। भारत में इस तरह के उद्योग-धंधों को बचाने की बेहद जरूरत है, ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। अंत में एक बात और, बुरा वक्त एक मौके की तरह होता है। भारत को इसका फायदा उठाकर अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। ऐसे दौर में यह कहने से कोई गुरेज नहीं है कि आज उन लाखों-करोड़ों लोगों को सरकार की मदद की जरूरत है जिनका जीवन और आजीविका इस संकट में पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई है। यह समय भारतीय लोकतंत्र की असली परीक्षा का है।

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज ऐंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं।)

नए मॉडल की जरूरत

बाजार को प्रभावित करने वाली अंतरराष्ट्रीय शक्तियों पर असीमित निर्भरता छोड़नी होगी

भूपेंद्र यादव

निश्चित ही कोविड-19 का यह त्रासद दौर भी एक दिन गुजर जाएगा क्योंकि आपदाएं स्थायी नहीं होती हैं। इतिहास में पहले भी ऐसी आपदाएं आई हैं और दुनिया उससे उबर कर निकली है। चौदहवीं शताब्दी में प्लेग नामक महामारी ने यूरोप की जीवन प्रणाली को प्रभावित किया था। इसके बाद चेचक, हैजा सहित अनेक महामारियों का दौर आया, जिससे मानव समाज तथा वैश्विक परिवेश में बड़ा बदलाव देखने को मिला। यह भी सच है कि ऐसी परिस्थितियों की भारी कीमत पहले भी चुकानी पड़ी है और आज भी चुकानी होगी। यह भी सत्य है कि कोविड-19 का यह दौर जाते-जाते दुनिया और मानव सभ्यता के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ जाएगा। इस अदृश्य परजीवी के संकट से उभरे सवालों को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझने की चुनौती हमारे सामने है।

काफी हद तक यह सही है कि पिछले कुछ दशकों में हमने तकनीक आधारित प्रगति के बहुस्तरीय लक्ष्य हासिल किए हैं। तकनीक के सहारे सब कुछ हासिल कर लेने की होड़ भी पैदा हुई है। ऐसा इसलिए भी हुआ कि पिछले दशकों में तकनीक के क्षेत्र में हुई क्रांति ने मानव जीवन की जरूरतों को पूरा करने का सरल और सुलभ साधन उपलब्ध कराया है। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव प्रकृति आश्रित कम रहा और तकनीकी आश्रित अधिक होता गया। लेकिन कोरोना नाम के इस वायरस की वजह से पैदा हुए संकट की स्थिति ने मानव समाज की अनंत इच्छाओं पर लगाम लगाया है। सब कुछ तेजी से हासिल कर लेने की गति को मानो रोक-सा दिया है। यह ठहराव ऐसा है कि आज हम अपने घरों में खुद को कैद करके ही सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं।

निश्चित ही दुनिया का हर देश कोरोना के स्थायी समाधान के रास्ते तलाश रहा है। इस वायरस को निष्प्रभावी करने की वैक्सीन ईजाद करके हम तात्कालिक समाधान की राह तो खोज लेंगे, लेकिन सिर्फ इतना कर लेना स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए यह धारणा रखना कि इसके किसी वैक्सीन की खोज कर लेने मात्र से मानव समाज उसी ढर्रे पर आ जाएगा, गलत अपेक्षा रखने जैसा है। मानव समाज को यह स्वीकार करना ही होगा कि हमारी चुनौती सिर्फ समाधान खोज लेने तक नहीं है, बल्कि सबक लेकर आगे की राह देखने की भी है. दूरगामी समाधान सबक लेने से ही निकलेगा। इस समस्या को अतीत मानकर बेतहाशा दौड़ में एकबार फिर कूद जाना, हमारी गलती होगी।

भविष्य में हमें इस बात का सटीक मूल्यांकन अवश्य करना होगा कि दुनिया को इस आपदा की कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। साथ ही, हमें प्रगति के संतुलित और प्रकृति पोषक उपायों की दिशा में भी सोचना होगा। प्रगति के असीमित लक्ष्यों को हासिल करने की इच्छा पालने वाली दुनिया के समक्ष इस नए दौर में कोविड का संकट मानव सभ्यता के लिए एक 'चेतावनी' बनकर उभरा है। तकनीक और प्रकृति के प्रति संतुलित सोच का अभाव हमें समस्याओं के नए अंधकार में ही ले जाएगा।

हमें समझना होगा कि दुनिया पहले से ही प्राकृतिक रूप से संकट की स्थिति की तरफ बढ़ रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। आए दिन बाढ़ और भूकंप की प्राकृतिक आपदाओं से मानव जीवन में संकट बढ़ रहा है। भू-संपति की सुरक्षा का स्तर अनिश्चित होता जा रहा है। ऐसे में वायरस श्रृंखला की विकटता नए किस्म के खतरे की आहट देने वाली है। सवाल उठता है कि कहीं हम जाने-अनजाने ऐसी दोहरी चुनौतियों को आमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं?

भारत के संदर्भ में अगर बात करें, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम प्रगति के संतुलित आयामों पर विचार करें। विकास के लक्ष्यों, उसकी सीमाओं और उसकी आवश्यकता को एक बार फिर परिभाषित करने की दिशा में व्यापक चर्चा को आगे बढ़ाएं। यह सवाल अब गंभीरतापूर्वक चर्चा की मांग करता है कि विकास की सीमा क्या है और संतुलित विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को भी चिह्नित करने की दिशा में अब सोचने की जरूरत है।

भारत की सामाजिक और भौगोलिक संरचना में बसावट के लिहाज से देखें, तो गांव, कस्बे और शहर संतुलित रूप से महत्व रखते हैं। बसावट की इस संरचना का न सिर्फ मानव जीवन बल्कि पशु-पक्षी, जीव-जंतु तथा पर्यावरण के लिए भी विशेष उपयोगिता है। जल-जंगल भी इस संरचना का हिस्सा हैं। अत: विकास के लक्ष्य और सीमाओं को तय करते समय हमें इस भौगोलिक संरचना की उपयोगिता को प्राथमिकता तथा इस संरचना की बसावट के सामाजिक महत्व को तरजीह देनी होगी। इसके सभी आयाम परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं, लिहाजा, इनके बीच समान और संतुलित विकास का होना भी उतना ही आवश्यक है। स्वच्छता, पर्यावरण और जल-संरक्षण की अनदेखी करके हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते।

मानव समाज को यह स्वीकार करना होगा कि चुनौती सिर्फ समाधान खोजने तक नहीं है, बल्कि उससे सबक लेकर आगे की राह देखने की भी जरूरत है

मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा के आधुनिक विकल्पों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस आवश्यकता की पूर्ति को ऊर्जा स्रोतों के दोहन के रूप में न लेकर अनुकूल विकल्पों को अपनाते हुए हमें पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा सहित ग्रीन-एनर्जी की ओर कदम बढ़ाना होगा।

जिन बदलावों की बात की जा रही है। उन बदलावों के लिए पहली आवश्यकता यह है कि समाज अपने सोचने की दृष्टि को भी बदलने का प्रयास करे। ऐसा करके ही हम अपने शौक की सीमा और आवश्यकता

की पूर्ति का अंतर समझ पायेंगे। कहा जाता है कि शौक और आवश्यकता में सिर्फ इतना अंतर है कि शौक असीमित हो सकते हैं और आवश्यकताओं की सीमा होती है। इस धरती के संसाधन सिर्फ हमारे शौक या पसंद-नापसंद से संबंधित नहीं हैं, बल्कि इनसे मानव जीवन के अस्तित्व का सवाल भी जुड़ा है। इस कठिन दौर से उबरने के बाद समाज को अपनी आवश्यकता से जुड़े तमाम विषयों पर विचार करना होगा, जो उसके भविष्य के लिए उपयोगी हैं। स्वास्थ्य चिंतन को लेकर हमारे दृष्टिकोण में नवाचार होना आवश्यक है। बेहतर सुविधाओं, अस्पतालों के साथ-साथ हमें स्वास्थ्य के प्रति शिक्षित समाज के निर्माण पर भी सोचना होगा। इस क्षेत्र में युगानुकूल शोध, भावी चुनौतियों से निपटने की तैयारी तथा आरोग्य को प्रोत्साहित करने वाली आयुष प्रणाली को बढ़ावा देने की जरूरत होगी।

पिछले दशकों में समाज को बाजार के बदलते स्वरूप ने काफी प्रभावित किया है। यह प्रभाव कई मामलों में हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने की सीमा तक पहुंचने लगा है। लिहाजा, बाजार को लेकर भी समाज की दृष्टि में बदलाव की जरूरत है। हमें समझना होगा कि बाजार समाज को असंतुलित ढंग से प्रभावित करने की स्थिति में न आए। प्रकृति की परवाह किए बिना बाजार को अंधी दौड़ में धकेलना, कहीं न कहीं संसाधनों के अनुचित दोहन को प्रोत्साहित करने जैसा है। बाजार का आर्थिक मॉडल नियंत्रित भले न हो, लेकिन इसका ध्यान रखना भी जरूरी है कि वह स्वच्छंद न हो जाए।

पिछले सात दशकों में भारत एक स्थिर और विश्वसनीय लोकतांत्रिक शक्ति बनकर उभरा है। भारत के राजनैतिक मॉडल की भी इसकी लोकतांत्रिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में हम भविष्य के बदलावों के आलोक में भारत की भूमिका पर चर्चा करेंगे, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि भावी बदलावों के प्रति राजनीति की क्या भूमिका होगी? निश्चित ही कोई भी राजनैतिक दल वर्तमान में पैदा हुए वायरस के खतरे की अनदेखी नहीं कर सकता है। भविष्य में ऐसा कोई खतरा देश पर न आए, इसके लिए सकारात्मक उपायों की अनदेखी राजनैतिक दल नहीं कर सकते। अपने वैचारिक मतभेदों के बावजूद, सभी दलों को मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक पारदर्शी नीति तैयार करने के लिए आगे आना ही होगा। राजनैतिक दलों को एक ऐसे नीतिगत विषयों पर विचार करना होगा, जो विकास के 'जीडीपी केंद्रित' मॉडल तक सीमित न होकर सामान्य जनजीवन से जुड़े विषयों तथा आजीविका के प्रश्नों पर ठोस समाधान देने में सक्षम हो। भारत जैसे देश के लिए आजीविका की सुरक्षा पर एकजुटता सर्वाधिक आवश्यक है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि अपवादों को दरकिनार कर दें, तो वर्तमान महामारी में देश ने एक इकाई के रूप में एकजुटता दिखाई है। लगभग पूरे देश ने लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने का जिम्मेदारी से पालन किया है। राज्य भी वायरस से लड़ने में केंद्र के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहे हैं। आज जिस एकजुटता और अनुशासन का परिचय देश ने

आर्थिक रिवाइवल के लिए वित्तीय पैकेजों को स्थायी सुरक्षा के प्रति केंद्रित करना होगा। और वैश्विक निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम उठाना होगा

दिया है, भावी चुनौतियों से निपटने में भी इसी भावना की जरूरत है।

यह सवाल सबके मन में है कि इस कोविड के खतरे के बाद अर्थव्यवस्था में किस तरह के बदलाव आएंगे? जैसा हमने देखा है कि इतिहास में जब भी कभी ऐसी महामारी आई है, उसके सामाजिक, आर्थिक तथा वैश्विक परिणाम किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले रहे हैं। कोविड के बाद का दौर भी परिवर्तनकारी होगा। सभी आकलन बताते हैं कि महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा होगी। हालांकि इसके प्रभाव का दायरा कितना अधिक होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने इस पर नियंत्रण पाने में कितना समय लगाया है।

आज वैश्वीकरण के दौर में जब कोविड के कारण सारी सीमाएं और आवागमन लगभग बंद हैं, तब वैश्विक अर्थ प्रणालियों की कमजोर कड़ियां सामने आ रही हैं। आर्थिक बदलावों के लिहाज से हमें आर्थिक रूप से अंतरराष्ट्रीय निर्भरता के क्षेत्रों पर पुनर्विचार करने की जरूरत होगी। एक, 'राज्य इकाइयों के संघ' के रूप में भारत को ऐसे मॉडल की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, जो बाजार को प्रभावित करने वाली अंतरराष्ट्रीय शक्तियों पर असीमित रूप से निर्भर न हो। हमें इस संकटकाल से उबरने के लिए आर्थिक पुनरुद्धार के लिए वित्तीय पैकेजों को स्थायी आजीविका सुरक्षा के प्रति केंद्रित करना होगा तथा वैश्विक निर्भरता को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। समाधान की बहस तात्कालिक होने के बजाय दूरगामी और मानव सभ्यता के लिए संतुलित तथा टिकाऊ हो, यह हमारी नीति-विषयक चर्चाओं के केंद्र में होना चाहिए। भविष्य के लिहाज से हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्थायी, प्रकृति अनुकूल, मानव हित में कदम उठाने होंगे। प्रगति के प्रति अपनी दृष्टि भी बदलनी होगी।

(लेखक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य हैं)

लेट-लतीफी से बढ़ा संकट

सरकार अच्छी तरह जानती है कि शुरुआत में उसने संकट से निपटने का अच्छा मौका गंवा दिया

गौरव वल्लभ

कोविड-19 के खतरे को देखते हुए 25 मार्च को जब भारत में लॉकडाउन लगाया गया, उस वक्त संक्रमण के कुल 657 मामले सामने आए थे और 11 लोग जान गंवा चुके थे। उस समय सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि उसने इस संकट से लड़ने के लिए अच्छा मौका गंवा दिया है। उसे मालूम था कि महामारी से लड़ने के लिए उसने समय रहते तैयारी नहीं की। उस वक्त केंद्र सरकार कोविड-19 के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के लिए कहीं ज्यादा तैयार थी। हम कोविड-19 से लड़ने के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी नहीं कर पाए। आक्रामक टेस्टिंग, क्वारेंटाइन सुविधाएं जैसी तकनीकी और ढांचागत व्यवस्था भी नहीं कर पाए। इस कारण कोविड-19 से संक्रमित लोगों की पहचान और उनसे संपर्क करने में देरी हुई। इन परिस्थितियों में केवल एक ही चारा बचा था कि देश में लोगों के मूल अधिकारों को मुल्तवी कर कर्फ्यू जैसी स्थिति कर दी जाए।

प्रधानमंत्री ने जब 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, उस वक्त उन्होंने कहा कि अगर हम इस बीमारी को नहीं रोक पाए तो भारत दशकों पीछे चला जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को अचानक रोक देने से मौजूदा संकट कहीं अधिक बड़ा हो गया है। लॉकडाउन के कारण सभी तरह के बिजनेस की प्रोडक्शन लाइन ठहर गई। ट्रक और ट्रेन का परिचालन रुकने से आपूर्ति प्रणाली भी ठप पड़ गई है। इन परिस्थितियों में कारोबारी इसी उधेड़-बुन में फंस गए कि खत्म हो चुकी मांग से हो रहे नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। वे आगे की आशंकाओं को देखते हुए अपने कर्मचारियों को निकालने पर मजबूर हो रहे हैं।

कड़वा सच यह है कि हमें इससे उबरने में 3-4 साल लग जाएंगे। इस बुरी स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ रेट 2020-21 में 3-4 फीसदी के निगेटिव स्तर पर पहुंचने की आशंका है। अर्थव्यवस्था का ऐसा बुरा हाल कोविड-19 संकट के पहले और बाद में उत्पन्न स्थिति की वजह से हुआ है। लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन आठ अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है, जो 30 दिन के लॉकडाउन के आधार पर ही जीडीपी (2019 के स्तर पर) का करीब आठ फीसदी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।

खाद्य सुरक्षा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। रबी का मौसम हमारे कुल खाद्यान्न उत्पादन का 50 फीसदी पैदावार देता है। फसलें इस समय कटाई के लिए खेतों में तैयार खड़ी हैं। अगर हम खाद्य संकट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आपूर्ति शृंखला को तुरंत शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तुरंत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करनी चाहिए। ऐसा करने से शहरी इलाके में आपूर्ति तेजी से बढ़ेगी, इसका फायदा यह मिलेगा की महंगाई पर नियंत्रण किया जा सकेगा। वरना वह बहुत जल्द 20 फीसदी के स्तर तक जा सकती है।

अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन आठ अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। 30 दिनों में यह जीडीपी के आठ फीसदी के बराबर पहुंच गया है, जो भयावह स्थिति है

खरीद से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों के पास पैसा पहुंचेगा।

मध्यम वर्ग भी इस समय नौकरी की असुरक्षा के संकट से जूझ रहा है। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए, जिससे अगले छह महीने तक किसी भी व्यक्ति की नौकरी न जाए। पिछले छह साल में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अनगिनत बार उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 13 लाख करोड़ रुपये कमाए हैं। जब अर्थव्यवस्था इतने गहरे संकट में फंस गई है, सरकार को बीमा कंपनियों, म्युचुअल फंड, जमा नहीं लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को राहत पैकेज देकर मजबूत करना चाहिए, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को आसानी से कर्ज मिल सके। इस समय एक ऐसी नीति की बेहद जरूरत है जिससे छोटे और मझोले कारोबारी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। ऐसा केवल नकदी की उपलब्धता बढ़ाकर ही किया जा सकता है। सरकार को 2020-21 के लिए सभी तरह के कैपिटल गुड्स और वाणिज्यिक वाहनों पर एक बार 75 फीसदी डेप्रिशिएशन का लाभ देना चाहिए, जिसे 2021-22 में 50 फीसदी के स्तर तक देना चाहिए। वहीं, कृषि क्षेत्र से जुड़ी संपत्तियां, जो खेती से जुड़ी गतिविधियों के लिए किराए पर दी जाती हैं, उन्हें भी 100 फीसदी डेप्रिशिएशन का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा करने से किसानों को सस्ते दर पर कृषि उपकरण मिल पाएंगे।

सरकार को तुरंत भारतीय रिजर्व बैंक से ज्यादा से ज्यादा कर्ज लेना चाहिए। सारा पैसा नीतिगत स्तर पर गुणात्मक कदमों और रुपये की अधिक छपाई के जरिए जुटाया जा सकता है। ऐसा करने से निश्चित तौर पर राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, जो 2.2 फीसदी तक बढ़ सकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए यह समय की मांग है। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही दो बड़े झटकों का सामना कर रही थी, अब शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी इसे 30 साल पीछे धकेल सकती है।

सरकार को पिछले छह साल की दुविधाभरी नीतियों को त्यागकर, भरोसा बढ़ाने लायक कदम उठाने चाहिए। अर्थव्यवस्था को कम से कम छह लाख करोड़ रुपये पूंजी की जरूरत है। आरबीआइ को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए जो न केवल फाइनेंशियल सेक्टर का भरोसा वापस लौटा सकें बल्कि कंपनियों की बैलेंसशीट को भी सुरक्षा की गारंटी दे सकें। आरबीआइ को गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) के लिए दो तरह का वर्गीकरण करना चाहिए। एक, कोविड के पहले के एनपीए नियम और दूसरे, कोविड के बाद एनपीए नियम। इसके तहत मार्च 2020 के पहले लिए गए सभी कर्ज को कोविड के पहले के वर्ग में रखना चाहिए। उसके बाद के कर्ज को कोविड के बाद के वर्ग में रखना चाहिए। नए एनपीए नियमों में राहत देकर उसमें 18 महीने तक की छूट देनी चाहिए। वरना मार्च 2021 तक एनपीए दोगुना होने की आशंका है।

अर्थव्यवस्था को अगर राहत पैकेज और दूसरे नीतिगत सहयोग मिलते हैं तो वह जल्द ही पटरी पर आ जाएगी। इसके लिए आज दृढ़ इच्छाशक्ति और हकीकत के मद्देनजर नीतियां बनाने की जरूरत है।

(लेखक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

"इतने बड़े संकट में भी केंद्र सरकार अपना एजेंडा चला रही है"

लॉकडाउन से कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने में निश्चित रूप से मदद मिल रही है, लेकिन इस दौरान अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी उभरी हैं। प्रवासी मजदूर खाने और ठिकाने के लिए भटक रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो रहे हैं, लाखों नौकरियां जा रही हैं। सरकार के अब तक के कदम कितने सही रहे, अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सब मुद्दों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव **सीताराम येचुरी** *से बात की आउटलुक के* **एस.के. सिंह** *ने। मुख्य अंश :*

कोविड-19 के कारण बनी स्थिति से निपटने में सरकार के कदम को किस तरह देखते हैं?

जिस तरह की परिस्थिति पूरी दुनिया में है, उसे देखते हुए लॉकडाउन अनिवार्य था, लेकिन कई बातें गौर करने वाली हैं। भारत में पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया, पर लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च को। इस दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की तरफ से जारी निर्देशों को देश में कहीं लागू नहीं किया गया। इसके विपरीत बड़े-बड़े आयोजन हुए। 'नमस्ते ट्रंप' हुआ, संसद चलती रही, (मध्य प्रदेश में) शपथ ग्रहण हुआ, तबलीगी जमात का आयोजन हुआ। सरकार की तरफ से देर से कदम उठाए गए। हमें जो लाभ मिलना चाहिए था, वह दुर्भाग्यवश इस देरी के चलते नहीं मिला।

लॉकडाउन से कोविड-19 से निपटने में कितनी मदद मिली?

लॉकडाउन के लिए भी तैयारी करनी चाहिए थी। लॉकडाउन से पहले केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य से संपर्क नहीं किया। अचानक चार घंटे के नोटिस पर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। लोगों को खाने-पीने या रहने का इंतजाम करने का समय ही नहीं मिल सका। इसी वजह से प्रवासी मजदूरों को लेकर समस्या हुई। उसके बाद केंद्र ने राज्यों से कह दिया कि आप इन मजदूरों को ठहराइए, उनके खाने का इंतजाम कीजिए। आपने पहले कोई सूचना नहीं दी, अगर पहले बताते तो राज्य सरकारें कुछ इंतजाम कर सकती थीं। इन मजदूरों के इंतजाम के लिए केंद्र ने राज्यों को कोई मदद भी नहीं दी।

लॉकडाउन में एक तो लोगों को काम नहीं मिल रहा, दूसरे उन्हें खाने-पीने की दिक्कत आ रही है। इससे कैसे निपटें?

हमने सरकार से कहा कि कहीं ऐसा न हो कि कोविड-19 से ज्यादा लोग भुखमरी के शिकार हो जाएं। इससे बचने के लिए सबको 7,500 रुपये का कैश ट्रांसफर दिया जाए। सरकार के पास 7.5 करोड़ टन गेहूं और चावल का भंडार है, इसे राज्यों को दिया जाना चाहिए ताकि वे उसे लोगों तक पहुंचाएं।

लॉकडाउन से कैसे निकला जाए?

आप मानें या न मानें, जिन देशों ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है, वे समाजवादी देश हैं। चीन, वियतनाम और क्यूबा जैसे देश। इन देशों में लॉकडाउन के बाद टेस्टिंग करके यह पहचान की गई

कि किन इलाकों में संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है। उन इलाकों में लॉकडाउन जारी रखा गया और दूसरे इलाकों में इसे धीरे-धीरे हटाया गया। इस तरह वे इससे बाहर निकल रहे हैं।

केरल एक मॉडल बनकर उभरा है। वहां आपकी पार्टी की सरकार है। वहां राज्य सरकार ने कैसे काम किया?

भारत में पहला मामला 30 जनवरी को केरल में ही सामने आया था। राज्य सरकार ने दुनिया भर से मिल रहे संकेतों और डब्ल्यूएचओ के निर्देशों को देखते हुए 25 जनवरी से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। एक और बात, केरल ने कहा कि हम अपने यहां इस संकट को नियंत्रण में ले आए हैं और अब इससे बाहर निकलना चाहते हैं। तब केंद्र ने उसके खिलाफ सर्कुलर निकाल कर कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे निर्देशों का पालन कीजिए।

स्वास्थ्यकर्मियों की तरफ से भी काफी शिकायतें आईं...।

कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने की आशंका थी, इसलिए लॉकडाउन किया गया। जब आशंका थी, तो उससे लड़ने की तैयारी भी होनी चाहिए थी। डॉक्टर और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पहले से पर्सनल प्रोटक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) किट के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? यहां तक कि मास्क की भी कमी हो गई। हमारे यहां टेस्टिंग किट की कमी है। चीन से जो किट आए, उनमें डिफेक्ट बताया जा रहा है। सवाल है कि जब किट आयात हो रहे थे, तब उनकी गुणवत्ता कौन जांच रहा था।

पीएम रिलीफ फंड था तो पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया? सीएम रिलीफ फंड पर टैक्स छूट की सुविधा भी नहीं दी गई?

यह सवाल हमने भी किया कि जब पीएम रिलीफ फंड है तो यह नया फंड खोलने की क्या जरूरत पड़ी। सरकार कह रही है कि सीएसआर का पैसा पीएम केयर्स फंड में जा सकता है, लेकिन सीएम रिलीफ फंड में नहीं। हमने शुरू में ही इसका विरोध किया था। हमने कहा कि अध्यादेश के जरिए इस कानून में संशोधन कीजिए ताकि सीएसआर फंड का पैसा सीएम रिलीफ फंड में भी जाए। पीएम केयर्स फंड का पैसा भी राज्यों को नहीं दिया जा रहा है।

बात फैसले की हो या संसाधनों के वितरण की, संघीय ढांचे का कितना पालन हो रहा है?

मेरे विचार से तो संघीय ढांचे का पूरा उल्लंघन हो रहा है। जीएसटी के बाद राज्यों के पास राजस्व जुटाने के ज्यादा साधन नहीं रह गए हैं। जीएसटी की शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था और उसके हिसाब से जो बकाया बन रहा है, वह केंद्र सरकार राज्यों को नहीं दे रही है। स्वास्थ्य समवर्ती सूची में है। निर्णय केंद्र सरकार ले रही है लेकिन जिम्मेदारी राज्यों की बताई जा रही है। यह राज्य के अधिकार का एक तरह से उल्लंघन है। आज सबसे खराब स्थिति गुजरात और मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र में संख्या सबसे ज्यादा है लेकिन वहां सरकार का कहना है कि गुजरात से काफी लोग आए हैं। सवाल है कि केंद्र की टीम सिर्फ दूसरी पार्टियों वाले राज्यों में क्यों जा रही है? इतने संकट में भी केंद्र सरकार अपना एजेंडा चला रही है।

अल्पसंख्यकों को लेकर अलग माहौल बन रहा है। ऐसी खबरें हैं कि लोग उनसे सामान नहीं खरीद रहे। इसके लिए किसे दोषी मानते हैं?

इस संकट में भी इस्लामोफोबिया शुरू हो गया है। खाड़ी के देशों में इसके खिलाफ बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया हो रही है। गुजरात के अस्पताल में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग-अलग रखने की व्यवस्था कर दी गई। वहां कुछ अस्पतालों ने तो यहां तक कह दिया कि मुसलमानों का इलाज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ उनके खिलाफ सीएए और अन्य मामलों में केस दर्ज किए जा रहे हैं। जामिया के छात्रों को गिरफ्तार किया गया। यहां भी सरकार अपना एजेंडा चला रही है। यह न व्यक्ति के हित में है, न देश हित में।

सरकार आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रही है, लेकिन मांग बढ़ाने पर नहीं। सिर्फ आपूर्ति बढ़ाने से अमीर और अमीर होंगे, गरीब और गरीब हो जाएंगे

तबलीगी जमात को लेकर जो माहौल बना, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं?

जब कोविड-19 फैल रहा था तब तबलीगी जमात को इस तरह का आयोजन नहीं करना चाहिए था। आयोजकों का फैसला गैर-जिम्मेदाराना था। लेकिन आयोजन की अनुमति किसने दी? सरकार को पता था कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामले पाए गए, तब भी वहां के लोगों को वीजा दिया गया। उन्हें भारत में आने और देश में कहीं भी जाने की इजाजत दी गई। तबलीगी ने महाराष्ट्र में आयोजन के लिए आवेदन किया था लेकिन वहां की सरकार ने मना कर दिया। जब महाराष्ट्र सरकार ने अनुमति नहीं दी तो दिल्ली में कैसे अनुमति मिल गई। इस घटना का इस्तेमाल पूरी मुसलमान कौम को बदनाम करने में हो रहा है। इसका पूरी दुनिया में असर दिखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा भारतीय मूल का ही है।

हेल्थ इमरजेंसी जैसी इस स्थिति में विपक्ष की भूमिका पर क्या कहेंगे?

विपक्ष के लिए ज्यादा गुंजाइश ही नहीं है। सोशल मीडिया या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हम कुछ कह सकते हैं। हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। पहले हम पत्र भेजते थे तो सरकार अगर अनदेखी करना चाहती थी तो भी एक-दो लाइन का पावती पत्र भेज देती थी। लेकिन अब वह भी बंद हो गया है। अभी विपक्ष के पास सुझाव देने के अलावा ज्यादा कुछ करने को नहीं है।

कोविड के कारण कई सेक्टर बंद पड़े हैं। जीडीपी का आकार घटने की आशंका है। रिवाइवल के लिए क्या किया जाना चाहिए?

अभी तक सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे विपरीत दिशा में हैं। सरकार आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रही है, मांग बढ़ाने पर नहीं। लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं है। जब तक लोग खरीदेंगे नहीं, तब तक मांग नहीं निकलेगी। जब मांग ही नहीं होगी, तो उत्पादन कौन करेगा। मांग बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसे देने पड़ेंगे। सरकार अमीरों को टैक्स में छूट दे रही है, इस उम्मीद में कि उन पर टैक्स की देनदारी कम होगी तो वे ज्यादा निवेश करेंगे। वे उत्पादन बढ़ाएंगे तो उसे खरीदेगा कौन? सिर्फ आपूर्ति बढ़ाई जाएगी तो अमीर और अधिक अमीर होगा, गरीब और अधिक गरीब होगा। गरीबी बढ़ेगी तो मांग नहीं निकलेगी, और जब मांग नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। कोविड-19 से पहले सरकार ने उद्योग को 2.15 लाख करोड़ रुपये की रियायतें दीं। सरकार अगर यह रकम सड़कें-नहरें बनवाने जैसे कामों में खर्च करती तो लाखों लोगों को काम मिलता। सरकार एसेट क्रिएशन पर निवेश करे और इसके जरिए लोगों के हाथ में पैसा दे। यही रिवाइवल का एकमात्र रास्ता है।

हर सेक्टर में लाखों में नौकरियां जाने की आशंका है। वेतन में भी कटौती हो रही है...।

सीएमआइई के अनुसार, बेरोजगारी दर 23.8 फीसदी पर पहुंच गई है। मई-जून में इसके 30 फीसदी तक जाने का अनुमान है। जब बेरोजगारी दर 30 फीसदी होगी तो मांग कैसे बढ़ेगी। कोविड के बहाने हर जगह छंटनी और वेतन में कटौती हो रही है। कंपनियों को इतने दिनों से मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब एक महीने उन्हें नुकसान हुआ, तो वे छंटनी और वेतन में कटौती करने लगी हैं। कोविड-19 नहीं आता तो उन्हें यह मौका नहीं मिलता।

गरीब जाना, वह बेसहारा

लॉकडाउन में हुए अध्ययन से पता चला है कि इन दिनों में करीब 270 मजदूर जान गंवा चुके हैं

निखिल डे, शंकर सिंह

लॉकडाउन लागू हुए एक महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इस दौरान यह तो स्पष्ट हो गया है कि गरीब की जिंदगी दूभर हो गई है। उनके जीवनयापन का आधार खोखला हो गया है। ऐसे में ये लोग कोरोना से मरेंगे या बचेंगे, यह तो वक्त ही बताएगा लेकिन फिलहाल वह बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। वे न केवल बेरोजगार हो गए बल्कि उनके पास जो थोड़ी-बहुत बचत थी, वह भी खत्म हो गई है। उनके पास खाने-पीने की वस्तुएं खत्म हो चुकी हैं, उनके बच्चों की शिक्षा रुक गई, कभी-कभार मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा भी छिन गई। वे अपनी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

अमीरों का एक भ्रम है कि देश के सारे गरीब सरकार पर निर्भर हैं। शायद लॉकडाउन ने इस भ्रम को थोड़ा तोड़ा होगा। लॉकडाउन होते ही अचानक लाखों मजदूर अपने कारखानों और बस्तियों से निकलकर अपने गांव की तरफ चल पड़े। साधन संपन्न वर्ग पूछने लगा कि ये कहां से निकल आए? हकीकत तो यह है कि ये ही तो देश में काम करने और उत्पादन करने वाले लोग हैं। आज तक उन्हें कोई न तो पहचान पाया और न ही समझ पाया। ये लोग कभी सरकार पर निर्भर नहीं रहे। वे अपने गांव से निकले थे कोई छोटा-मोटा रोजगार ढूंढ़ने। नौकरी नहीं रोजगार, जहां वे 8,000-10,000 रुपये महीने कमाकर अपनी जिंदगी चलाने का प्रयास करते थे। जो लोग अपने परिवारों को गांव में छोड़कर आते हैं, वे युवा आमतौर पर एक साथ रहते हैं। एक छोटे से कमरे में 10-12 मजदूर एक साथ रहते हैं। फैक्टरियों के अंदर सैकड़ों की संख्या में लोग काम करते हैं। उनकी जिंदगी चारदीवारी के अंदर सिकुड़ी हुई रहती है। ऐसी जगहों पर शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) रखना असंभव है और उसकी बात भी करना क्रूर मजाक है। लॉकडाउन होते ही उनको समझ में आ गया कि उनका रोजगार समाप्त हो रहा है, यदि कोरोना हो गया तो यहां भी नहीं बचेंगे और नहीं हुआ तो भी उन्हें कोई राहत देने वाला नहीं है। इसलिए वे बिना सरकार से कुछ मांगे, भटकते हुए सैकड़ों मील दूर अपने गांव पैदल ही निकल पड़े।

21 दिन खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार राष्ट्र को संबोधित किया और लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। मजदूरों को फिर से हिदायत दी कि वे जहां हैं, वहीं रहें। लेकिन साधन संपन्न वर्ग के लिए दूसरे नियम हैं। तीर्थ यात्रियों, विद्यार्थियों और अमीर वर्ग के अन्य लोगों को घर पहुंचाने की व्यवस्था लगातार होती रही। लेकिन मजदूर वर्ग को कहा गया कि वे उन्हीं शिविरों में रहें या वापस उन्हीं जगहों पर लौटकर जाएं, जहां काम करते थे। मजदूरों को पता था कि वहां सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज ही संभव नहीं है, तो उनके मन में एक सीधा सवाल कौंधता था कि यह तकलीफ और त्याग, जिसकी प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अपील करते रहे हैं, किनके फायदे के लिए है?

लॉकडाउन होने पर विदेशों से आने वाले प्रवासी भारतीयों को वापस लाने के लिए हवाई जहाज और चार्टर्ड विमान लगाए गए। उनके लिए एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग और उनको सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। लेकिन मजदूरों को केवल चार घंटे का नोटिस दिया गया कि देश बंद होने वाला है। इससे लोग सड़कों पर आ गए और किसी भी तरह से घर पहुंचने का मन बनाया। गृह मंत्रालय ने एक आदेश दिया कि इन्हें जहां है, वहीं रोको और कैंपों में डाल दो। यहां तक कि हरियाणा सरकार ने आदेश दिया कि स्टेडियमों को अस्थायी जेल जैसा बनाओ और किसी भी सूरत में मजदूरों को बंद रखने की व्यवस्था करो। उच्चतम न्यायालय में सरकार ने आश्वसन दिया कि इन सभी मजदूरों को कम से कम 14 दिन तक वहीं बंद रखा जाएगा। जिन लोगों ने इज्जत के साथ अपनी रोटी कमाई थी और अब अपने घर जाना चाहते थे, उन्हें कैदी बना दिया गया और आगे के दिनों में खाने के लिए कटोरा लिए लाइनों में खड़ा कर दिया गया।

भारत ने एक विदेशी मॉडल ले लिया और भारत के मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग ने एक बार भी नहीं सोचा कि वे अपने बड़े-बड़े घरों में हैं, जहां एक-एक कमरे में एक-एक व्यक्ति रहता है। इसके उलट जब इन मजदूरों ने खिड़कियों से बाहर झांककर देखा, तो उन्हें कहा गया कि आपको समझ में नहीं आता कि यदि यह दूरी नहीं रखेंगे तो हम सबमें वायरस फैल जाएगा।

प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया और गरीबों को मदद करने का उपदेश दिया। लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की। 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज हकीकत में करीब 60,000 करोड़ रुपये का ही था। बाकी तो पहले से ही लोगों को मिलने वाले अधिकारों को सरकार ने इस समय दिलाने की व्यवस्था की। किसानों को 2,000 रुपये की मदद तो पहले ही पीएम किसान के तहत मिल रही थी। मनरेगा में मजदूरी हर साल महंगाई के साथ बढ़ती ही है, इसलिए इसे राहत पैकेज का हिस्सा कहना बिलकुल गलत है। मनरेगा का काम भी लॉकडाउन के साथ एकदम रुक गया। इसके तहत काम जो आपदा के समय एक वैकल्पिक रोजगार के रूप में उपलब्ध रहना चाहिए, वह काम बंद था तो मनरेगा से कौन सी राहत? सरकार ने आदेश देकर

सरकार द्वारा घोषित 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज, हकीकत में केवल 60 हजार करोड़ रुपये का ही है। बाकी तो पहले से मिलने वाले अधिकार ही दिए गए हैं

फैक्टरी और कंपनी मालिकों को अपने मजदूरों को लॉकडाउन के समय पूरी मजदूरी देने की हिदायत दी। लेकिन सरकार ने खुद अपने रोजगार गारंटी, मजदूरों के चलते काम में मस्टर रोल बंद करके कमाई का यह जरिया भी छीन लिया। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान है। लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया।

लॉकडाउन के दो-तीन दिन के बाद ही भुखमरी की कहानियां आने लगीं। हजारों-लाखों की संख्या में फंसे मजदूरों की दास्तान सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों और सचेत नागरिकों के समूह 'स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क' ने अपने अध्ययन के माध्यम से पेश की। 10,000 मजदूरों से सवाल पूछने पर जो जवाब मिले, वे चौंकाने वाले और रुलाने वाले भी हैं। इन मजदूरों में से 89 फीसदी को मालिकों ने लॉकडाउन के समय कोई पैसा नहीं दिया। 44 फीसदी मजदूरों के पास कोई पैसा और राशन बचा नहीं था। 78 फीसदी मजदूरों के पास जेब में 300 रुपये भी नहीं थे और 96 फीसदी लोगों को सरकार से कोई राशन नहीं मिला था। ये बातें सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए दायर की गई जनहित याचिका में रखी गईं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार की रिपोर्ट को ही मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवासी मजदूरों की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और सरकार को ही शाबाशी दी।

बदहाल व्यवस्था : दिल्ली के सराय काले खां के शेल्टर होम में प्रवासी श्रमिक

लॉकडाउन को आगे बढ़ाते समय 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने देश के सामने सात सूत्रीय फॉर्मूला रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि लोग कैसे कोरोना वायरस के प्रकोप से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों का ध्यान रखें, जबकि केंद्र सरकार ही बुजुर्गों को मात्र 200 रुपये महीना पेंशन देती है और वह भी बीपीएल परिवार वाले बुजुर्गों को। बाकी दो तिहाई बुजुर्ग इस समय कहां से खाएंगे और कैसे जिएंगे? बुढ़ापे में वह कमा नहीं सकते हैं और किसी काम पर जा नहीं सकते हैं। उनको 200 रुपये की पेंशन भी नसीब नहीं है और न ही नसीब होंगे वे 1,000 रुपये जो सरकार बुजुर्गों को देगी।

अन्य छह सूत्रों में प्रधानमंत्री मालिकों को उपदेश देते हैं कि वे मजदूरों को मजदूरी दें, लेकिन मनरेगा के मजदूरों को भूल जाते हैं। प्रधानमंत्री अमीरों को कहते हैं कि गरीबों का ध्यान रखें लेकिन बार-बार अनुरोध करने पर भी देश के गोदामों में सड़ रहे अनाज को अभी भी मजदूरों को भूख से बचाने के लिए बांटने को तैयार नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने सबको अपने स्मार्टफोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करके कोरोना से बचने का सुझाव दिया। कितने गरीबों के पास स्मार्टफोन हैं?

शायद मजदूर वर्ग अब शासकों को पहचानने लगा है। ऐसे में, कोरोना से लड़ाई न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों पर चलकर लड़नी चाहिए

कनिका शर्मा नामक शोधकर्ता ने बताया कि लॉकडाउन में अभी तक कम से कम 270 मौतें हुई हैं। लॉकडाउन की वजह से करोड़ों परिवार गरीबी की तरफ धकेले जा रहे हैं और करोड़ों परिवारों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सरकार को ही नेतृत्व करके सबको रास्ता खोजने की हिम्मत और साहस दिलाना पड़ेगा। आगे के रास्ते के लिए चार मुख्य उपाय हैं जो हमारे देश की कार्य क्षमता में है। भूखे पेट के साथ न कोई इंसान और न ही कोई समाज किसी बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। देश के गोदामों में रखे अनाज को सर्वव्यापी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें बिना कोई विशेष पहचान मांगे हर इंसान को अनाज उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, भयंकर बेरोजगारी का सामना करने के लिए एक सर्वव्यापी आपदा रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिसमें हर व्यक्ति को न्यूनतम मजदूरी पर काम की गारंटी मिले ताकि उसे अपना परिवार बचाने का विश्वास हो। रोजगार गारंटी के काम गांव और शहर में साल भर चलाने होंगे जिसमें 100 दिन की सीमा न हो और ऐसे काम कराए जा सकें जिनसे कोरोना संकट का सामना किया जा सकता है। तीसरा बिंदु सबको बराबर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है। इसका सामना एक व्यापक सार्वजानिक और समान जन स्वास्थ्य ढांचे से ही होगा, जहां हमें निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों को भी सार्वजानिक क्षेत्र में अधिग्रहीत कर लेना चाहिए।

आखिर में, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन है। घर में बैठकर कुछ ही लोग काम कर सकते हैं और कुछ ही काम हो सकते हैं। हर मोहल्ले, पंचायत और इलाकों में भी लोगों को बंधुत्व के आधार पर अर्थव्यवस्था, समाज और देश चलाने का रचनात्मक तरीका ढूंढ निकालना होगा। यह ऐसा समय है जब सरकार को दिखाना पड़ेगा कि वह गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए है, या साधन संपन्न ताकतवर लोगों के लिए ही काम करेगी। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस जाति, धर्म और पैसे को नहीं पहचानता, मजदूर वर्ग को हमारे शासकीय वर्ग ने नहीं पहचाना। लेकिन शायद अब मजदूर वर्ग शासन को पहचानने लगा है। कोरोना से लड़ने की भी एक राजनीति है। यह न्याय, समानता, आजादी और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो तो शायद हम मिलकर इस महामारी का सामना कर पाएंगे।

(दोनों लेखक सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर किसान शक्ति संगठन के संस्थापक सदस्य हैं)

हालात सुधरना दूर की कौड़ी

जीडीपी में 40 फीसदी योगदान करने और 23 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कंस्ट्रक्शन, रिटेल, टेक्सटाइल, होटल सेक्टर ज्यादा प्रभावित

एस.के. सिंह

विजय जिंदल की फरीदाबाद में एसपीएल इंडस्ट्रीज नाम से गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह पूरी तरह बंद है। उनके निर्यात के कई ऑर्डर रद्द हो गए हैं, जो माल भेजा था उसका भुगतान नहीं मिला है। वह कहते हैं, "हमारा 30 से 35 फीसदी खर्च कर्मचारियों पर होता है। इसमें सरकार को मदद करनी पड़ेगी। सरकार इंडस्ट्री को ब्याज मुक्त वर्किंग कैपिटल मुहैया करवाए और उस पर एक साल का मोरेटोरियम हो। मदद नहीं मिली

चक्का बंद : 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला टेक्सटाइल सेक्टर पूरी तरह ठप

तो गारमेंट एक्सपोर्ट में लगी 60 से 70 फीसदी इकाइयां बंद हो जाएंगी। सरकार को कम से कम छह महीने तक मदद करनी पड़ेगी, तब तक शायद विदेशी बाजार भी पटरी पर आ जाए।"

विजय जिंदल या गारमेंट इंडस्ट्री अकेली नहीं, कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर के स्वरूप को बदल दिया है। भारत की जीडीपी में 40 फीसदी से ज्यादा योगदान करने और 23 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले कंस्ट्रक्शन, रिटेल, टेक्सटाइल, पर्यटन और होटल एवं रेस्तरां इंडस्ट्री जैसे सेक्टर पर इस संकट का असर गहरा है। आने वाले दिनों में इन सेक्टर में आमूल-चूल बदलाव दिख सकते हैं। संभव है कि कुछ इकाइयां हमेशा के लिए बंद हो जाएं तो कहीं बिजनेस की शर्तें पूरी तरह बदल जाएं। क्रिसिल के अनुसार भारत में एक चौथाई ठेका मजदूर हैं। कंस्ट्रक्शन, खनन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में सबसे पहले इन्हीं की छंटनी होगी। इस संकट का जल्दी कोई समाधान भी नहीं दिख रहा। ग्लोबल एडवाइजरी फर्म विलिस टावर्स वाटसन के एक सर्वे में 57 फीसदी कंपनियों ने कहा कि अगले छह महीने के

दौरान उनका बिजनेस काफी ज्यादा प्रभावित होगा। 46 फीसदी कंपनियों को महामारी का असर एक साल और 19 फीसदी दो साल तक रहने का अंदेशा है। दूसरी ओर, रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से करीब 1,500 रिटेलर्स के सर्वे में पता चला कि लॉकडाउन तीन महीने तक खिंचा तो 25 फीसदी रिटेलर्स की दुकानें बंद हो जाएंगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अर्थव्यवस्था का रिवाइवल कैसे और कब होगा, यह कई जाने-अनजाने कारकों पर निर्भर करता है। मसलन, कोविड-19 की दवा कब बनती है, देश-दुनिया में लॉकडाउन पूरी तरह कब खत्म होता है और कोविड से कितनी मौतें होती हैं। ज्यादातर बड़े देशों ने उद्योग जगत के लिए राहत पैकेज की कई चरणों की घोषणा कर दी है, जबकि भारत में अभी इसका इंतजार है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार मांग बढ़ाने के उपाय करे। ऐसा न हो कि सरकार तब इलाज लेकर आए जब आदमी की मौत हो चुकी हो। दूसरे देशों ने जीडीपी के पांच से बीस फीसदी तक का पैकेज दिया है। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी सवाल घाटे का नहीं, अर्थव्यवस्था बचाने का है।

कैसे सुधरे हालात

आम राय यह है कि सरकार अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में मांग बढ़ाने के उपाय करे। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट डॉ. डी.के. अग्रवाल ने *आउटलुक* से कहा, "अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में हम जितनी देर करेंगे रिवाइवल की लागत उतनी ज्यादा होगी। सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव बनाया था। इसमें निजी क्षेत्र का निवेश 30 फीसदी मान लें तो सरकार को 14 लाख करोड़ रुपये अभी खर्च करने चाहिए। सरकार मनरेगा पर खर्च करे, किसान सम्मान निधि का पैसा एडवांस में दे।"

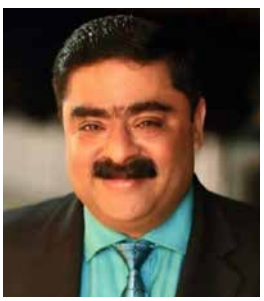

आने वाले दिनों में बिजनेस की शर्तें भी बदलेंगी, लोग यह नहीं समझे तो बिजनेस कभी खड़ा नहीं हो सकेगा

अनुराग कटरियार
प्रेसिडेंट, एनआरएआई

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री (सीआइटीआइ) उपाध्यक्ष और वर्धमान यार्न्स एंड थ्रेड्स लिमिटेड के एमडी डीएल शर्मा कहते हैं, "सरकार ने कुछ कदम उठाए जरूर हैं लेकिन इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है।" अग्रवाल कहते हैं, "सरकार को खासकर एमएसएमई के लिए जल्दी और बड़ा पैकेज लाना चाहिए। हमारा आकलन है कि एमएसएमई को बंदी से बचाने के लिए कम से कम चार फीसदी जीडीपी ग्रोथ जरूरी है। इतनी ग्रोथ रेट के लिए 16 लाख करोड़ रुपये का पैकेज चाहिए जो हमारी जीडीपी के सात फीसदी के बराबर होगा। इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि अभी महामारी के चलते मांग बहुत कम है।"

शर्मा कहते हैं कि निर्यात के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। अभी विदेशी खरीदार भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि हम माल सप्लाई कर पाएंगे या नहीं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद है। कोई खरीदार एडवांस देने को तैयार नहीं। पहले टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर ब्याज में पांच फीसदी तक छूट मिल जाती थी। अगर वही फिर मिलने लगे तो काफी राहत मिल जाएगी। गारमेंट एक्सपोर्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (जीईएमए) के प्रेसिडेंट विजय जिंदल का मानना है कि रिवाइवल एकदम से नहीं होगा। इंडस्ट्री अभी आईसीयू में है, सरकार को कम से कम छह महीने तक मदद करनी पड़ेगी।

इस संकट का सबसे ज्यादा असर एमएसएमई पर दिख रहा है। अग्रवाल कहते हैं कि इन्हें कर्ज पर ब्याज में पांच फीसदी छूट मिलनी चाहिए। आज वे इस स्थिति में नहीं कि ज्यादा ब्याज चुका कर धंधा चला सकें। इनकी सबसे बड़ी समस्या फंड की है। सरकार को उनके 50 से 75 फीसदी कर्ज पर गारंटी देनी पड़ेगी, 25-30 फीसदी की गारंटी से कुछ नहीं होगा। कर्ज पर कम से कम एक साल का मोरेटोरियम भी होना चाहिए, उनके लिए तीन महीने का मोरेटोरियम कुछ भी नहीं है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का भी सुझाव है कि सरकार छोटे कारोबारियों के नए कर्ज की गारंटी दे। शर्मा तो एमएसएमई के लिए कर्ज पर ब्याज फिलहाल माफ करने की बात भी कहते हैं। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एसीसीआइ) के प्रेसिडेंट अशोक भालोटिया के मुताबिक जिन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा है, उनकी स्थिति ज्यादा खराब है। लोग अपनी यूनिट तक बेचने को तैयार हैं लेकिन माहौल ऐसा है कि कोई खरीदार नहीं मिल रहा। अगर यही स्थिति रही तो किसानों की तरह उद्यमी भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे।

सरकार ने उद्योग से सभी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए कहा है। लेकिन अग्रवाल के अनुसार ज्यादातर इकाइयां इस स्थिति में नहीं हैं। सरकार को वेतन में 75 फीसदी मदद देनी चाहिए। भालोटिया कहते हैं कि अप्रैल में एक दिन भी फैक्ट्री नहीं चली तो वेतन कहां से दें। ईएसआई फंड में 75 से 80 हजार करोड़ रुपये हैं, सरकार को इस फंड का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे, श्रम पर संसदीय समिति ने हाल ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कर्मचारियों को वेतन देने के लिए इंडस्ट्री पर दबाव

जीएसटी रिफंड में तेजी और ब्याज में सब्सिडी की दरकार

एससी रल्हन
इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्टर और फियो के पूर्व अध्यक्ष

हमारा एक्सपोर्ट कारोबार मार्च में 35 फीसदी और अप्रैल में शून्य रह गया है। एमएसएमई निर्यातकों का कारोबार पटरी पर लाने के लिए विदेश व्यापार नीति की अवधि 31 मार्च 2020 के बाद एक वर्ष और बढ़ाई जाए। पहली तिमाही में बैंक कर्ज ब्याज मुक्त किया जाए, इसके बाद जुलाई 2020 से मार्च 2025 तक ब्याज पर सब्सिडी मिले। आयात शुल्क पर जुर्माना और ब्याज न लगे। वास्तविक खपत पर ही बिजली बिल जारी हों और न्यूनतम देय शुल्क माफ हो। छोटे निर्यातकों को सरकार तुरंत आइजीएसटी रिफंड करे। श्रमिकों को मार्च का वेतन दिया है पर अप्रैल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। लॉकडाउन में बगैर उत्पादन के श्रमिकों को पूरा वेतन देने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईएसआई फंड में उद्यमियों के अंशदान की भारी राशि पड़ी है, मेरे विचार से सरकार को इस फंड से श्रमिकों को पूरा वेतन देना चाहिए।

ईएसआइ फंड से श्रमिकों को दिया जाए वेतन

कमल ओसवाल
वाइस चैयरमैन, नाहर ग्रुप ऑफ कंपनीज

मुझे लगता है, लॉकडाउन के बाद भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स सेक्टर को बाजार में मांग के लिए कम से कम छह महीने तक इंतजार करना होगा। कुछ दिनों तक उपभोक्ताओं की प्राथमिकता जरूरी वस्तुएं ही रहेंगी, गारमेंट्स का नंबर बाद में आता है। नियम है कि बीमारी की हालत में श्रमिकों को काम से छुट्टी की अवधि में ईएसआइ फंड से वेतन जारी होता है। इसी तर्ज पर आपातकाल में औद्योगिक उत्पादन ठप होने की सूरत में श्रमिकों को पूरा वेतन भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार फंड बनाए। उद्यमियों पर बिजली का न्यूनतम शुल्क, बैंकों का ब्याज, किराया और अन्य तय खर्च उठाने का भार रहता है ऐसे में श्रमिकों को अप्रैल का वेतन ईएसआई फंड से जारी किया जाना चाहिए।

न निर्माण, न बिक्री : पांच करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी-रोटी रियल एस्टेट सेक्टर के भरोसे थी

नहीं डाला जा सकता।

फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (फिस्मे) के प्रेसिडेंट अनिमेष सक्सेना के अनुसार एमएसएमई के लिए स्थितियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि उनमें ऑटोमेशन कम है और उनमें प्रवासी मजदूर काफी होते हैं। अभी लोगों को यही साफ नहीं है कि लॉकडाउन कब खुलेगा, खुलेगा तो कहीं फिर दोबारा तो नहीं लग जाएगा। राजनीतिक लीडरशिप को पहले यह डर दूर करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि हम लॉकडाउन खोलने की तरफ बढ़ रहे हैं, तभी मजदूर काम पर लौटने की सोचेंगे।

उद्योग के सामने नकदी की बड़ी समस्या है। नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के प्रेसिडेंट अनुराग कटरियार ने बताया, "बिजनेस जब भी दोबारा शुरू होगा, हर कंपनी कंगाल हो चुकी होगी। उसके पास कैश नहीं होगा। हमारे सामने बहुत से नए खर्चे होंगे। सबसे पहले स्टॉक के लिए पैसा चाहिए क्योंकि रेस्तरां इंडस्ट्री में स्टॉक नहीं रख सकते, वह नष्ट हो जाता है। साफ-सफाई के नए नियम बनेंगे, उनके मुताबिक खुद को तैयार करना पड़ेगा। रेस्तरां इतने दिनों से बंद है तो उसे दोबारा शुरू करने से पहले थोड़ा रंग-रोगन भी करना पड़ेगा। इन सबके लिए नए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। आज के माहौल में प्राइवेट इक्विटी तो मिलेगी नहीं, बैंक से पैसे लेने पर अभी कर्ज लौटाना मुश्किल होगा। एक उपाय यह हो सकता है कि आरबीआइ सॉफ्ट लोन देने की अनुमति बैंकों को दे। इस कर्ज पर ब्याज दर कम और छह महीने का मोरेटोरियम हो।" कटरियार के अनुसार रेस्तरां, कर्मचारी, प्रॉपर्टी ओनर, फूड एग्रीगेटर, सरकार सबको नई शर्तों के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर लोग यह बात नहीं समझेंगे तो बिजनेस कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। कर्मचारियों को मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी मालिक अगर उम्मीद करता है कि उसे पहले जितना किराया मिलेगा, तो यह मुश्किल है। जब तक समस्या है तब तक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम हो सकता है। कुछ चीजें सरकार भी ठीक कर सकती है। रेस्तरां बिजनेस में जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अगर सरकार क्रेडिट दे तो काफी राहत मिलेगी।

रियल्टी डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई के चेयरमैन जक्षय शाह मानते हैं कि अभी वित्तीय के साथ दूसरे उपायों की भी जरूरत है। जैसे लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हो, जो प्रोजेक्ट तैयार हैं या तैयार होने के करीब हैं उनमें एफडीआइ की अनुमति मिले, केंद्र सरकार राज्यों को कुछ महीने तक स्टांप ड्यूटी आधी करने का निर्देश दे और अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपये की जाए। सरकार रियल एस्टेट को केंद्र में रखकर उपायों की घोषणा करे तो उसका असर अर्थव्यवस्था की दूसरे सेक्टर पर भी दिखेगा, क्योंकि करीब 250 एंसिलरी इंडस्ट्री इससे जुड़ी होती हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म सीबीआरई के भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, मध्य-पूर्व और अफ्रीका के चेयरमैन और सीईओ अंशुमान मैगजीन के अनुसार स्थिति को देखते हुए कंपनियां बिजनेस प्लान पर नए सिरे से विचार कर रही हैं। रियल एस्टेट कंपनियां अगले 12 महीने को ध्यान में रखकर रणनीति बनाएं तो सेक्टर जल्दी रिवाइव हो सकेगा। घर खरीदारों को प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म एनारॉक की सलाह है कि अगर वे मोल-भाव करें तो खासा डिस्काउंट मिल सकता है। दिल्ली-एनसीआर और मुंबई समेत देश के सात बड़े शहरों में 66,000 करोड़ रुपये के 78,000 फ्लैट बनकर तैयार हैं। डेवलपर्स पर इन्हें बेचने का दबाव रहेगा।

इन्वेस्टमेंट एलाउंस से बढ़ेगा मैन्युफैक्चरिंग में निवेश

पूरन डावर
चेयरमैन, डावर फुटवियर इंडस्ट्रीज

लेदर फुटवियर और अन्य उत्पादों के निर्यातक गर्मियों के सीजन के ऑर्डर पूरे कर रहे थे, लेकिन अनायास लॉकडाउन होने से अनेक ऑर्डर रद्द हुए हैं। जो माल भेजे गए, वे भी खरीदारों को मिल नहीं पाए। मेरा मानना है कि इस साल 30 फीसदी निर्यात भारी डिस्काउंट पर भी नहीं हो पाएगा। निर्यातकों के सामने लिक्विडिटी सबसे बड़ी समस्या है। मेरा मानना है कि निर्यातकों को पांच साल तक के लिए मौजूदा सीसी लिमिट में 50 फीसदी बढ़ोतरी की जाए। लॉकडाउन के बाद अवसरों का फायदा उठाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिबॉर रेट पर कर्ज और हेजिंग की सुविधा मिले। इससे उद्योगों की फंड जुटाने की लागत कम होगी। इन्वेस्टमेंट एलाउंस से मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। आयकर की दर घटाने के बजाय इसकी दस फीसदी राशि से करदाताओं को पेंशन, स्वास्थ्य और जीवन बीमा सुरक्षा दी जानी चाहिए।

वापसी की चुनौतियां

फिस्मे के सक्सेना कहते हैं, जैसे ही बसें-ट्रेनें चलना शुरू होंगी, मजदूर पहले अपने घर जाना चाहेंगे। वे कब आएंगे यह किसी को नहीं मालूम। कामकाज दोबारा शुरू करने में यह बहुत बड़ी चुनौती है। टेक्सटाइल, अपैरल और हैंडीक्राफ्ट निर्यात सेक्टर के लिए मुश्किलें ज्यादा हैं। ये सेक्टर श्रम आधारित ज्यादा हैं, इनमें प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी है। लोगों के निर्यात ऑर्डर भी काफी रद्द हुए हैं। घरेलू बाजार में भी कपड़ों की बिक्री का एक सीजन होता है। मौजूदा सीजन की आखिरी शिपमेंट अप्रैल-मई तक होती है। अगला सीजन अक्टूबर-नवंबर में शुरू होगा। यानी जब स्थिति सामान्य होगी, हम लीन सीजन में होंगे। अगले सीजन तक कंपनियों के लिए बिना ज्यादा काम के टिके रहना मुश्किल होगा। सीआइटीआइ के शर्मा ने कहा, "टेक्सटाइल बहुत ही कम मार्जिन और ज्यादा मजदूरों वाली इंडस्ट्री है। मार्च में मिलों ने सैलरी दे दी, लेकिन अप्रैल का पैसा कहां से देंगे। लोगों की आमदनी घट रही है तो इसका असर खपत पर दिखेगा, चाहे वह खाने-पीने की चीजें हो या पहनने की।"

एनआरएआइ के कटरियार के अनुसार कुछ बिजनेस तो हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बिजनेस जब भी खुले, पहले की तुलना में 30-40 फीसदी से ज्यादा कारोबार नहीं होगा। चीन में बिजनेस दोबारा शुरू हुए हैं लेकिन वहां होटल और रेस्तरां में ऑक्युपेंसी रेट 30 से 35 फीसदी है, वह भी तब जब चीन में हर व्यक्ति महीने में औसतन 28 बार बाहर खाना खाता है। भारत में तो यह औसत सिर्फ 4.1 है। जब बिजनेस के खर्चे वही रहेंगे, लेकिन कारोबार आधा रह जाएगा तो बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा। जीईएमए के जिंदल ने बताया, "कोरोना की बीमारी पहले विदेश में शुरू हुई। वहां खरीदारों ने ऑर्डर रद्द या होल्ड कर दिए। हमने जो माल भेजा, उसका भुगतान रुक गया। इस सेक्टर में 95 फीसदी उद्यमी एमएसएमई हैं। उनके पास नगद नहीं के बराबर है।" छंटनी और वेतन कटौती के माहौल में लोग घर खरीदने का फैसला तो टाल ही सकते हैं, बुकिंग करवा चुके ग्राहक भी भुगतान में डिफॉल्ट कर सकते हैं। इसलिए क्रेडाइ के जक्षय शाह को लगता है कि नई लॉन्चिंग में देरी होगी। पुराने प्रोजेक्ट में खरीदारों के डिफॉल्ट करने से डेवलपर्स को नकदी की काफी समस्या आएगी। हालांकि उन्हें कुछ उम्मीद भी है। वह कहते हैं, "कोविड-19 संकट ने लोगों को एहसास कराया है कि घर सबसे सुरक्षित जगह है, इसलिए मेरा मानना है कि लोग आने वाले दिनों में घर खरीदने में ज्यादा निवेश करेंगे।"

कोई खरीदार एडवांस नहीं दे रहा, ब्याज में पांच फीसदी छूट फिर मिलने लगे तो काफी राहत होगी
डी.एल. शर्मा
उपाध्यक्ष, सीआइटीआइ

कुछ दिक्कतें सरकारी आदेशों से भी पैदा हुई हैं। 15 अप्रैल से लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हुआ तो गृह मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए, लेकिन राज्यों ने उन्हें अपने तरीके से लागू किया। सक्सेना के मुताबिक हरियाणा सरकार ने 19 अप्रैल की शाम को कहा कि यूनिट खोलने के लिए उद्योगों को एक पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा। 19 तारीख की रात आप पोर्टल पर आवेदन के लिए कह रहे हैं, फिर तो 20 से काम शुरू हो ही नहीं सकता। एक और उदाहरण पीएफ और ईएसआई का है। कंपनियों को 15 तारीख तक पीएफ का पैसा जमा करना पड़ता है। ईएसआई ने बहुत पहले कह दिया कि कंपनियां मई तक पैसे जमा कर सकती हैं, लेकिन पीएफ विभाग ने तारीख बढ़ाने की सूचना 15 तारीख की सुबह दी। सक्सेना कहते हैं, क्या यह जानबूझकर किया गया ताकि जितने लोग पैसे जमा कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए। कामकाज बंद होने के बावजूद कई राज्य बिजली का फिक्स्ड चार्ज वसूल रहे हैं। सक्सेना के अनुसार जब उत्पादन नहीं हो रहा, बिजली खर्च नहीं हो रही है तो फिक्स्ड चार्ज का बोझ क्यों लाद रहे हैं।

अब तक के उपाय

सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की इजाजत नहीं दी। कर्मचारियों की संख्या भी कम रखने की हिदायत दी गई। भालोटिया के अनुसार हमें सिर्फ 25 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने को कहा गया। यूनिट चलाने के लिए ज्यादा कर्मचारी चाहिए और नियम बना दिया जाए कि इतने लोग ही काम कर सकेंगे, तो यूनिट चलाना मुमकिन नहीं होगा। अग्रवाल ने कहा, "सरकार को किसी भी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस प्रोवाइडर तक, पूरे ईकोसिस्टम को शुरू करने की अनुमति देनी पड़ेगी। अगर कोई उद्यमी सामान बनाता है और उसकी बिक्री नहीं होती, तो वह क्यों बनाएगा।" फिस्मे के सक्सेना भी कहते हैं, किसी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन एक जिले में नहीं है। कोई भी इकाई पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा मात्र होती है। भले ही कम क्षमता के साथ काम हो, सरकार को किसी इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू चेन शुरू करने की अनुमति देनी चाहिए थी।

साथ में चंडीगढ़ से **हरीश मानव,**
दिल्ली से **के.के. कुलश्रेष्ठ**

मजदूर हकों की रक्षा करें

सरकारी खजाने पर कामगारों, छोटे और मझोले उद्योगों का वाजिब हक, इसे बड़े उद्योगों को नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें गरीबों के प्रति सामाजिक दायित्व निभाने को बाध्य किया जाना चाहिए

सजी नारायण सीके

जब लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार हो रहा है, तो सवाल उठता है कि कोविड-19 के बाद के दौर में कामगारों और मजदूरों का भविष्य क्या होगा। लॉकडाउन के चलते संगठित और असंगठित, दोनों क्षेत्रों के कामगार कई तरह के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। अक्सर जब जीडीपी नुकसान की चर्चा होती है तब बड़ी इंडस्ट्री की बात ही प्रधानता से होती है, उसमें शामिल मजदूरों के बारे में कोई जिक्र नहीं होता।

कुछ ऐसी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें आ रही हैं जिनमें भारत की स्थितियों का गलत आकलन है। इसका एक उदाहरण अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की रिपोर्ट है। इसमें है कि कोरोनावायरस संकट के चलते अनौपचारिक क्षेत्र के करीब 40 करोड़ कामगार गरीबी में और गहरे धंस जाएंगे। यूरोपीय मानकों के हिसाब से भारत का आकलन करना गलत होगा। उन देशों का विशाल संगठित क्षेत्र मौजूदा संकट को नहीं झेल सकेगा, भले ही वे स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे हों। भारत में अगर हम पिछले संकटों का इतिहास देखें तो पाएंगे कि असंगठित क्षेत्र में झटके झेलने की अकूत क्षमता है जबकि संगठित क्षेत्र नाकाम साबित हो जाते हैं। दरअसल, असंगठित क्षेत्र के दिहाड़ी मजदूर और अपने काम-धंधे के जरिए रोज कमाने-खाने वाले लोग ही असली राष्ट्रनिर्माता हैं, न कि बड़े कारपोरेट या इंडस्ट्री वाले। सरकार के प्रयासों को लोगों ने जिस तरह तहेदिल और अनुशासित तरीके से समर्थन दिया है, उससे भारत दूसरे देशों की तुलना में कोविड-19 पर बेहतर नियंत्रण कर सकता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने की भारत की अंतर्निहित क्षमता का अध्ययन होना चाहिए। समाधान ढूंढ़ने की इसकी क्षमता 1998 के एशियाई आर्थिक संकट, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट, नोटबंदी के समय और ऐसे दूसरे मौकों पर भी दिखी है। वैसे तो अनौपचारिक क्षेत्र की स्थिति खराब ही रहती है, लेकिन संकट के दिनों में उसका कलेवर बदल जाता है। दूसरे देशों से आ रही रिपोर्ट के अनुसार, अनेक देशों में प्रवासियों की स्थिति बेहद खराब है। भारतीय दूतावास भारतीय मूल के लोगों की मदद करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों के दूतावासों के लिए अपने प्रभावित लोगों की मदद करना मुश्किल हो रहा है।

भारत में कोविड-19 संकट और लॉकडाउन से कई समस्याएं सामने आई हैं। इनमें वेतन न मिलना, देर से मिलना या वेतन में कटौती शामिल है। अनेक लोगों की नौकरियां चली गई हैं। नियोक्ताओं ने अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया और कई कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या घटा दी। ठेकेदारों ने मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया है और वे राहत शिविरों के भीड़-भाड़ में रहने को मजबूर हैं। इसलिए हमें भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाधान तलाशने की जरूरत है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्य बनाने और कामगारों की आजीविका की रक्षा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने 27 और 29 मार्च को जारी केंद्र सरकार के उस सर्कुलर का स्वागत किया है जिसमें नियोक्ताओं को कर्मचारियों का पूरा वेतन देने, किरायदारों से किराया न लेने और औद्योगिक इकाइयों से कर्मचारियों की छंटनी न करने को कहा गया है, खासकर ठेका मजदूरों की। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ नियोक्ता इसके खिलाफ कोर्ट चले गए। नियोक्ता संगठनों को सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने के बजाय इसे सामाजिक दायित्व के रूप में लेना चाहिए था।

भारतीय उद्योगों को घरेलू श्रम कानूनों और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों को सम्मान देने की संस्कृति अपनानी चाहिए। श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर कारगर त्रिपक्षीय बातचीत पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हमारे कामगारों को अच्छी नौकरी, पर्याप्त और सस्ती सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और बीमा की गारंटी मिलनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुत से छोटे और मझोले उद्यम इन दिनों काफी मुश्किल में हैं। लॉकडाउन के चलते वे अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को वेतन देकर केंद्र सरकार की तरफ से वेतन सब्सिडी के रूप में मिलने वाले राहत पैकेज से इसे वापस ले सकते हैं। इससे नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच संबंध भी बेहतर होंगे। दिहाड़ी मजदूरों, ठेका मजदूरों, कम आमदनी वाले काम-धंधे में लगे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए रकम दी जा सकती है। सीधे वेतन बिल से जोड़े बिना इंडस्ट्री को रकम देना ठीक नहीं। अच्छी बात है कि उद्योग संगठनों ने वेतन में मदद के रूप में डीबीटी और बैंक कर्ज का समर्थन किया है और छंटनी का विरोध। सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन की अवधि को सवैतनिक अवकाश के रूप में देखा जाना चाहिए, छंटनी के अवसर के रूप में नहीं।

इन दिनों प्रवासी मजदूरों से जुड़ी अभूतपूर्व समस्याएं देखने को मिल रही हैं। वे अपने घर वापस जा रहे हैं। इसका ठोस हल पेश किया जाना चाहिए। श्रमिकों की कमी दूर करने और उन्हें उनके कार्य स्थलों पर वापस लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास, मुफ्त ट्रेन टिकट, नकद इन्सेंटिव जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आधार और जनधन डीबीटी खातों के जरिए राष्ट्रीय कृषि श्रमिक रजिस्टर भी तैयार किया जा सकता है। कैंपों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को राशन, रहने का ठिकाना, स्वास्थ सुविधा, कमाई में मदद और परिवार के साथ संपर्क बनाने के लिए मुफ्त इंटरनेट की जरूरत है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की पहचान करने और उनका डाटाबेस तैयार करने का काम शुरू किया है। हमें तत्काल

नियोक्ता कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश नहीं दे रहे, ठेकेदारों ने मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया और वे राहत शिविरों में रहने को मजबूर

प्रवासी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। हमें उन लोगों को श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए जिन्होंने इस जानलेवा वायरस से लड़ने में जान गंवा दी। भारतीय मजूदर संघ (बीएमएस) स्वास्थ्य एवं अस्पतालकर्मियों, पुलिसकर्मियों और प्रशासन से जुड़े कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ा है। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे अस्पतालकर्मियों के लिए उनको दोगुना वेतन देने की घोषणा की है।

संकट के दिनों में अनेक नियोक्ता श्रम कानूनों की अनदेखी करते हैं और श्रमिक विरोधी कदम उठाते हैं। वे चाहते हैं कि पहले से परेशान कर्मचारियों को कम वेतन दें, कर्मचारियों की संख्या घटाएं, श्रम कानूनों पर अमल टालें, 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का सिद्धांत लागू करें, काम के घंटे बढ़ाएं, उम्रदराज लोगों को छोड़कर युवाओं को काम पर रखें, ईएसआइ फंड से वेतन दिया जाए, ईपीएफ से लोन दिया जाए। एक राज्य में तो नियोक्ता संगठन ने कर्मचारी संगठनों पर अंकुश लगाने की मांग तक कर डाली। उद्योगों को ऐसे प्रस्ताव रखने से बचना चाहिए। यह उद्योग जगत के लिए मानवीय चेहरा दिखाने का समय है। हमेशा की तरह उद्योग जगत ने तत्काल नौ से 11 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग की है। सरकार उद्योग से संबंधित मुद्दों के जल्दी समाधान की कोशिश भी कर रही है, लेकिन यहां हमें अलग तरह से सोचने की जरूरत है। कंपनियों को स्टिमुलस और बेलआउट पैकेज देकर सप्लाई बढ़ाने के बजाय हमें मांग बढ़ाने के कदम उठाने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग, खासकर ऑटोमोबाइल और गारमेंट जैसे सेक्टर में मांग गिरने की वजह से समस्या आई। इसलिए सरकार का प्रयास क्रय-क्षमता बढ़ाने और बाजार का सेंटीमेंट सुधारने पर होना चाहिए। डीबीटी, मनरेगा, वेतन सब्सिडी, कमाई में मदद, समाज कल्याण के उपाय, इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास की अन्य गतिविधियों से श्रमिकों की क्रय-क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन कदमों से श्रमिकों, आम लोगों और समाज के संकटग्रस्त वर्ग के हाथ में नकदी मिलेगी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने ग्रामीण भारत को फोकस करते हुए 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की जो घोषणा की है यह सही कदम है। सरकार की तरफ से उन्हीं उद्योगों को मदद दी जानी चाहिए, जो गंभीर वित्तीय संकट में हों।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रतिस्पर्धा की क्षमता की कमी के साथ सुस्ती का सामना कर रहा है। इसलिए ऑनलाइन स्किल ट्रेनिंग देने, आंत्रप्रेन्योरशिप कोर्स शुरू करने, मदद पहुंचाने वाले केंद्र खोलने, शिक्षित युवाओं को कम खर्च में कारोबारी सलाह देने, रिसर्च एवं डेवलपमेंट में निवेश पर इन्सेंटिव देने, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच समन्वय बनाने जैसे कदम उठाने की जरूरत है। मानव संसाधन, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण में तत्काल बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना चाहिए। एमएसएमई के लिए भी काउंसलिंग सेंटर या हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए। एमएसएमई भारतीय उद्योग की रीढ़ है। इनमें भी छोटे और मझोले उद्यम सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं। अगर राहत पैकेज दिया जाता है तो इसे उद्योग में रोजगार की संख्या को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिए। कोविड संकट से एमएसएमई, रिटेलर, कम आमदनी वाले स्वरोजगार कर्मी और सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। असली मैन्युफैक्चरर सप्लाई चेन वाले वे उद्यमी हैं जो बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं। सरकार ने ई-कॉमर्स पर अंकुश लगाने का साहसिक कदम उठाया है, जिससे रिटेलर को बल मिलेगा और करोड़ों रोजगार की रक्षा होगी। एक राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति लाने की जरूरत है। चाइनीज कंपनियों द्वारा संकटग्रस्त भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए एफडीआइ नीति में बदलाव सही दिशा में उठाया गया कदम है।

न रोजी, न ठिकाना : लॉकडाउन में कामधंधा नहीं बचा तो मजदूर गांव लौटने को मजबूर हुए

समाधान के तौर पर हमारे कुछ सुझाव हैं- चीन से आयात पर निर्भरता कम करना, जीएसटी और आयकर में राहत देना, कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तरफ से वर्किंग कैपिटल मुहैया कराना, कर्ज पर ब्याज में राहत देना, किसी कर्ज को एनपीए घोषित करने की समय सीमा बढ़ाना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ज्यादा कर्ज देना, एकल खिड़की क्लियरेंस और जल्दी मंजूरी की व्यवस्था करना, सरकार द्वारा सिर्फ एमएसएमई से खरीद करना, बिजली पर सब्सिडी, गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन करना। भारत में 85 फीसदी औद्योगिक गतिविधियां एमएसएमई करती हैं। इसके बावजूद उद्योग से जुड़ी सभी चर्चाएं बड़ी इंडस्ट्री के इर्द-गिर्द होती हैं। सरकार के रेवेन्यू पर छोटे और मझोले उद्योगों का वाजिब हक है, इसे बड़े उद्योगों को नहीं दिया जाना चाहिए।

सरकार क्रय-क्षमता बढ़ाने और सेंटीमेंट सुधारने का प्रयास करे। डीबीटी, मनरेगा, वेतन सब्सिडी और विकास की गतिविधियों से बढ़ेगी श्रमिकों की क्रय-क्षमता

(लेखक भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं)

खुश रहना मुश्किल नहीं

खुश रहने की क्षमता विकसित की जा सकती है, येल यूनिवर्सिटी में यह सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम बन गया

ओ.पी. सिंह

अमेरिका की प्रसिद्ध येल यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं, लॉरी सैंटोस। अपना विषय पढ़ाने के साथ-साथ 2018 से उन्होंने 'साइंस ऑफ वेल बीइंग' के नाम से एक पाठ्यक्रम शुरू किया। वे वहां के छात्रों में चिंता और अवसाद के बढ़ते स्तर से चिंतित थीं। उन्होंने व्यवहार-परिवर्तन और मनोविज्ञान का अध्ययन किया और ठाना कि इस पाठ्यक्रम के जरिए वे छात्रों को एक खुशहाल जीवन-शैली के लिए शिक्षित-प्रेरित करेंगी। उनका कहना है कि तरक्की के तमाम दावे और दिखावे के बीच अमेरिका में पिछले बीस साल में एंटी-डिप्रेसेंट दवाइयों की खपत चार-सौ गुना बढ़ी है। मनोविज्ञान में अब उपयोगी जानकरियां हैं, जिसके अभ्यास से खुश रहने की क्षमता विकसित की जा सकती है। येल यूनिवर्सिटी के तीन-सौ साल के इतिहास में मात्र दो साल में ये सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रम बन गया है।

खुशी के ऊपर अमेरिका की ही कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संयो ने भी व्यापक शोध किया है। खुश आदमी से उनका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे आनंद, उत्साह और गर्व की ज्यादा और उदासी, चिंता और गुस्से की अनुभूति कम होती है। ऐसे लोग समझते हैं कि चिल्ल-पों तो मची रहेगी, जलने-भुनने के बजाय उत्साहपूर्वक कुछ करना ज्यादा ठीक है। एक स्वाभाविक प्रश्न है कि आखिर खुश रहना इतना मुश्किल क्यों है? मन बुझ तो घड़ी भर में जाता है, फिर हर्षित होने के लिए बड़े-बड़े कारण क्यों मांगता है? इसके लिए हमें अपने आप या किसी और को कोसने की जरूरत नहीं है। शोध में पाया गया है कि खुश रहने के मूल में पचास प्रतिशत हमारा जीन, दस प्रतिशत जीवन की परिस्थितियां और चालीस प्रतिशत हमारा व्यवहार-विचार है। ऊपर से दिमाग की बनावट कुछ ऐसी है कि हम तीर-तुक्का लड़ाते रहते हैं, अन्य से अपनी तुलना कर दुबले होते रहते हैं और हर चीज से जल्दी, बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। इन कारणों से हम पैसा, प्रसिद्धि और पावर जैसी चीजों के लिए जान झोंक देते हैं। सोचते हैं कि इनमें से एक भी हाथ लग जाए तो बाकी तो वैसे ही खींच लेंगे। ऐसा न होना है और न होता है। फिर सिर धुनते हैं। इसके इलाज का दावा करने वाले नीम-हकीमों के शरणागत होते हैं। सालों लगाकर और लाखों गवांकर हाथ वही आता है, 'ढाक के तीन पात'। ऐसे में, ज्यादा अच्छा है कि खुशी के बारे में साक्ष्य-आधारित जानकरियां जुटाई जाएं और उसी के आधार पर खुश रहने की क्षमता का विकास किया जाए।

पॉजिटिव साइकोलॉजी का कहना है कि वांछित कदम उठाकर और उचित अभ्यास कर हम दिमाग की स्वाभाविक गड़बड़ियां, जैसे कि दूर की कौड़ी लाना, दूसरों की ताक-झांक में मगज खपाना और हर बात पर जल्दी ही उखड़ जाना ठीक कर सकते हैं। सही चुनने की बुद्धि सीख सकते हैं। दिमाग को अच्छी आदतें सिखा सकते हैं। जैसे कि दूसरों से तुलना से बचने के लिए एक तो अपने वर्तमान को गौर से देखें कि हालात क्या सचमुच में इतने बुरे हैं जितना आप समझ रहे हैं। फिर, अगर तुलना ही करनी है तो अपने उन बीते दिनों से करें जब हालात और भी बुरे थे। बेमेल चीजों में अनावश्यक तुलना कर दुखी होने का क्या प्रयोजन? जल्दी ऊबने की आदत से बचने के लिए चीजों के बजाय अनुभव पर समय और पैसा लगाएं। चीजें पुरानी पड़ जाती हैं, अनुभव हमेशा अतुल्य और नूतन होता है। कोई चीज अच्छी लगे तो ठहर जाएं, टिक कर अनुभव करें। भागा-दौड़ी में न माया मिलेगी न राम। कोई चीज पर्याप्त न लगे तो कल्पना करें कि अगर जो हासिल है वो भी न होता तो क्या होता? और हर रोज ऐसे जिएं जैसे ये जिंदगी का आखिरी दिन हो। आगे का सोच-सोचकर लिस्ट लंबी करने का कोई लाभ नहीं है।

सही चुनाव बहुत जरूरी है। काम को ही लें। पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सेलिग्मन का कहना है अगर इसमें आपके कम से कम चार 'सिग्नेचर स्ट्रेंक्थ' का भी उपयोग होता है, तो ये बोझ न होकर आपकी पसंद बन जाएगा। दूसरे, देने का अभ्यास करें। लेने वाले का भला हो न हो, आपकी चांदी पक्की है। शोध में पता चला है कि देने से शरीर में 'हैप्पी हार्मोन' डोपमिन, सेरटोनिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसीन का संचार होता है। परिणामस्वरूप, आनंद की अनुभूति होती है। इसे 'हेल्पर्ज हाई' कहते हैं। तीसरे, लोगों से मेलजोल, बातचीत रखें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध में पाया गया है कि सामाजिक संपर्क से रक्त-धमनियों में ऑक्सीटोसिन, जिसे 'लव हार्मोन' भी कहते हैं, रिलीज होता है जो सेरटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है। आपकी बल्ले-बल्ले हो जाती है। चौथे, अगर समय और पैसे के बीच चुनना हो तो समय को महत्व दें। कई शोध का निष्कर्ष है कि साधारण जरूरत पूरी होने के बाद और अधिक पैसे से आनंद में आनुपातिक वृद्धि नहीं होती है। पाचवें, दिमाग को काबू में रखने के लिए मेडिटेशन करें। ब्रेन-स्कैन में ये देखा गया है कि काम खत्म होते ही दिमाग का अलग-अलग भाग अनियंत्रित होकर आपस में अपने-आप चुगली-चाटी में जुट जाता है। इसे 'माइंड'स डिफॉल्ट नेटवर्क' कहते हैं। अगर इसे बेलगाम छोड़ दिया जाए, तो बेड़ा गर्क कर देता है। और आखिर में, स्वस्थ आदतें रखें, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद लें।

व्यक्ति को हर रोज ऐसे जीना चाहिए, जैसे यही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो। आगे की सोच-सोच कर लिस्ट लंबी करने का कोई लाभ नहीं

कुल मिलाकर साक्ष्यों की मानें तो खुशी का कोई शॉर्टकट नहीं है। न ही ये किसी दुकान में बिकता है। ये तो अधिकांश आपके जीन और जीवन की परिस्थितियों के अधीन है। हां, चालीस प्रतिशत जरूर ये आपकी कोशिशों और आदतों की मानता है। अब मर्जी आपकी है कि मृग-मरीचिका के पीछे दौड़ते रहें, खुशी के फर्जी डीलरों के हत्थे चढ़ते रहें या फिर साक्ष्य-आधारित जानकारी का उपयोग कर शरीर में 'हैप्पी हॉर्मोन' की फुलझड़ी चलाने की जुगत में लगें।

(लेखक हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं)

अक्षय कुमार

₹28 करोड़

मदद के लिए सितारों का हाथ

अगर कोरोना संकट अभूतपूर्व है तो बॉलीवुड की दरियादिली भी कल्पनातीत है

मुंबई से **गिरिधर झा**

कोरोना संकट के चलते बॉलीवुड के बड़े सितारों में अक्षय कुमार को अनुमानित तौर पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सबसे ज्यादा, करीब 700-800 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है। कोविड-19 के कारण इस साल बड़े बजट की उनकी तीन फिल्में (*सूर्यवंशी,*

सलमान खान

₹15 करोड़

लक्ष्मी बम और *पृथ्वीराज*) संकट में पड़ गई हैं। इतने भारी नुकसान के बावजूद वर्तमान संकटकाल में जरूरतमंदों की मदद करने में वे सबसे आगे हैं। हाल के समय में हर साल औसतन तीन-चार हिट फिल्में देने वाले 'खिलाड़ी' कुमार ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए 28 करोड़ रुपये दान दिए हैं। उन्होंने 25 करोड़ रुपये पीएम केयर्स फंड और तीन करोड़ रुपये बृहन्मुंबई कॉरपोरेशन (बीएमसी) को दान दिया। उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने जब उनकी तारीफ की, तब जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "यह ऐसा समय है, जब हमारे लोगों की जिंदगी बचाना सबसे महत्वपूर्ण है।" अभिनेत्री का करिअर छोड़कर लेखिका के तौर पर सक्रिय ट्विंकल ने लिखा था, "वे मुझे गर्व की अनुभूति करवाते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आप वास्तव में इतनी बड़ी रकम दान करना चाहते हैं? हमें इसके लिए पैसा जुटाने की भी आवश्यकता पड़ गई। इस पर उन्होंने सिर्फ यह कहा, जब मैंने करिअर शुरू किया, तब मेरे पास कुछ नहीं था। आज जब मैं अच्छी स्थिति में हूं तो उन लोगों की मदद करने से पीछे कैसे हट सकता हूं, जिनके पास आज कुछ भी नहीं है?" महामारी के इस दौर में अक्षय ने इंडस्ट्री की दूसरी हस्तियों के लिए पैमाना बहुत ऊंचा कर दिया है, जहां बेशुमार धन-दौलत पाने वाले फिल्म निर्माता

नकद दान देने के अलावा कई सितारे इस दौर में दूसरे तरीकों से भी लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं

और कलाकार भी ऐसे मौकों पर कंजूसी करने से बाज नहीं आते थे। पिछले वर्षों में अनगिनत भारतीय सितारों ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की ग्लोबल सूची में अपनी जगह बनाई है। लेकिन शायद ही उनमें से पहले किसी ने आपदा के समय ऐसी फुर्ती और दानवीरता दिखाई, जैसी इस बार सभी ने दिखाई। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नकद दान देने के अलावा अधिकांश हस्तियों ने अलग-अलग तरीके से सहायता दी है। किसी ने कोरोना वारियर्स के लिए सेफ्टी किट की व्यवस्था की, तो किसी ने गरीबों के लिए भोजन और राशन का इंतजाम किया।

इससे पहले फिल्म इंडस्ट्री बाढ़ या भुखमरी जैसी राष्ट्रीय आपदाओं के समय दूसरे तरीकों से योगदान करती थी। बड़े कलाकार और टेक्नीशियन रैलियां निकालते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे और म्यूजिक नाइट्स आयोजित करते थे, ताकि मदद के लिए फंड जुटाया जा सके। लेकिन इस बार स्थिति एकदम अलग है। फंड जुटाने के लिए कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि कलाकार घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसलिए इस बार अपनी जेब से सहायता देने का ही विकल्प है।

इस बार बॉलीवुड में मदद करने का दौर अपने घर से ही शुरू हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री में दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों की सहायता के लिए सलमान खान सबसे पहले आगे आए। 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के समय से ही मुंबई के पास पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में रह रहे *दबंग* स्टार फिल्म इंडस्ट्री के श्रमिकों के 32 संघों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इंप्लॉईज (एफडब्ल्यूआइसीई) के जरिए कम से

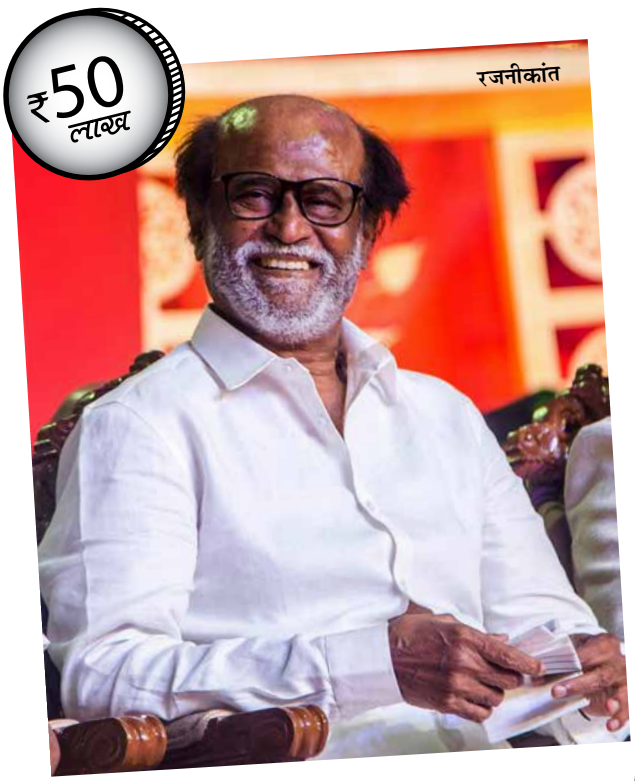

कम 15 करोड़ रुपये की मदद दे रहे हैं। फेडरेशन के अध्यक्ष बी. एन. तिवारी ने बताया, "सलमान ने लॉकडाउन के कारण गंभीर आर्थिक मुश्किल में फंसे दिहाड़ी श्रमिकों के बैंक खातों का विवरण मांगा था। वे तभी से हर खाते में 3,000 रुपये जमा कर रहे हैं। दूसरी किस्त जल्दी ही जमा हो जाएगी।

करीब पांच लाख श्रमिक अपने श्रम संगठनों के माध्यम से फेडरेशन से जुड़े हैं। इनमें से बड़ी संख्या में श्रमिक मुश्किल से रोजी-रोटी चला पा रहे थे। लॉकडाउन के कारण काफी श्रमिकों के पास खाने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि उनके पास कोई बचत नहीं है या फिर बहुत कम पैसे बचे हैं। तिवारी ने *आउटलुक* को बताया कि यह हमारे लिए बिलकुल नई चुनौती है। हम इसके लिए तैयार नहीं थे। सलमान खान और उनकी तरह इंडस्ट्री के दूसरे लोगों से जो मदद मिल रही है, इसके अतिरिक्त हम अपने रिजर्व फंड से श्रमिकों की मदद कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मजदूर भूखा न सोए। तिवारी कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि सलमान खान की पहल के बाद फेडरेशन दूसरे कलाकारों जैसे अजय देवगन, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी और निर्माता बोनी कपूर के भी संपर्क में आया। देवगन और शेट्टी ने 51-51 लाख रुपये दान दिया है। उन्होंने कहा, "हमें अपने सदस्यों से 1,000 रुपये जैसी छोटी राशि भी दान में मिल रही है। हमारे लिए यह मदद बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्य स्थानों पर भी कई जाने-माने कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने वित्तीय सहायता दी है। टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ रुपये दान दिए, जबकि साजिद नाडियावाला ने पीएम केयर्स फंड के अलावा महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में भी दान दिया। उन्होंने अपने 400 कर्मचारियों को बोनस भी दिया ताकि वे भी उदारता से दान दे सकें।

दृश्यम फिल्म के निर्माता मनीष मुंदड़ा, जो इस समय नाइजीरिया में हैं, कई अस्पतालों को पीपीई और सेफ्टी किट की सप्लाई भेज रहे हैं। भारतीय टेलीविजन की जानी-मानी हस्ती एकता कपूर ने अपने प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स से जुड़े दिहाड़ी मजदूरों के लिए अपना एक साल का वेतन ढाई करोड़ रुपये दान किया है। उन्होंने ट्वीट किया, "कोरोना का असर व्यापक, अप्रत्याशित

बॉलीवुड सितारों ने खोली अपनी झोली

अक्षय कुमार
₹28 करोड़

भूषण कुमार
₹11 करोड़

प्रभास
₹4 करोड़

पवन कल्याण
₹2 करोड़

महेश बाबू
₹1.25 करोड़

चिरंजीवी
₹1 करोड़

नागार्जुन
₹1 करोड़

विकी कौशल
₹1 करोड़

कार्तिक आर्यन
₹1 करोड़

वरुण धवन
₹55 लाख

रजनीकांत
₹50 लाख

कपिल शर्मा
₹50 लाख

प्रियंका चोपड़ा

किंग खान: शाहरुख खान ने अपना चार मंजिला निजी दफ्तर बीएमसी के लिए खोल दिया है

और बहुआयामी है। हम सभी को वह करना है जिससे हमारे आसपास और हमारे देश के लोगों की दिक्कतें कम हों।" एकता ने आगे कहा, "बालाजी में काम करने वाले दैनिक मजदूरों और मौजूदा अनिश्चितता के हालात में शूटिंग न होने से आर्थिक परेशानी में आए दूसरे लोगों का ख्याल रखना हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।"

रितिक रोशन ने बीएमसी कर्मचारियों के लिए एन 95 और एफएफपी 3 मास्क का इंतजाम किया है। उन्होंने एनजीओ अक्षय पात्र के साथ मिलकर जरूरतमंदों के लिए 1.2 लाख फूड पैकेट बंटवाने में भी मदद की। जैकलीन फर्नांडीज ने मुंबई में 2,500 परिवारों को आवश्यक वस्तुएं सुलभ कराने के लिए

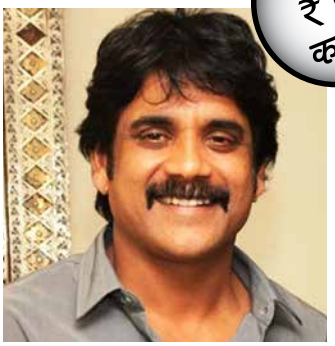

₹1 करोड़

दक्षिण के सितारे: चिरंजीवी (बाएं) और नागार्जुन भी मदद के लिए आगे आए

कदम उठाए। ये परिवार कोरोना संकट के कारण मुश्किल में पड़ गए हैं। वह कहती हैं, "संकट की इस घड़ी में इस तरह की छोटी कोशिश भी मायने रखती है।"

कोविड-19 से लड़ने के लिए शाहरुख खान ने भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने पीएम केयर्स फंड और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में अघोषित रकम दान की और अपने ऑफिस की चार मंजिला इमारत बीएमसी के लिए खोल दी ताकि आवश्यक चीजों से सुसज्जित इमारत को क्वारेंटाइन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा उनका कंपनी समूह जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, मीर फाउंडेशन और रेड चिलीज वीएफएक्स शामिल है, 50,000 पीपीई किट वितरित करने के अलावा मुंबई में 5,500 परिवारों की भोजन आवश्यकता पूरी कर रहा है। उनके समूह ने दिल्ली में 10,000 लोगों के लिए तीन लाख भोजन पैकेट का इंतजाम करने और 2,500 दैनिक मजदूरों को राशन सुलभ कराने की भी पहल की है। शाहरुख खान कहते हैं, "चुनौती की जटिलता को देखते हुए मैंने और मेरी टीम ने अपने तरीके से सहायता देने के बारे में सोचा। हमने कई तरह से मदद देने की पहल की है। उम्मीद है कि इससे थोड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा, "एक राष्ट्र और एक व्यक्ति के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हमें जो भी मिला है, वह सब हम दे दें। मैं अपने स्तर पर यथासंभव प्रयास कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आपमें से हर कोई ऐसा ही करेगा। एकजुट होकर ही हम इस कठिनाई और अकल्पनीय संकट के दौर से मुकाबला कर सकते हैं।"

हालांकि शाहरुख ने यह खुलासा करने से बचने का प्रयास किया कि उनकी टीम इस संकट से जूझने में मदद के लिए कितनी रकम खर्च कर रही है। अमिताभ बच्चन, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, सैफ अली खान, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, राजकुमार राव और अनुष्का शर्मा जैसे कई सितारें हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने अपने योगदान को गोपनीय ही रखा है। दक्षिण के सितारों ने भी दान देने में भरपूर उदारता दिखाई है। रजनीकांत उन अग्रणी लोगों में से हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए दान दिया। रजनीकांत ने 50 लाख रुपये दान दिया है। जबकि *बाहुबली* फिल्म से प्रसिद्धि पाने वाले तेलुगू स्टार प्रभास ने चार करोड़ रुपये दान दिए हैं। दान करने वाले अन्य कलाकारों में पवन कल्याण (दो करोड़), महेश बाबू (1.25 करोड़), अजित कुमार (1.30 करोड़), अल्लू अर्जुन (1.25 करोड़), चिरंजीवी (एक करोड़) और नागार्जुन (एक करोड़ रुपये) शामिल हैं। कोरोनावायरस से उत्पन्न संकट के काले बादल समूची फिल्म इंडस्ट्री पर भी मंडरा रहे हैं लेकिन इससे मुकाबला करने के लिए सितारों और फिल्म निर्माताओं की मदद के लिए बढ़े हाथ उम्मीद की किरण दिखाते हैं। तो क्या हम शाहरुख खान के अंदाज में कह सकते हैं, "पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।"

रितिक रोशन

विकी कौशल

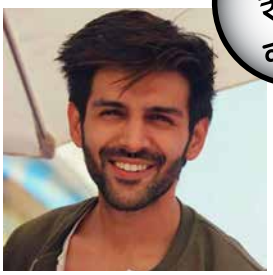

कार्तिक आर्यन

₹1 करोड़

कई बॉलीवुड सितारे ऐसे हैं जो अपने द्वारा की गई मदद को सार्वजनिक करना नहीं चाहते

आर्थिक नीतियों की हकीकत

एस.के. सिंह

सरकार आर्थिक नीतियां किसके लिए बनाती है? कहने को तो इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया जाता है, लेकिन क्या सचमुच इन नीतियों का लाभ हर वर्ग को मिलता है? जाने-माने अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की यह किताब इन्हीं सवालों के जवाब देती है। 2001 में सरकार के गोदामों में काफी अनाज इकट्ठा था, दूसरी तरफ लोग भुखमरी के शिकार थे। स्थिति आज भी नहीं बदली है। सरकार के पास बफर स्टॉक से ज्यादा अनाज है, और लोग आज भी भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। खाद्य सब्सिडी का मकसद गरीबों तक भोजन की पहुंच आसान बनाना है, लेकिन हुआ इसके उलट है। द्रेज लिखते हैं कि एफसीआइ का संचालन खाद्यान्न की कीमत कम करने के लिए नहीं, बल्कि ऊंचा बनाए रखने के लिए हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक परिवार के हिसाब से एक टन अनाज एफसीआइ के गोदामों में जमा है। बहुत से गरीब परिवार राशन दुकान की अपेक्षा बाजार से अनाज खरीदना बेहतर समझते हैं क्योंकि राशन दुकान में मिलने वाले अनाज की क्वालिटी खराब होती है। एफसीआइ की इस 'जमाखोरी' के कारण उन्हें ऊंची कीमत पर अनाज खरीदना पड़ता है।

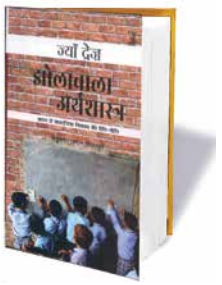

झोलावाला अर्थशास्त्र

ज्यां द्रेज
अनुवाद | चन्दन श्रीवास्तव
प्रकाशक | वाणी प्रकाशन
पृष्ठ: 376 | मूल्य: 375 रुपये

लेखक ने गरीबी रेखा की पहचान, मनरेगा में काम करने वाले और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि बीपीएल श्रेणी के लोगों को लक्षित करने वाला तरीका पूरी तरह छोड़ दिया जाना चाहिए। इसकी वजह व्यावहारिक है। शहरी इलाकों के लिए निर्धारित गरीबी रेखा का जो बजट तय किया गया है वह प्रति दिन प्रति व्यक्ति 32 रुपये है। सच्चाई यह है कि रोजाना 32 रुपये में जीना कहीं से भी मुमकिन नहीं। आज मिड डे मील की काफी सराहना की जाती है लेकिन इसे अमल में लाने में काफी मुश्किलें पेश आईं। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को भोजन देने के लिए 1995 में नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन (एनपीएनएसपीई) योजना बनी थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट को 2001 में यह निर्देश देना पड़ा कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर में पका हुआ भोजन दिया जाए। अब भी स्कीम के अमल में गड़बड़ियों की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। यही स्थिति स्वास्थ्य सेवाओं की है। जीडीपी की तुलना में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च के मामले में भारत दशकों से निचली पंक्ति के देशों में है। निजी क्षेत्र में नियमन का कोई कारगर ढांचा न होने से मरीज के शोषण की आशंका बनी रहती है। मरीज अक्सर शोषण के शिकार भी होते हैं।

द्रेज ने स्कूलों की बदहाली की बात भी कही है। आज भी अनेक गांवों में स्कूल के नाम पर कोई भवन नहीं है। यह भी देखा गया कि स्कूल की इमारत का इस्तेमाल भंडार घर, पुलिस कैंप, सार्वजनिक शौचालय आदि के लिए हो रहा है। इन सबसे अलग वह भारत भी है जहां रेल मंत्री यह कहते हैं कि बुलेट ट्रेन जल्दी से जल्दी चले, यह हर हिंदुस्तानी की चाहत है। क्या रेल मंत्री यह नहीं जानते कि रेलगाड़ियों का देर से चलना ही आज रेलवे की सबसे बड़ी समस्या है। रेल से सफर करने वालों में बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो आज भी बिना आरक्षण वाले डिब्बों में सफर करते हैं। उनके लिए बुलेट ट्रेन के क्या मायने हो सकते हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। किताब के अंत में नोटबंदी का जिक्र करते हुए यह सही कहा गया है कि यह गैरकानूनी आमदनी को रोकने में बिलकुल भी कामयाब नहीं हुई। दरअसल, कमजोर वर्ग कभी आर्थिक नीतियों के केंद्र में नहीं होता। उसके नाम पर घोषणाएं तो बहुत होती हैं लेकिन अंतत: इन घोषणाओं और योजनाओं का लाभ किसी और को मिलता है। यही तो है *झोलावाला अर्थशास्त्र!*

स्त्री जीवन की कविताएं

काव्य जगत में स्वरांगी साने का नाम अपेक्षाकृत नया है, लेकिन उनकी कविताएं मन को काफी उद्वेलित करती हैं। इस काव्य संग्रह की ज्यादातर रचनाएं नारी मन की व्यथा को व्यक्त करने वाली हैं। कभी प्रतीकों में, तो कभी खुल कर। वह लिखती हैं, दीदी को 'प्याज काटना' इसलिए पसंद था, क्योंकि इस बहाने वह अपने आंसू छिपा लेती थीं। बचपन से लड़कियों के हाथों पर इसलिए मेहंदी लगाई जाती है कि वह कभी अपने हाथों की लकीरें न देख सकें। तीन खंडों में रची इन कविताओं में नारी का सबसे बड़ा दर्द छलकता है- कोई घर उसका अपना नहीं होता (किरायेदार), बस मां के घर से ससुराल तक ही होती है उसकी दुनिया (सार), तीमारदारी करने के लिए ही बनी है वह। नारी होने का क्या मतलब है, इसे उन्होंने अहिल्या कविता में बताया है – 'या तो उसे पतिव्रता होना है या पत्थर।' एक अन्य कविता में वह लिखती हैं- 'हार मान लेने का रोग, उसे तभी लग गया था, जब उससे कहा गया था, तुम लड़की हो।' इन सबके बावजूद उसे जीना है। सिर्फ जीना नहीं, अपना दुख-दर्द भूल कर जीना है। लेकिन क्या वह सचमुच भूल पाती है? 'वह ठीक-ठीक जवाब नहीं दे पाती, लगता है सच कह दे' (हंसी)। महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित कहीं नहीं, न घर में न बाहर। इसी ओर इंगित करती हुई यह पंक्ति है- 'वह खुलकर जीना चाहती है, लेकिन खतरे को देखकर वह कछुए की तरह खोल में सिमट जाती है।' बहरहाल, नारी व्यथा को शब्द देने वाली रचनाकार को कविता से प्रेम है, इसीलिए तो कहती हैं कि 'कविता में जाना, मेरे लिए पीहर जाने जैसा है।'

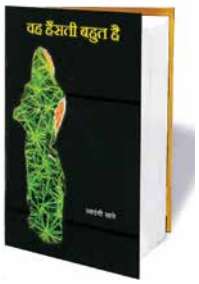

वह हंसती बहुत है

स्वरांगी साने
प्रकाशक | श्री सर्वोत्तम प्रकाशन
पृष्ठ: 144 | मूल्य: 100 रुपये

आउटलुक डेस्क

इस लुक दा जवाब नहीं

यदि अभी *83* फिल्म रिलीज हो गई होती तब भी हम वर्ल्डकप में भारत को विश्व विजेता बनाने वाले कपिल देव की बात कर रहे होते। देव ने सर के बाल साफ कर साथ दाढ़ी ही, बढ़ा ली है। देव ने इस लुक को विवियन रिचर्डस और धोनी से इंस्पायर्ड बताया है।

सेनेटाइजर वाली जज

अमेरिकन आइडल का नया रिमोट एपिसोड हाल ही में शुरू हुआ। एपिसोड जज कैटी पेरी और साथी जज लियोनेल रिची और ल्यूक ब्रायन अपने घर से ही प्रस्तुतियां देख रहे हैं। कैट सेनेटाइजर बॉटल के कवर की तरह ड्रेस पहन कर आईं। कैट का संदेश, हाथ साफ, सब सुरक्षित।

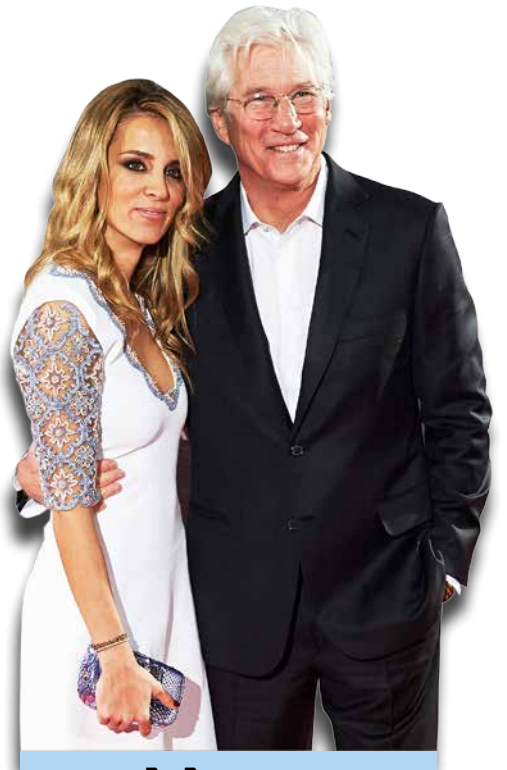

नए-नवेले पापा

'सत्तर में बत्तर' कहावत पुरानी हो गई। कम से कम रिचर्ड गेरे ने तो इसे साबित कर दिया है। उनकी 37 साल की पत्नी एलेजेन्द्रां सिल्वा ने हाल ही में उनके बेटे को जन्म दिया है। 14 महीने पहले पिछले साल फरवरी में उनके पहले बेटे एलेक्जेंडर का जन्म हुआ था।

बैठे-बैठे क्या करें

इन दिनों समय काटने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह के चैलेंज चल पड़े हैं। इन्हीं में से एक है पिलो चैलेंज। भारत में नेहा कक्कड़ के बाद तमन्ना भाटिया दूसरी हैं जो तकिए को सोने के अलावा किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर रही हैं।